।। संगच्छध्वम् संवदध्वम् ।।

समाचार पचीसा

राजनीति का जनपक्षकार

● वर्ष-5
● अंक-207
रायपुर, गुरुवार
16 अप्रैल 2026
● पृष्ठ-8
● मूल्य-3 रु.

पेज-8> शिक्षा के अधिकार को पारदर्शी...

समान नागरिक संहिता बनाने समिति का गठन

महिलाओं को जमीन रजिस्ट्री में छूट

साय कैबिनेट ने लिए महत्वपूर्ण निर्णय

रायपुर। मुख्यमंत्री विष्णु देव साय की अध्यक्षता में बुधवार को कैबिनेट की बैठक में दो महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए जिनमें नारी शक्ति और वीर जवानों से संबधित रहे। उप मुख्यमंत्री श्री अरुण साव ने बैठक के बाद पत्रकार-वार्ता को संबोधित किया। उन्होंने पत्रकार-वार्ता में कैबिनेट की बैठक में लिए गए निर्णयों की जानकारी दी। अरुण साव ने बताया, सरकार ने महिलाओ को सशक्त करते हुए घर और जमीन की मालकीन बनाने की दिशा में अहम फैसला लेते हुए अब यदि कोई भी संपत्ति महिलाओ के नाम पर पंजीकृत होती है तो उस पर 50 प्रतिशत की छूट मिलेगी। इसी के साथ शहीद होने वाले जवानों और सेवारत सैनिकों तथा भूतपूर्व सैनिकों की विधवाओं के लिए सरकार ने 25 लाख रुपये तक की अचल संपत्ति खरीदने पर स्टाम्प शुल्क में 25 प्रतिशत तक छूट देने का निर्णय लिया है। इसके अलावा बैठक में अन्य अनेक निर्णय लिए गए।

मंत्रिपरिषद द्वारा छत्तीसगढ़ में समान नागरिक संहिता लागू करने के संबंध में समान नागरिक संहिता का प्रारूप तैयार करने के लिए सेवानिवृत्त न्यायाधीश रंजना प्रकाश देसाई की अध्यक्षता में एक समिति का गठन करने का निर्णय लिया गया तथा समिति के सदस्यों के मनोनयन के लिए मुख्यमंत्री जी को अधिकृत किया गया।

छत्तीसगढ़ में वर्तमान में विवाह, तलाक, उत्तराधिकार, दत्तक ग्रहण, भरण-पोषण एवं पारिवारिक मामलों से संबंधित विवादों में विभिन्न धर्मों के अनुसार अलग-अलग पर्सनल लॉ लागू हैं। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 44 के तहत राज्य को सभी नागरिकों के लिए समान नागरिक संहिता लागू करने का निर्देश दिया गया है। अलग-अलग कानूनों के कारण वैधानिक प्रक्रिया में असमानता उत्पन्न होती है, जिससे न्याय प्रक्रिया जटिल होती है। ऐसे में कानून को सरल, एकरूप और न्यायसंगत बनाने के लिए समान नागरिक संहिता लागू करना आवश्यक माना जा रहा है, जिससे धार्मिक और लैंगिक समानता को भी बढ़ावा मिलेगा।

अरुण साव ने कहा कि इसी दिशा में छत्तीसगढ़ में एक उच्चस्तरीय समिति गठित करने का निर्णय लिया गया है, जो राज्य के नागरिकों, संगठनों एवं विशेषज्ञों से व्यापक सुझाव लेकर समान नागरिक संहिता का प्रारूप तैयार करेगी। यह समिति वेब पोर्टल के माध्यम से फीडबैक भी आमंत्रित कर सकती है। समिति की सिफारिशों के आधार पर तैयार प्रारूप को विधिसम्मत प्रक्रिया के तहत मंत्रिपरिषद से अनुमोदन के बाद विधानसभा में प्रस्तुत किया जाएगा, जिससे राज्य में एक समान और पारदर्शी नागरिक कानून व्यवस्था स्थापित हो सके। मंत्रिपरिषद ने महिलाओं के हित में महत्वपूर्ण निर्णय लिया है कि महिलाओं के नाम पर होने वाले भूमि रजिस्ट्रेशन पर लगने वाले शुल्क में 50 प्रतिशत की कमी की जाएगी। इसका उद्देश्य महिलाओं को संपत्ति अर्जन के लिए प्रोत्साहित करना और उन्हें आर्थिक रूप से सशक्त बनाना है। इस निर्णय से सरकार को लगभग 153 करोड़ रुपये राजस्व की कमी होगी, लेकिन महिला सशक्तीकरण के लिए इसे महत्वपूर्ण कदम माना गया है।

मंत्रिपरिषद की बैठक में राज्य के सेवारत सैनिकों, भूतपूर्व सैनिकों एवं उनकी विधवाओं के हित में एक महत्वपूर्ण निर्णय लिया गया, जिसके तहत उन्हें जीवनकाल में एक बार छत्तीसगढ़ राज्य के भीतर 25 लाख रूपए तक की संपत्ति (भूमि/भवन) क्रय करने पर देय स्टाम्प शुल्क में 25 प्रतिशत की छूट प्रदान किया जाएगा। देश सेवा में समर्पित सैनिकों का जीवन प्रायः स्थानांतरण और अस्थायित्व से भरा होता है, जिसके बाद वे स्थायी निवास के लिए संपत्ति क्रय करते हैं, ऐसे में यह निर्णय उन्हें आर्थिक राहत प्रदान करेगा।

मंत्रिपरिषद द्वारा छत्तीसगढ़ औद्योगिक भूमि एवं भवन प्रबंधन नियम, 2015 में संशोधन के प्रस्ताव का अनुमोदन किया गया। इस संशोधन से सेवा क्षेत्र को आबंटन हेतु स्पष्ट वैधानिक पात्रता मिलेगी। भूमि आवंटन प्रावधानों में न्यूनतम एवं अधिकतम सीमा का तार्किक सामंजस्य स्थापित होगा। लैंड बैंक भूखण्डों हेतु एप्रोच रोड का वैधानिक प्रावधान किया गया है। एनबीएफसी सहित वित्तीय संस्थाओं को सम्मिलित करने से उद्योगों के लिए ऋण उपलब्धता के विकल्प बढ़ेंगे। कंपनियों में शेयर धारिता परिवर्तन से संबंधित प्रावधानों में व्यावहारिक स्पष्टता आएगी और

व्यापार करने में सुगमता सुनिश्चित होगा। पीपीपी मॉडल के लिए स्पष्ट प्रावधान से निजी निवेश एवं औद्योगिक अवसंरचना विकास को प्रोत्साहन मिलेगा।

छत्तीसगढ़ गौण खनिज साधारण रेत (उत्खनन एवं व्यवसाय) नियम, 2025 में संशोधन का अनुमोदन किया गया। अब केन्द्र अथवा राज्य सरकार के सार्वजनिक उपक्रम जैसे छत्तीसगढ़ मिनरल डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन लिमिटेड को रेत खदानें आरक्षित की जा सकेगी। इससे पट्टेदार के एकाधिकार के फलस्वरूप उत्पन्न रेत की आपूर्ति-संकट में कमी आएगी तथा दुर्गम क्षेत्रों में रेत खदानों के सुगम संचालन सहित रेत की सुगम उपलब्धता सुनिश्चित हो सकेगी।

मंत्रिपरिषद् की बैठक में छत्तीसगढ़ गौण खनिज नियम, 2015 में व्यापक संशोधन के प्रस्ताव का अनुमोदन किया गया। इस संशोधन का उद्देश्य खनन क्षेत्र में पारदर्शिता, नियंत्रण और राजस्व वृद्धि सुनिश्चित करना है, अवैध खनन को रोकना तथा प्रक्रिया का सरलीकरण करना है।गौण खनिज की ऐसी खदाने जो अकारण बंद रहती है अथवा शिथिल रहती है, में कठोर प्रावधान लाया गया है। अब इन खदानों के अनिवार्य भाटक दर में 30 वर्षों के बाद वृद्धि की गई है। इन खदानों को व्यपगत (लैप्स) घोषित किए जाने संबंधी कठोर प्रावधानों को नियमों में शामिल किया गया है, जिसके फलस्वरूप ऐसी खदानों का संचालन अनिवार्य रूप से किये जाने की बाध्यता सुनिश्चित हो सकेगी। खनिजों के अवैध उत्खनन/परिवहन/भंडारण पर कठोर दंड का प्रावधान किया गया है। जिसमें न्यूनतम जुर्माना 25 हजार रूपए निर्धारित किया गया है, जो कि 5 लाख रूपए तक भी हो सकता है। अवैध परिवहन के मामलों में सुपुर्दगी दिए जाने हेतु जमानत राशि का भी निर्धारण किया गया है।

ओबीसी, दलितों की हिस्सा चोरी कर रहे पीएम मोदीः राहुल

नईदिल्ली। केंद्र सरकार द्वारा लोकसभा सीटों की संख्या बढ़ाकर 850 करने और 2026 से पहले की जनगणना के आधार पर परिसीमन की अनुमति देने के लिए संविधान संशोधन का प्रस्ताव रखे जाने के मद्देनजर, लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी ने बुधवार को कहा कि कांग्रेस सरकार को अन्य पिछड़ा वर्ग (ओबीसी), दलित और आदिवासी समुदायों के प्रतिनिधित्व का हिस्सा छीनने नहीं देगी और इसे एनडीए का राष्ट्र-विरोधी कदम बताया। एक्स पर एक पोस्ट में राहुल गांधी ने कहा कि उनकी कांग्रेस महिला आरक्षण का स्पष्ट रूप से समर्थन करती है, लेकिन सरकार को परिसीमन केवल 2026 की जनगणना के आधार

महिला आरक्षण बिल का समर्थन पर तरीके पर ऐतराज

नई दिल्ली। कांग्रेस सहित विपक्ष के कई प्रमुख दलों ने लोकसभा में महिला आरक्षण लागू करने से संबंधित संवैधानिक संशोधन विधेयक को पेश किए जाने से एक दिन पहले बुधवार को कहा कि वे महिलाओं को 33 प्रतिशत आरक्षण दिए जाने के पक्ष में हैं, लेकिन इस विधेयक के परिसीमन के प्रावधानों का पुरजोर विरोध करेंगे क्योंकि ये 'खतरनाक' हैं।

प्रावधानों के खिलाफ वोट

राज्यसभा में नेता प्रतिपक्ष एवं कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खरगे के आवास पर हुई विपक्षी दलों की बैठक में नारीशक्ति वंदन अधिनियम में संशोधन और परिसीमन संबंधी विधेयक पर विस्तार से चर्चा की गई तथा ''सर्वसम्मति से'' यह फैसला किया गया कि वे परिसीमन के प्रावधानों के खिलाफ एकजुट होकर वोट करेंगे।

उन्होंने यह भी कहा कि लोकसभा की वर्तमान 543 सीटों के आधार पर वर्ष 2029 से महिला आरक्षण लागू किया जाए।

बैठक में खरगे, लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी, कांग्रेस महासचिव के. सी. वेणुगोपाल और जयराम रमेश, समाजवादी पार्टी के रमाशंकर राजभर और सनातन पांडेय, द्रमुक नेता टी. आर. बालू, जम्मू-कश्मीर के मुख्यमंत्री और नेशनल कांफ्रेंस के नेता उमर अब्दुल्ला शामिल हुए।

विपक्षी नेताओं लिया भाग

इसके अलावा तृणमूल कांग्रेस की सांसद सागरिका घोष, राष्ट्रीय जनता दल (राजद) के नेता तेजस्वी यादव, शिवसेना (उबाठा) के संजय राउत एवं अरविंद सावंत, राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी (शरदचंद्र पवार) की सांसद सुप्रिया सुले, आम आदमी पार्टी (आप) के सांसद संजय सिंह सहित अन्य विपक्षी नेता शामिल हुए। समाजवादी पार्टी (सपा) के अध्यक्ष अखिलेश यादव, शिवसेना (उबाठा) प्रमुख उद्धव ठाकरे और झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने डिजिटल माध्यम से बैठक में भाग लिया।

हम सभी महिला आरक्षण विधेयक के पक्ष में हैं। हालांकि जिस तरह से इसे लाया गया है वह संदिग्ध है और हमें इस पर गंभीर आपत्ति है। यह राजनीति से प्रेरित है। मोदी सरकार विपक्षी दलों को निशाना बनाने और दबाने के लिए इस तरह से काम कर रही है।

बैठक के बाद कांग्रेस अध्यक्ष ने संवाददाताओं से कहा,हम सभी महिला आरक्षण विधेयक के पक्ष में हैं।

मुख्यमंत्री नारी शक्ति वंदन महासम्मेलन में हुए शामिल

रायपुर। मुख्यमंत्री श्री विष्णुदेव साय ने आज राजधानी रायपुर स्थित दीनदयाल उपाध्याय ऑडिटोरियम में आयोजित नारी शक्ति वंदन महासम्मेलन में शामिल हुए और कार्यक्रम को संबोधित किया। उन्होंने इस दौरान महिलाओं के सशक्तिकरण को लेकर केंद्र और राज्य सरकार की प्रतिबद्धता दोहराई। उन्होंने कहा कि नारी शक्ति वंदन अधिनियम 2023 का पारित होना देश की महिलाओं के सशक्तिकरण के लिए एक ऐतिहासिक कदम है, जिससे निर्णय प्रक्रिया में उनकी प्रभावी भागीदारी सुनिश्चित होगी।

विस्तृत समाचार पेज-3 पर

प्रमुख समाचार

बंगाल में विकास नहीं, सिर्फ विनाश हुआ हैः राजनाथ

नईदिल्ली। रक्षा मंत्री और भाजपा नेता राजनाथ सिंह ने बुधवार को तृणमूल कांग्रेस पर तीखा हमला करते हुए कहा कि पिछले पंद्रह वर्षों में पश्चिम बंगाल में विकास की जगह विनाश ही देखने को मिला है। पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव से पहले सिंह ने दक्षिण दिनाजपुर जिले में एक रोड शो किया, जिसमें भारी भीड़ उमड़ी, जो जनता के मजबूत समर्थन को दर्शाती है। सभा को संबोधित करते हुए राजनाथ सिंह ने कहा कि क्या कानून और संविधान ममता की इच्छा के अनुसार चलने चाहिए? पंद्रह साल बीत गए, फिर भी विकास की जगह बंगाल में विनाश ही देखने को मिला है - वोट बैंक की राजनीति तक सिमट गया है, जहां धर्म के आधार पर लाभ बांटे जाते हैं। उत्तरी बंगाल में विकास के लिए केवल 900 करोड़ रुपये आवंटित किए गए हैं, जबकि मदरसों को विकास के लिए 5,000 करोड़ रुपये दिए गए हैं। इस असंतुलन ने आज के युवाओं को संघर्ष करने पर मजबूर कर दिया है। इससे पहले, 12 अप्रैल को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उत्तर बंगाल के खिलाफ कथित भेदभाव और राज्य सरकार की बजट प्राथमिकताओं का मुद्दा उठाया था।

पवन खेड़ा को सुप्रीम कोर्ट से झटका, जमानत पर लगी रोक

नई दिल्ली। कांग्रेस नेता पवन खेड़ा को सुप्रीम कोर्ट से बड़ा झटका लगा है। शीर्ष अदालत ने बुधवार को सुनवाई करते हुए तेलंगाना हाईकोर्ट द्वारा दी गई ट्रांजिट अग्रिम जमानत पर रोक लगा दी। यह मामला असम पुलिस द्वारा दर्ज मानहानि और जालसाजी के आरोपों से जुड़ा है। दरअसल, असम के मुख्यमंत्री हेमंता विस्व सरमा की पत्नी रिनीकी भुइयां शर्मा ने पवन खेड़ा के खिलाफ एफआईआर दर्ज कराई थी। खेड़ा पर आरोप है कि उन्होंने रिनीकी भुइयां के पास कई देशों के पासपोर्ट होने का दावा किया था, जिसे लेकर विवाद खड़ा हुआ। संभावित गिरफ्तारी से बचने के लिए पवन खेड़ा ने तेलंगाना हाईकोर्ट का रुख किया था, जहां से उन्हें एक सप्ताह की ट्रांजिट अग्रिम जमानत मिल गई थी। हालांकि, इस फैसले को असम सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी, जिस पर अब शीर्ष अदालत ने रोक लगा दी है। मामले की सुनवाई जस्टिस जे.के. माहेश्वरी और जस्टिस अतुल एस. चंदुरकर की पीठ ने की। अदालत ने अपने आदेश में स्पष्ट किया।

जनगणना का पहला फेज आज से, 16 मई से 15 जून तक चलेगा

नई दिल्ली। देश में जनगणना दो चरणों में संपन्न होगी- पहला चरण हाउस लिस्टिंग ऑपरेशन और दूसरा चरण पॉपुलेशन काउंटिंग का होगा. इस बार पहली बार यह पूरी प्रक्रिया डिजिटल तरीके से की जाएगी.देश की राजधानी दिल्ली में जनगणना के पहले चरण हाउस लिस्टिंग ऑपरेशन की शुरुआत 16 अप्रैल से होगी. इस दौरान सभी इमारतों और घरों से जुड़ी जानकारी एकत्र की जाएगी. भारत के रजिस्ट्रार जनरल और जनगणना आयुक्त मृत्युंजय कुमार नारायण ने बताया कि जनगणना की प्रक्रिया दो चरणों में 30-30 दिन के लिए चलेगी.जनगणना में लगी टीमें पहले चरण में 16 अप्रैल से 15 मई तक नई दिल्ली नगर पालिका परिषद और दिल्ली के कैंटोनमेंट इलाकों में डेटा एकत्र करेंगी। वहीं दूसरा चरण 16 मई से 15 जून तक दिल्ली नगर निगम के अंतर्गत आने वाले इलाकों में पूरा किया जाएगा।

5 मई के बाद गुंडों को उल्टा लटका देंगेः अमित शाह

नईदिल्ली। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने उत्तरी बंगाल में अपने चुनाव प्रचार के दौरान तृणमूल कांग्रेस (टीएमसी) पर तीखा हमला बोलते हुए कहा कि भाजपा भ्रष्टाचार के जरिए जनता से कथित तौर पर लूटा गया एक-एक रुपया वापस लेगी। बंगाल विधानसभा चुनाव से पहले लगातार रैलियों में बोलते हुए उन्होंने दावा किया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का राजनीतिक करियर बेदाग रहा है और मतदाताओं से राज्य में भाजपा को सत्ता में लाने का आग्रह किया।जलपाईगुड़ी के राजगंज में एक रैली को संबोधित करते हुए शाह ने कहा कि मुख्यमंत्री ममता बनर्जी का सत्ता से हटना अब सिर्फ समय की बात है। केंद्रीय गृह मंत्री ने कहा कि भारतीय जनता पार्टी सत्ता में आने के बाद तृणमूल नेताओं के खिलाफ कार्रवाई करेगी, जिन्होंने शिक्षक भर्ती घोटाले में 300 करोड़ रुपये हड़पे और उत्तर बंगाल के लिए केंद्र द्वारा स्वीकृत बाढ़ राहत कोष से 100 करोड़ रुपये चुराए। शाह ने कहा कि उत्तर बंगाल तीन टी के लिए जाना जाता है-टी (चाय), टिंबर (लकड़ी) और टूरिज्म (पर्यटन)।

आप के सांसद अशोक मित्तल के घर ईडी का छापा

नई दिल्ली। आम आदमी पार्टी के राज्यसभा सांसद और मशहूर शिक्षाविद् अशोक मित्तल के खिलाफ प्रवर्तन निदेशालय ने बड़ी कार्रवाई शुरू की है। प्रवर्तन निदेशालय की टीमों ने मित्तल के पंजाब और हरियाणा स्थित करीब 8 से 9 ठिकानों पर एक साथ छापेमारी की। सूत्रों के अनुसार, यह कार्रवाई जालंधर स्थित उनके आवास, गुरुग्राम और उनके बेटे से जुड़े ठिकानों पर चल रही है। छापेमारी के दौरान अशोक मित्तल अपने जालंधर स्थित घर पर ही मौजूद थे। प्रारंभिक जानकारी के मुताबिक, यह कार्रवाई लवली प्रोफेशनल यूनिवर्सिटी के फंड से जुड़ी कथित वित्तीय अनियमितताओं और गड़बड़ियों को लेकर की जा रही है। ईडी की टीमें दस्तावेजों और वित्तीय लेन-देन के रिकॉर्ड की गहनता से जांच कर रही हैं। इसके साथ ही डिजिटल सबूत जुटाने के लिए इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस भी खंगाले जा रहे हैं, ताकि फंड फ्लो के वास्तविक स्रोतों और संभावित हेरफेर का पता लगाया जा सके। हालांकि, इस मामले में जांच एजेंसी ने अभी तक कोई आधिकारिक विस्तृत बयान जारी नहीं किया है।

अमेरिका-ईरान युद्धविराम एक सकारात्मक कदम

सौरभ वार्ष्णेय

अमेरिका और ईरान के बीच संभावित युद्धविराम न सिर्फ इन दोनों देशों के लिए, बल्कि पूरे विश्व के लिए राहत भरी खबर है। अमेरिका और ईरान के बीच बढ़ता तनाव लंबे समय से वैश्विक शांति, ऊर्जा सुरक्षा और आर्थिक स्थिरता के लिए खतरा बना हुआ था।सबसे पहले, युद्धविराम से क्षेत्रीय शांति को बढ़ावा मिलेगा। मध्य-पूर्व पहले ही कई संघर्षों से जूझ रहा है, और ऐसे में किसी बड़े युद्ध का टलना लाखों लोगों की जान बचा सकता है। साथ ही, यह इजरायल जैसे देशों के लिए भी राहत की स्थिति पैदा करेगा, जो इस तनाव से सीधे प्रभावित होते हैं।दूसरा, वैश्विक अर्थव्यवस्था पर इसका सकारात्मक असर पड़ेगा। युद्ध के दौरान तेल की कीमतों में तेजी आती है, जिससे भारत जैसे तेल आयातक देशों पर बोझ बढ़ता है। युद्धविराम से तेल बाजार में स्थिरता आएगी और महंगाई पर नियंत्रण में मदद मिलेगी।तीसरा, यह कूटनीतिक प्रयासों की जीत भी मानी जाएगी। यदि बातचीत और समझदारी से विवाद सुलझते हैं, तो यह दुनिया के अन्य देशों के लिए भी एक उदाहरण बनेगा कि संघर्ष का समाधान युद्ध नहीं, बल्कि संवाद है।हालांकि, यह भी ध्यान रखना जरूरी है कि युद्धविराम स्थायी शांति की गारंटी नहीं होता। जब तक दोनों पक्ष अपने मतभेदों के मूल कारणों को दूर नहीं करते, तब तक तनाव दोबारा बढ़ सकता है। अमेरिका-ईरान युद्धविराम एक सकारात्मक कदम है, जो न केवल तत्काल संकट को टालता है, बल्कि विश्व शांति और स्थिरता की दिशा में उम्मीद की किरण भी जगाता है।

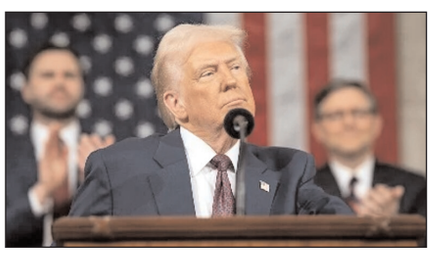

पश्चिम एशिया लंबे समय से संघर्ष, तनाव और अस्थिरता का केंद्र रहा है। अमेरिका और ईरान के बीच बढ़ते टकराव ने न केवल क्षेत्रीय शांति को खतरे में डाला, बल्कि वैश्विक अर्थव्यवस्था और सुरक्षा व्यवस्था पर भी गंभीर असर डाला है। ऐसे में दोनों देशों के बीच युद्धविराम की पहल निस्संदेह एक सकारात्मक और

स्वागतयोग्य कदम है।सबसे पहले, यह युद्धविराम मानवता के दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण है। किसी भी युद्ध में सबसे अधिक नुकसान आम नागरिकों को उठाना पड़ता है। जान-माल की हानि, विस्थापन और भय का वातावरण—ये सब युद्ध के दुष्परिणाम हैं। युद्धविराम से कम-से-कम इस पीड़ा को कुछ हद तक कम करने का अवसर मिलता है।दूसरे, यह कदम क्षेत्रीय स्थिरता की दिशा में एक महत्वपूर्ण संकेत है। मध्य पूर्व पहले ही कई संघर्षों से जूझ रहा है। यदि अमेरिका और ईरान जैसे शक्तिशाली देश संयम दिखाते हैं, तो इससे अन्य देशों को भी संवाद और कूटनीति का मार्ग अपनाने की प्रेरणा मिलेगी।आर्थिक दृष्टि से भी यह युद्धविराम राहत लेकर आता है। युद्ध की स्थिति में तेल की कीमतों में भारी उतार-चढ़ाव होता है, जिसका सीधा प्रभाव भारत जैसे आयात-निर्भर देशों पर पड़ता है। युद्धविराम से वैश्विक बाजारों में स्थिरता आने की उम्मीद बढ़ती है, जिससे आम जनता पर महंगाई का दबाव कम हो सकता है।हालांकि, यह समझना भी आवश्यक है कि युद्धविराम केवल पहला कदम है, अंतिम समाधान नहीं। स्थायी शांति के लिए दोनों देशों को आपसी विश्वास बहाली, संवाद और कूटनीतिक प्रयासों को मजबूत करना होगा। अतीत में कई बार समझौते हुए, लेकिन अविश्वास और राजनीतिक हितों के कारण वे टिक नहीं सके। इसलिए इस बार दोनों पक्षों को गंभीरता और प्रतिबद्धता दिखानी होगी।

अमेरिका-ईरान युद्धविराम एक आशा की किरण है। यह दर्शाता है कि संवाद और समझदारी के जरिए बड़े से बड़े विवाद को भी सुलझाया जा सकता है। अब जरूरत इस बात की है कि इस अवसर को स्थायी शांति में बदला जाए, ताकि पूरी दुनिया एक अधिक सुरक्षित और स्थिर भविष्य की ओर बढ़ सके।

पश्चिम एशिया में लंबे समय से जारी तनाव के बीच अमेरिका और ईरान के बीच युद्धविराम की खबर वैश्विक स्तर पर राहत का संदेश लेकर आई है। विशेष रूप से हॉर्मुज़ जलडमरूमध्य का खुलना अंतरराष्ट्रीय अर्थव्यवस्था, ऊर्जा आपूर्ति और वैश्विक शांति के लिए एक सकारात्मक संकेत माना जा रहा है।

हॉर्मुज़ जलडमरूमध्य दुनिया के सबसे महत्वपूर्ण समुद्री मार्गों में से एक है, जहां से वैश्विक तेल आपूर्ति का बड़ा हिस्सा गुजरता है। इस मार्ग के बाधित होने से तेल की कीमतों में उछाल, आपूर्ति संकट और आर्थिक अस्थिरता जैसी समस्याएं पैदा हो जाती हैं।

अमीर बनने एटीएम मशीन तोड़ चोरी करने की नाकाम कोशिश, पहुंचा जेल

खैरागढ़। फिल्मी अंदाज़ में एटीएम मशीन तोड़कर पैसे निकालने की कोशिश करने वाला आरोपी हकीकत की जमीन पर ज्यादा देर टिक नहीं पाया। रातों-रात अमीर बनने का उसका प्लान कुछ ही घंटों में पुलिस की कार्रवाई के सामने धराशायी हो गया। 14 अप्रैल को उदयपुर स्थित एटीएम में तोड़फोड़ की घटना सामने आई। मशीन की देखरेख करने वाले कर्मचारी ने जब एटीएम बंद देखा तो अंदर का मंजर चौंकाने वाला था। मशीन के साथ लॉबी में छेड़छाड़ और तोड़ फोड़ हुई थी, साफ था कि किसी ने पूरी तैयारी के साथ 'कैश लूटने' की कोशिश की, लेकिन तकनीक और सुरक्षा के आगे उसकी चाल नहीं चल पाई। मामले की सूचना मिलते ही छुईखदान पुलिस ने तेजी दिखाते हुए अपराध दर्ज किया और तुरंत जांच शुरू कर दी। पुलिस ने तकनीकी साक्ष्यों जैसे आसपास की गतिविधियों, संदिग्ध मूवमेंट और मुखबिर नेटवर्क का सहारा लिया। इसी दौरान एक अहम सूचना मिली कि एक व्यक्ति पुलिस को देखकर असामान्य तरीके से बचने की कोशिश कर रहा है। बस फिर क्या था, पुलिस ने घेराबंदी कर उसे पकड़ लिया। पूछताछ में आरोपी चंपालाल जंघेल (40 वर्ष), निवासी ग्राम उदयपुर ने एटीएम में तोड़फोड़ कर चोरी का प्रयास करना स्वीकार कर लिया। उसके पास से वारदात में इस्तेमाल किए गए औजार भी बरामद किए गए हैं।

एकलव्य विद्यालय में नौकरी के नाम पर महिला से लाखों ठगने वाला जेल दाखिल

डोंगरगढ़। नौकरी दिलाने के नाम पर ठगी का एक और मामला सामने आया है, जहां बेरोजगारी की मजबूरी का फायदा उठाकर एक महिला से लाखों रुपये ऐंठ लिए गए। मामले में डोंगरगढ़ पुलिस ने कार्रवाई करते हुए मुख्य आरोपी को गिरफ्तार कर न्यायिक रिमांड पर जेल भेज दिया है। पुलिस के अनुसार, ग्राम अछोली निवासी 33 वर्षीय महिला ललिता सिंह ने थाना डोंगरगढ़ में शिकायत दर्ज कराई थी कि नवंबर 2025 में आशीष पुर्ती और उसका एक साथी काली राम पार्कर (निवासी जिला दुर्ग) ने उसे एकलव्य मॉडल आवासीय विद्यालय में काउंसलर पद पर नौकरी दिलाने का भरोसा दिलाया। इसके एवज में आरोपियों ने कुल 4 लाख रुपये की मांग की और एडवांस के रूप में 2 लाख रुपये ले लिए। पीड़िता का आरोप है कि रकम लेने के बाद आरोपियों ने न तो नौकरी दिलाई और न ही पैसे लौटाए। काफी समय तक टालमटोल करने के बाद जब सच्चाई सामने आई, तब पीड़िता ने पुलिस का सहारा लिया।

छत्तीसगढ़ वेदांता पावर प्लांट हादसा, कांग्रेस ने भी बनाई जांच टीम

सक्ती। बिजली उत्पादन करने वाली वेदांता पावर प्लांट में कल हुए हादसे में 17 मजदूरों की अबतक मौत हो चुकी है. अभी भी गंभीर रुप से घायलों का इलाज रायपुर में चल रहा है। जिसमें से कई घायलों की हालत गंभीर बनी हुई है। सक्ती कलेक्टर ने कहा है कि हम हालात पर नजर बनाए हुए हैं। घायलों को अच्छे से अच्छा इलाज मिले इसकी पूरी व्यवस्था की गई है। कलेक्टर ने कहा कि प्लांट प्रबंधन और जिला प्रशासन की चर्चा की बाद मुआवजे का भी ऐलान कर दिया गया है। हादसे में जिन मजदूरों की जान गई है, उनके परिजनों को 35 लाख दिया जाएगा। इसके साथ ही परिवार के सदस्य को नौकरी दी

जाएगी। जिन घायलों का इलाज चल रहा है उनके इलाज का खर्च भी प्लांट प्रबंधन उठाएगा। जिला प्रशासन ने हादसे की जांच के लिए मजिस्ट्रियल इंक्वायरी के आदेश दे दिए हैं।एक तरह जहां मरने वालों का आंकड़ा बढ़ता जा रहा है, वहीं इस दुखद हादसे पर सियासत भी तेज होने लगी है। कांग्रेस ने हादसे की जांच के लिए अपनी एक जांच दल गठित की है। ये जांच दल पीड़ित परिवारों और मजदूरों से मिलकर हादसे से जुड़ी जानकारी जुटाएगा। जिला प्रशासन की टीम ने भी हादसे की जांच 8 बिंदुओं पर करेगी।

जांच में यह परीक्षण किया जाएगा कि घटना कब और कैसे घटित हुई। घटना स्थल पर कौन-कौन मजदूर कार्यरत थे, तथा किन-किन मजदूरों की मृत्यु एवं कौन-कौन घायल हुए। सहायक संचालक, औद्योगिक स्वास्थ्य एवं सुरक्षा जिला जांजगीर चांपा और सक्ती की ओर से उत्पादन प्रारंभ होने से लेकर घटना दिनांक तक किए गए निरीक्षणों की समीक्षा की जाएगी। यह देखा जाएगा कि निरीक्षण के दौरान कोई खामियां पाई गई थीं या नहीं, यदि कोई खामी पाई गई थी तो उन पर क्या कार्रवाई हुई। घटना के कारणों का निर्धारण करते हुए यह स्पष्ट किया जाएगा कि दुर्घटना तकनीकी कारणों से हुई या मानवीय त्रुटि के कारण। यह भी निर्धारित किया जाएगा कि इस घटना के लिए कौन जिम्मेदार है। हादसे में जिन मजदूरों की जान गई उनके नाम- रितेश कुमार, भागलपुर, बिहार, अमृत लाल पटेल, सक्ती, छत्तीसगढ़, तरुण कुमार ओझा, सिंदरी, धनबाद, आकिब खान, दरभंगा, बिहार, सुशांत जना, मेदनीपुर, प. बंगाल, अब्दुल करीम, बोका, झारखंड, उधब सिंह यादव, रायगढ़, छत्तीसगढ़, शेख सैफुद्दीन, मेदनीपुर, प. बंगाल, पप्पू कुमार, सोनभद्र, यूपी अशोक परहिया, पलामू, झारखंड, मानस गिरी, मेदनीपुर, प. बंगाल, ब्रजेश कुमार, सोनभद्र, यूपी, रामेश्वर महिलांगे, खिरोरा, जांजगीर चांपा, कार्तिक महतो, पुरुलिया, प. बंगाल, नदीम अंसारी, सक्ती, छत्तीसगढ़,खशिवनाथ मुर्मू, पुरुलिया, प. बंगाल, ठंडा राम लहरे।

धान खरीदी में 2.54 करोड़ का घोटाला, ऑनलाइन व स्टॉक में बड़ा अंतर

केंद्र प्रभारी के खिलाफ एफआईआर दर्ज, जांच में हुए कई चौंकाने वाले खुलासे

मुंगेली। जिले में धान खरीदी को लेकर बड़ा घोटाला उजागर हुआ है। जिले के हथनीकला धान खरीदी केंद्र में पदस्थ प्रभारी विक्रम सिंह राजपूत पर करीब 2.54 करोड़ के धान गबन का आरोप लगा है। मामले में सिटी कोतवाली थाना में एफआईआर दर्ज कर पुलिस ने जांच शुरू कर दी है।

बता दें कि जिला सहकारी केंद्रीय बैंक मर्यादित शाखा मुंगेली में पदस्थ पर्यवेक्षक भरत लाल कौशिक ने इस पूरे मामले की शिकायत दर्ज कराई है। उन्होंने लिखित आवेदन में आरोप लगाया है कि आरोपी द्वारा कुल 8216.30 क्विंटल धान की हेराफेरी कर अमानत में खयानत की गई है, जिसकी कुल कीमत 2,54,70,530 है।

भरत लाल कौशिक ने बताया कि मामले की गंभीरता को देखते हुए कलेक्टर (सहकारिता शाखा) मुंगेली द्वारा 30 मार्च 2026 को संयुक्त जांच दल गठित किया गया था। इस जांच दल में नायब तहसीलदार चंदन दुबे,

सहकारिता विस्तार अधिकारी मिथलेश साहू, खाद्य निरीक्षक भानूप्रिया नंदकर, जिला सहकारी बैंक सरगांव के पर्यवेक्षक सुनील यादव और मंडी निरीक्षक शुभम पैकरा शामिल थे। टीम ने 8 अप्रैल 2026 को अपनी जांच रिपोर्ट प्रस्तुत की।

जांच रिपोर्ट में भौतिक सत्यापन के दौरान बड़े पैमाने पर गड़बड़ी सामने आई। ऑनलाइन रिकॉर्ड में 9798.70 क्विंटल धान दर्शाया गया था, जबकि मौके पर केवल 7534 क्विंटल (18835 बोरी) धान ही मिला। इसके अलावा 682.30 क्विंटल का वजन शॉर्टेज पाया गया। इस प्रकार कुल 8216.30 क्विंटल धान की कमी सामने आई, जिसकी कीमत प्रति क्विंटल 3100 के हिसाब से 2,54,70,530 आंकी गई है।

जांच में यह भी पाया गया कि धान की किस्म में भारी अंतर है। ऑनलाइन रिपोर्ट के अनुसार मोटा धान 261.60 क्विंटल और सरना धान 9537.10 क्विंटल दर्ज था, जबकि मौके पर मोटा धान 1260.40 क्विंटल और सरना धान मात्र 322 क्विंटल पाया गया। इस तरह मोटा धान 998.80 क्विंटल अधिक और सरना धान 9215.10 क्विंटल कम मिला। जांच के दौरान कई गंभीर अनियमितताएं भी सामने आईं।

कंप्यूटर ऑपरेटर की अनुपस्थिति में डेटा एंट्री की गई, जबकि बारदाना प्रभारी की गैरमौजूदगी में धान की लोडिंग और रख-रखाव किया गया। साथ ही आरोपी और उसके पिता द्वारा अनियमित तरीके से कार्य संचालन किए जाने की बात भी सामने आई है। जांच के दौरान आरोपी विक्रम सिंह राजपूत पिछले 3-4 दिनों से अनुपस्थित पाया गया। उसका मोबाइल फोन बंद मिला और घर पर नोटिस चस्पा करने के बाद भी वह उपस्थित नहीं हुआ। इससे जानबूझकर गड़बड़ी करने की आशंका और मजबूत हो गई है।

सहायक आयुक्त सहकारिता द्वारा आरोपी को 10 अप्रैल 2026 को अंतिम अवसर देकर जवाब मांगा गया था, लेकिन निर्धारित समय सीमा में कोई जवाब प्रस्तुत नहीं किया गया। इसके बाद नोडल अधिकारी के निर्देश पर 13 अप्रैल 2026 को सिटी कोतवाली थाना मुंगेली में एफआईआर दर्ज कराई गई। फिलहाल पुलिस पूरे मामले की गहन जांच में जुटी हुई है और यह पता लगाने की कोशिश कर रही है कि इस घोटाले में और कौन-कौन लोग शामिल हैं।

रेड कॉल सेंटर से सुरक्षित होगी हर डिलीवरी

- **30 दिन तक मां-बच्चे की डिजिटल निगरानी, प्रशासन का दावा-जिले की हर गर्भवती महिलाओं तक पहुंचेगा लाग**

जगदलपुर। जगदलपुर के महारानी अस्पताल में रेड (रीचिंग एवरी डिलिवरी) कॉल सेंटर शुरू किया गया है। इससे जिले की हर गर्भवती महिला तक स्वास्थ्य सेवाओं की सीधी पहुंच होगी। इस व्यवस्था के तहत प्रसव से पहले और प्रसव के बाद 30 दिनों तक मां-नवजात शिशु की डिजिटल निगरानी की जाएगी। जिससे किसी भी संभावित समस्या का समय रहते समाधान किया जा सके। इस कॉल सेंटर का उद्घाटन एक नवजात शिशु की मां के हाथों कराया गया। कॉल सेंटर के माध्यम से गर्भवती महिलाओं से सीधे संवाद स्थापित कर उन्हें सुरक्षित और संस्थागत प्रसव के लिए प्रेरित किया जाएगा। नई व्यवस्था के तहत विशेष रूप से 7 से 9 महीने की गर्भवती महिलाओं, खासकर हाई रिस्क श्रेणी में आने वाली महिलाओं पर फोकस किया जाएगा। कॉल सेंटर के प्रतिनिधि सप्ताह में एक से दो बार फोन के माध्यम से इन महिलाओं से संपर्क करेंगे, उनकी स्वास्थ्य स्थिति की जानकारी लेंगे और आवश्यक परामर्श देंगे। साथ ही जरूरत पड़ने पर नजदीकी स्वास्थ्य केंद्रों के साथ समन्वय स्थापित कर समय पर उपचार और सहायता सुनिश्चित की जाएगी।

सूरजपुर जनपद पंचायत के सामने बनी झोपड़ियों में भीषण आग, बड़ा हादसा टला

सूरजपुर। सूरजपुर जिले में एक बड़ा हादसा उस वक्त टल गया जब जनपद पंचायत कार्यालय के बाहर अचानक भीषण आग लग गई।आग इतनी तेजी से फैली कि देखते ही देखते आसपास झोपड़ियों में बने अस्थायी दुकान भी चपेट में आ गए। घटना के बाद इलाके में अफरा-तफरी का माहौल बन गया और लोग अपनी-अपनी दुकानों से सामान बचाने में जुट गए। आपको बता दें कि आग लगने का कारण अभी तक स्पष्ट नहीं हो पाया है, लेकिन शुरुआती अंदाजा शॉर्ट सर्किट

या लापरवाही को माना जा रहा है। हालांकि, इसकी आधिकारिक पुष्टि अभी नहीं हुई है। घटना के दौरान वहां मौजूद स्थानीय दुकानदारों ने हिम्मत और सूझबूझ का परिचय देते हुए तुरंत आग बुझाने की कोशिश शुरू कर दी।दुकानदारों ने बाल्टियों में पानी लाकर आग पर काबू पाने की कोशिश की।काफी मशक्कत के बाद आखिरकार आग को फैलने से रोक गया।यदि समय रहते आग पर काबू नहीं पाया जाता, तो यह घटना एक बड़े हादसे में बदल सकती थी। आपको बता दें कि जिस जगह पर आग लगी, उसके ठीक पास ही जनपद पंचायत कार्यालय को बिजली आपूर्ति करने के लिए एक जनरेटर रखा हुआ था। यदि आग जनरेटर तक पहुंच जाती, तो विस्फोट होने की आशंका थी, जिससे जान-माल का भारी नुकसान हो सकता था। फिलहाल आग पर पूरी तरह काबू पा लिया गया है।

कवर्धा राजपरिवार के मंदिर से मुकुट चोरी

कवर्धा। कवर्धा राजपरिवार के हनुमान मंदिर में चोरी की घटना सामने आई है। अज्ञात चोरों ने मंदिर से लगभग 10 तोला चांदी का मुकुट चोरी कर लिया है। मंदिर के पुजारी की शिकायत पर कोतवाली पुलिस ने जांच शुरू कर दी है। पूरा मामला कवर्धा सिटी कोतवाली थाना क्षेत्र के फूलवारी का है। मंदिर में स्थापित हनुमान जी की प्रतिमा पर चांदी का मुकुट लगा था। पुजारी से मिली मुकुट चोरी की सूचना पर जांच के लिए पहुंची कोतवाली पुलिस ने घटनास्थल के निरीक्षण के बाद आसपास के लोगों से पूछताछ करते हुए सुराग जुटाने में लगी है।

सूरजपुर के भैयाथान में दूर होगा जल संकट जिला प्रशासन ने शुरू किया बोर खनन का काम

सूरजपुर। जिले में लगातार घट रहे भू-जलस्तर के चलते पानी की किल्लत कई इलाकों में दिनों दिन बढ़ती जा रही है। सबसे ज्यादा दिक्कत भैयाथान इलाके में हो रही है। भू-जलस्तर के गिरने से कुएं और तालाब का पानी कम होता जा रहा है। कई जगहों पर तो कुएं और तालाब भी पूरी तरह से सूख चुके हैं। बीते दिनों ईटीवी भारत की टीम ने, भैयाथान विकासखंड के अंतर्गत आने वाले ग्राम केवटाली के बरपारा और जुडहापार की तस्वीरें दिखाई थी। ये बताया था कि लगातार कम होते जल स्रोतों की वजह से स्थानीय लोग अप्रैल के महीने में

ही पानी की किल्लत से जूझने को मजबूर हैं। स्थानीय लोगों ने भी शिकायत करते हुए कहा कि वो मजबूरी में ढोढी यानी गड्ढों में जमा पानी पीने को मजबूर हैं। इससे वो बीमार भी हो सकते हैं लेकिन उनके पास कोई और चारा नहीं है। ईटीवी भारत की खबर पर संज्ञान लेते हुए पीएचई विभाग ने अब ग्रामीणों को बड़ी राहत देने की बात कही। लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग (पीएचई) की टीम ने जल संकट से जूझ रहे प्रभावित इलाकों का दौरा किया और बोर खनन का कार्य शुरू कर दिया है। बोर खनन के माध्यम से अब ग्रामीणों को स्वच्छ पेयजल उपलब्ध कराने की पहल की जा रही है, जिससे उनकी लंबे समय से चली आ रही समस्या का स्थायी समाधान हो सके। बोर खनन की खबर से गांव के लोगों में खुशी का माहौल है।

लोगों ने कहा कि वो पिछले कई सालों से जल संकट और पानी के पानी की समस्या से जूझ रहे हैं। अब जब संबंधित विभाग ने बोर खनन का काम शुरू कर दिया है।

छत्तीसगढ़ प्रमुख समाचार

सरगुजा में 3 परिवार के 16 लोगों की घर वापसी

सरगुजा। जिले में 5 साल पहले ईसाई धर्म अपनाने वाले 3 परिवार के 16 लोगों की समाज प्रमुखों ने घर वापसी कराई है। समाज के लोगों ने इसके लिए कई घंटे तक बैठक की और तीनों परिवारों की सहमति ली। इसके बाद कलश के दीप जलाकर तीनों परिवारों की घर वापसी कराई। सरगुजा में तेजी से धर्मांतरण के दावों के बीच यह पहल चर्चा में है। जानकारी के मुताबिक, लखनपुर ब्लॉक के ग्राम पंचायत पटकुरा में मझवार समाज घर वापसी का कार्यक्रम रखा। पंचायत के सरपंच और समाज के प्रमुख सोनसाय मझवार ने इसकी पहल की। मझवार समाज के तीन परिवारों सालिक राम, बैगा राम मझवार ओर बढाईक राम मझवार ने पहले ईसाई धर्म अपना लिया था। वे ईसाई रीति रिवाज को मानने लगे थे।सरपंच सोनसाय मझवार ने बताया कि, समाज के प्रमुखों ने बैठक आयोजित कर तीनों परिवारों के प्रमुखों और अन्य लोगों को समझाइश दी। मझवार समाज अनुसूचित जन जाति वर्ग में आते हैं। ये परंपरागत रूप से हिंदू धर्म को मानते हैं। तीनों परिवारों ने समझाइश के बाद हिंदू धर्म में वापसी के लिए अपनी सहमति दे दी।

स्वामी आत्मानंद अंग्रेजी माध्यम उत्कृष्ट विद्यालय में बंपर वैकेंसी

जगदलपुर। आत्मानंद स्कूलों में शिक्षकीय समेत गैर शिक्षिकीय पदों पर भर्ती ली जाएगी। इसके लिए आवेदन 27 अप्रैल 2026 शाम 5.30 बजे तक जमा किए जा सकते हैं। बस्तर संभाग के ब्लॉक में सहायक शिक्षक (विज्ञान, कला) और व्याख्याता (अंग्रेजी) सहित अन्य पदों पर 134 रिक्तियों के लिए ऑफलाइन आवेदन मांगे गए हैं। संबंधित विषय में स्नातक/स्नातकोत्तर योग्य उम्मीदवार आवेदन कर सकते हैं। स्वामी आत्मानंद अंग्रेजी माध्यम उत्कृष्ट विद्यालय में व्याख्याता, शिक्षक, सहायक शिक्षक, ग्रंथपाल, चपरासी और चौकीदार पदों के लिए वैकेंसी निकली है। अलग-अलग पदों के लिए शैक्षणिक योग्यता अलग-अलग है। शिक्षकों के लिए टीईटी पास होना अनिवार्य है। आईए आपको बताते हैं कि बस्तर में किन जगहों के स्वामी आत्मानंद अंग्रेजी माध्यम उत्कृष्ट विद्यालय में संविदा पदों पर भर्तियां निकली है। बस्तर, दरभा, लोहण्डीगुड़ा, तोकापाल, करपावण्ड, किलेपाल, धरमपुरा, नानगुर, भानपुरी, बकावण्ड, माड़पाल, बड़ेचकवा, मांझीगुड़ा चिंगपाल, अलनार, करंजी।

चिमनी निर्माण के दौरान हुआ था हादसा- ज्योत्सना महंत

कोरबा। सक्ती जिले के वेदांता पावर प्लांट हादसे में अब तक 17 लोगों की मौत, विपक्ष ने इसे लापरवाही बताते हुए सवाल उठाए हैं। कांग्रेस ने जांच के लिए कमेटी बनाई और सरकार से उच्च स्तरीय जांच की मांग की है। कोरबा सांसद ज्योत्सना चरणदास महंत ने इस घटना को सुरक्षा नियमों की बार-बार अनदेखी बताया। उन्होंने याद दिलाया कि इससे पहले वेदांता के कोरबा प्लांट में चिमनी निर्माण के दौरान एक बड़ा हादसा हुआ था। उस दुर्घटना में लगभग 40 श्रमिकों की मौत हुई। उन्होंने आरोप लगाया कि कंपनी प्रबंधन ने सुरक्षा व्यवस्था में पर्याप्त सुधार नहीं किया है और वेदांता लिमिटेड के संयंत्रों में श्रमिकों की सुरक्षा पर अक्सर सवाल उठते रहे हैं। सांसद ने कहा कि बार-बार हादसों के बावजूद जिम्मेदार एजेंसियों की चुप्पी चिंताजनक है। उन्होंने मामले की उच्च स्तरीय जांच समिति गठित करने, जिम्मेदार अधिकारियों और प्रबंधन के खिलाफ एफआईआर दर्ज कर सख्त कार्रवाई की मांग की। ज्योत्सना महंत ने मांग की कि वेदांता प्रबंधन मृतक श्रमिकों के परिवारों को उचित मुआवजा दे।

जनगणना कार्य से सम्बद्ध अधिकारी-कर्मचारियों का अवकाश निरस्त

उब कांकेर। जनगणना 2027 के महत्वपूर्ण राष्ट्रीय कार्य को सुचारू एवं समयबद्ध रूप से सम्पन्न कराने के उद्देश्य से कलेक्टर एवं प्रमुख जिला जनगणना अधिकारी निलेशकुमार महादेव क्षीरसागर ने इससे सम्बद्ध अधिकारी-कर्मचारियों का अवकाश पर प्रतिबंध लगाने का आदेश जारी किया है। जारी आदेश के अनुसार जिले के सभी मास्टर ट्रेनर्स, फील्ड ट्रेनर्स, प्रगणकों, पर्यवेक्षकों तथा जनगणना कार्य में सम्बद्ध अधिकारी-कर्मचारियों के अवकाश 15 अप्रैल से 10 जून तक प्रतिबंधित किया गया है। उक्त अवधि में कोई भी अधिकारी अथवा कर्मचारियों को बिना पूर्व अनुमति के मुख्यालय छोड़ने की अनुमति नहीं होगी। आदेश में उल्लेख किया गया है कि विशेष परिस्थितियों में जिला स्तर के मास्टर ट्रेनर्स, फील्ड ट्रेनर्स एवं जनगणना कार्य में सम्बद्ध अधिकारी-कर्मचारियों हेतु कलेक्टर एवं प्रमुख जिला जनगणना अधिकारी तथा विकासखण्ड तहसील स्तर के प्रगणकों, पर्यवेक्षकों व इस कार्य में सम्बद्ध कर्मचारियों को संबंधित अनुविभागीय जनगणना अधिकारी द्वारा अवकाश स्वीकृत किया।

नगर पंचायत नवागढ़ के अध्यक्ष को हाईकोर्ट से बड़ी राहत

बिलासपुर। बेमेतरा जिले के नपं नवागढ़ के अध्यक्ष सिद्धांत चौहान को हटाने के आदेश पर हाईकोर्ट ने लगाई रोक लगा दी है। कोर्ट ने उन्हें हटाने के आदेश के प्रभाव एवं प्रचलन पर भी फिलहाल स्थगन दिया है। न्यायालय ने सिद्धांत चौहान को पद पर बने रहते हुए कार्य करते रहने की अनुमति दी है। मामले की अगली सुनवाई तक यथास्थिति बनाए रखने के निर्देश दिए हैं। दरअसल, सिद्धांत चौहान का चुनाव सीधे जनता के द्वारा नगर पंचायत नवागढ़ के अध्यक्ष के पद पर 5.02.25 को हुआ, और पहली मीटिंग 08.03.25 को हुई, जिसमें उपाध्यक्ष का चुनाव किया गया। 11.03.25 को सिद्धांत चौहान द्वारा प्रेसिडेंट इन काउंसिल का गठन किया, परंतु प्रेसिडेंट इन काउंसिल के सदस्यों द्वारा इस्तीफा प्रस्तुत किया, जिसे सिद्धांत चौहान ने अस्वीकार किया। इसके पश्चात नगर पंचायत नवागढ़ के विभिन्न कार्यों का संपादन नियमानुसार सिद्धांत चौहान द्वारा किया गया। पार्षदों ने असहयोग करने पर निर्माण व आवश्यक कार्यों से संबंधित सभी प्रस्ताव सामान्य सभा में प्रस्तुत किए गए।

वन विभाग की मेहरबानी! आम और सेमल की तस्करी में शामिल गाड़ियों को बिना कार्रवाई के छोड़ा

- **एसडीओ की भूमिका पर सवाल**

कोंडागांव। कोंडागांव जिले में फलदार और प्रतिबंधित वृक्षों की अवैध कटाई और तस्करी का खेल थमने का नाम नहीं ले रहा है, और इस खेल का वन विभाग के अधिकारियों का शह मिल रहा है। इसका नमूना जिले के बोरगांव के पास लकड़ी से लदी दो गाड़ियों को घेराबंदी कर पकड़ने के बाद देखने को मिला, जब अधिकारी ने कागजात को सही बताते हुए गाड़ियों को तुरंत छोड़ने का आदेश दे दिया। जानकारी के अनुसार, मुखबिर की मिली

सटीक सूचना पर वन विभाग के अमले ने दो गाड़ियों को पकड़ा, जिनमें भारी मात्रा में प्रतिबंधित आम और सेमल की लकड़ियां भरी हुई थी।

कर्मचारियों ने जैसे ही गाड़ियों की जांच शुरू की, उपवनमंडलधिकारी ने मौके पर मौजूद अमले को निर्देश दिया कि गाड़ियों के कागज ओके हैं, इन्हें तुरंत छोड़ दिया जाए। अधिकारी के आदेश पर कर्मचारियों ने गाड़ी तो तुरंत छोड़ दी, लेकिन बड़ा सवाल यह है कि बिना भौतिक सत्यापन और ट्रांजिट पास की मौके पर जांच किए, महज एक फोन कॉल के आधार पर अवैध वनोपज को कैसे वैध घोषित किया जा सकता है पकड़ी गई दोनों गाड़ियां दुर्ग-भिलाई पासिंग हैं। स्थानीय ग्रामीणों का सवाल है—यदि लकड़ी का परिवहन इतना ही सरल है, तो रायपुर-दुर्ग से गाड़ियां विशेष रूप से कोंडागांव के ग्रामीण अंचलों में लकड़ी लेने क्यों आ रही हैं? यह किसी बड़े संगठित गिरोह की ओर इशारा करता है। जब मीडिया ने इस संदिग्ध कार्रवाई पर स्छह से पक्ष जानना चाहा, तो उन्होंने कैमरे पर बाइट देने से साफ इनकार कर दिया। हालांकि, मीडिया के पास उपलब्ध विशेष वीडियो रिकॉर्डिंग में अधिकारी यह तर्क देते सुने जा रहे हैं कि आम और सेमल को पंचायत स्तर पर बिना किसी अनुमति के काटकर परिवहन किया जा सकता है। विशेषज्ञों का कहना है कि अधिकारी का यह बयान न केवल भ्रामक है, बल्कि विभागीय राजपत्र के भी खिलाफ है। आम एक फलदार वृक्ष है और सेमल इमारती लकड़ी की श्रेणी में आता है।

मनेंद्रगढ़ में कांग्रेस ने आयोजित किया वृहद शिविर

मनेंद्रगढ़-चिरमिरी-भरतपुर। डॉ. भीमराव अंबेडकर जयंती के अवसर पर मनेंद्रगढ़ में कांग्रेस पार्टी द्वारा एक विशाल रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया। इस शिविर में सुबह से ही बड़ी संख्या में लोग रक्तदान करने पहुंचे। कार्यक्रम में

भरतपुर-सोनहत के पूर्व विधायक गुलाब कमरो भी शामिल हुए। उन्होंने स्वयं रक्तदान कर उपस्थित लोगों को प्रेरित किया। कमरो ने कहा कि रक्तदान एक महादान है, जिससे जरूरतमंद मरीजों को नया जीवन मिल सकता है। उनके इस कदम से लोगों में उत्साह बढ़ा और बड़ी संख्या में लोगों ने स्वेच्छा से रक्तदान किया। शिविर की एक खास बात यह रही कि 58 वर्षीय संतोष अग्रवाल नाम की महिला ने भी बिना किसी झिझक के रक्तदान किया। उनके इस कार्य से समाज में एक सकारात्मक संदेश गया। आयोजकों ने बताया कि महिलाएं अक्सर भ्रांतियों के कारण रक्तदान से हिचकती हैं।

शराब लेते समय भीड़ में हाथ टकराने पर पिटाई

कोरबा। कोरबा में बीच सड़क मारपीट के 2 अलग-अलग मामले सामने आए हैं। बिलासपुर और कोरबा में मामूली बात पर जमकर लात-घूंसे और डंडे चले हैं, जिसका वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ है। पहला मामला कोरबा का है, जहां शराब लेने के दौरान भीड़ में हाथ टकराने पर मारपीट हो गई। दूसरा मामला बिलासपुर का है, जहां होटल से खाना लेकर लौट रहे युवक को विवाद के बाद बदमाशों ने पीट दिया। घटना कोरबा जिले के सिविल लाइन रामपुर थाना क्षेत्र की है। 11 अप्रैल की रात 10 बजे निहारिका स्थित अंग्रेजी शराब दुकान के सामने कुछ युवकों के बीच आपसी विवाद हो गया।

निर्माणाधीन पानी की टंकी में गिरा संरक्षित बज्जू

कोरबा। जिले के कटघोरा वन मंडल के ग्राम मुढाली में एक एशियन पाम सिवेट (बज्जू) को पानी की निर्माणाधीन टंकी से सुरक्षित बाहर निकाला गया। यह बज्जू कई दिनों से टंकी में फंसा हुआ था। नोवा नेचर वाइल्डलाइफ रेस्क्यू टीम ने कड़ी मशक्कत के बाद उसे बचाकर जंगल में छोड़ दिया। दरअसल, हरदीबाजार क्षेत्र के ग्राम मुढाली में बन रही पानी की टंकी में यह बज्जू गिर गया था। ग्रामीणों ने उसे बाहर निकालने के लिए टंकी में सीढ़ी भी लगाई, लेकिन कई दिनों तक वह बाहर नहीं निकल पाया। इसके बाद गांव के युवक भूपेंद्र दास ने नोवा नेचर टीम के जितेंद्र सारथी को इसकी सूचना दी।

संक्षिप्त समाचार

ग्राम नरदहा में ग्राम सभा का आयोजन विकास एवं आय के स्रोतों पर हुई चर्चा

रायपुर। ग्राम पंचायत नरदहा में आज ग्राम

सभा का आयोजन सरपंच श्रीमती निलिमा वर्मा की अध्यक्षता में किया गया। ग्राम सभा में शासन द्वारा निर्धारित विभिन्न विषयों पर विस्तार से चर्चा की गई तथा ग्रामीणों की सहभागिता सुनिश्चित की गई। कार्यक्रम में जिला पंचायत रायपुर के उप संचालक श्री कमल सिदार ने ग्रामीणों को संबोधित करते हुए पंचायत की स्वयं की आय के स्रोतों को बढ़ाने के लिए प्रेरित किया तथा स्थानीय संसाधनों के बेहतर उपयोग पर जोर दिया। ग्राम पंचायत के सचिव श्री यशवंत कन्नौजे द्वारा वित्तीय वर्ष 2025-26 में प्राप्त विभिन्न योजनाओं से संबंधित आय एवं व्यय का विवरण ग्राम सभा में पढ़कर सुनाया गया। इसके साथ ही अन्य विकासात्मक विषयों पर भी विचार-विमर्श किया गया। ग्राम सभा के माध्यम से पंचायत के विकास कार्यों में पारदर्शिता एवं जनभागीदारी को बढ़ावा देने की दिशा में महत्वपूर्ण पहल की गई। ग्राम सभा में उपसरपंच श्री हेमलाल साहू, पंचगण श्री चन्द्र कुमार कुर्रे, डॉ. नरेंद्र वर्मा, श्री रविंद्र वर्मा, श्री नीलकंठ साहू, श्रीमती भागीरथी यादव, श्री चंदूलाल वर्मा (पूर्व सरपंच प्रतिनिधि), श्री सुखीराम लहरे (पूर्व ग्रामीण सभा अध्यक्ष), रोजगार सहायक श्रीमती दुलेश्वरी वर्मा, समस्त मेट एवं बड़ी संख्या में ग्रामीणजन उपस्थित रहे।

एमडी के नाम से फर्जी संदेश भेजकर साइबर ठगी की कोशिश

रायपुर। छत्तीसगढ़ स्टेट पॉवर ट्रांसमिशन कंपनी के प्रबंध निदेशक श्री राजेश कुमार शुक्ला के नाम का दुरुपयोग करते हुए अज्ञात व्यक्तियों व्दारा अधिकारियों को ठगने का प्रयास किया गया। अधिकारियों की सजगता एवं सतर्कता से ठगों के मनसूबे नाकाम हो गए और इसकी शिकायत टोल फ्री नंबर 1930 में कर दी गई है। ट्रांसमिशन कंपनी के कुछ अधिकारियों को आज दोपहर में एक फर्जी मोबाइल नंबर 99315-25803 से व्हाट्सएप के माध्यम से संदेश भेजे गए, जिनमें स्वयं को एमडी बताते हुए यह कहा गया कि वे किसी महत्वपूर्ण बैठक में व्यस्त हैं और तत्काल प्रभाव से एक बड़ी राशि 49 लाख 60 हजार 801 आरटीजीएस के माध्यम से एक निर्दिष्ट खाते में स्थानांतरित की जाए। संदेश में जल्दबाजी का माहौल बनाते हुए अधिकारियों पर तुरंत कार्रवाई करने का दबाव भी बनाया गया, जो कि साइबर ठगों द्वारा अपनाई जाने वाली सामान्य रणनीति मानी जाती है। मैसेज में बैंक का नाम, खाता संख्या, आईएफएसई कोड और लाभार्थी के संस्थान का नाम लिखा था। कंपनी के सतर्क अधिकारियों ने इस संदिग्ध संदेश को गंभीरता से लेते हुए इसकी पुष्टि करने का प्रयास किया, जिसके बाद यह स्पष्ट हुआ कि यह पूरा मामला एक सुनियोजित साइबर फ्रॉड है।

पनीर है कि एनालॉग से बना डिश मेनू कार्ड में बताना होगा

रायपुर। शहर में पिछले दिनों बड़े पैमाने पर मिले नकली पनीर के जखीरा ने हैरानी में डाल दिया है कि आखिर अब तक जिसे पनीर समझ कर लोग खा रहे थे वह मिलावटी था.वहीं एक बड़े तबके को होटल ढाबों में दूध से बने पनीर की जगह स्किम्ड मिल्क पाउडर, फैट, सोयाबीन ऑयल आदि से बने एनालॉग खिलाया जा रहा है जिसे समझ पाना आम आदमी के लिए आसान नहीं हैं। लगातार विरोध और स्वास्थ्य विभाग की सक्रियता को देखते हुए अब ऐसे उपयोगकर्ता भी सोंचने मजबूर हुए हैं। विभागीय जानकार बता रहे हैं कि होटल व ढाबों में अगर दूध से बने पनीर की आपूर्ति नहीं है तो संचालक अपने मेनू कार्ड से पनीर से बनाई जाने वाली डिश के लिए पनीर शब्द की जगह एनालॉग बटर मसाला, एनालॉग टिक्का आदि-आदि लिखेंगे। तब लोगों को तय करना होगा कि वे ऐसे पनीर को खाएं या न खाएं। क्योंकि बाजार में ज्यादातर दूध से बने पनीर की जगह स्किम्ड मिल्क पाउडर, फैट, सोयाबीन ऑयल आदि से बना एनालॉग धड़ल्ले से बिक रहा है।

नारी शक्ति महासम्मेलन सम्पन्न में सीएम साय बोले नरेंद्र मोदी ने 12 वर्षों में महिलाओं का सम्मान बढ़ाने का किया है काम

रायपुर। नारी शक्ति वंदन अधिनियम को लेकर पंडित दीनदयाल उपाध्याय ऑडिटोरियम रायपुर में नारी शक्ति महासम्मेलन आयोजित किया गया।कार्यक्रम में विभिन्न समाजिक संगठन की महिलाएं हजारों की संख्या में शामिल हुई। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने कहा कि नारी शक्ति महासम्मेलन को संबोधित करते हुए कहा कि 21वीं सदी में एक बहुत ही महत्वपूर्ण निर्णय होने जा रहा है। संसद में 33 प्रतिशत आरक्षण सुनिश्चित किया जा रहा है। इसके लिए देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी नए भारत का निर्माण कर रहे हैं। नारी शक्ति वंदन अधिनियम के समर्थन में पूरे देश में नारी शक्ति वंदन अधिनियम के समर्थन के लिए विभिन्न प्रकार के कार्यक्रम चल रहे हैं। देश में प्राचीन काल से नारी का सम्मान होते आया है। भगवान से पहले भगवती का नाम आता है। आधुनिक भारत के निर्माण में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी काम कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने 12 वर्षों में महिलाओं का सम्मान बढ़ाने का काम किया है। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान, सुकन्या समृद्धि योजना, नारी शक्ति वंदन अधिनियम योजना सहित कई योजनाओं का संचालन महिलाओं के लिए केन्द्र सरकार संचालित कर रही है। देश के सर्वोच्च पद पर एक महिला श्रीमती द्रौपदी मुर्मू जी देश का प्रतिनिधित्व कर रही है। कार्यक्रम में मुख्यमंत्री श्री साय ने नारी शक्ति वंदन महासम्मेलन में आई मातृशक्ति का पुष्पवर्षा कर उनका अभिनंदन किया।

प्रधानमंत्री का एक ही प्रण मातृत्व वंदन का हो सर्वत्र अभिनंदन : सरोज

भाजपा राष्ट्रीय उपाध्यक्ष सुश्री सरोज पांडेय ने कहा है नारी शक्ति वंदन अधिनियम 2023 में पारित हुआ। नारी शक्ति वंदना अधिनियम पहले भारत के संसद में 1996, 1998, 2008 में प्रस्तुत हुआ लेकिन इस अधिनियम का समर्थन किसी ने नहीं किया। सब महिलाओं को सिर्फ वोटर के तौर पर देखते थे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि 2029 में नारी शक्ति वंदन अधिनियम लागू होगा लोकसभा और विधानसभा में 33 प्रतिशत आरक्षण महिलाओं को मिलेगा। इसके लिए विशेष सत्र बुलाया गया है। 2029 में महिलाओं को आरक्षण का लाभ मिलेगा। उन्होंने कहा कि यह एक क्रांतिकारी कदम है। प्रधानमंत्री जी ने कहा कि हम 2047 तक विकसित भारत बनाएंगे और विकसित भारत बनाने के लिए आधी आबादी का सशक्त होना बहुत जरूरी है। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी जी ने महिलाओं को समाज में सम्मान दिया नारीत्व एवं मातृत्व का सम्मान किया। उन्होंने कहा कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान, प्रधानमंत्री आवास योजना में मकान महिला के नाम पर होगा, उज्ज्वला योजना का लाभ महिलाओं के नाम से होगा। लखपति दीदी योजना लायी, ड्रोन उडने की शिक्षा दिलवाई तकनीकी दृष्टि से भी सक्षम बनाने का काम किया। विकसित भारत की तैयारी है भारत के बदलाव में हम 2047 विकसित भारत की ओर बढ़ रही।

नारी शक्ति वंदन अधिनियम देश की लोकतांत्रिक यात्रा में एक निर्णायक कदम होगा द्व लक्ष्मी रजवाड़े

महिला एवं बाल विकास मंत्री श्रीमती लक्ष्मी राजवाड़े ने कहा कि नारी शक्ति अधिनियम देश की माता-बहनों और बेटियों को सशक्त बनाने की योजना हैं। महिलाओं की नीति निर्माण तथा राजनीतिक नेतृत्व में सहभागिता सुनिश्चित करने के लिए देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी और राज्य के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय एवं समस्त मातृशक्ति को बहुत-बहुत बधाई। उन्होंने कहा कि नारी शक्ति अधिनियम केवल एक विधायी दस्तावेज नहीं है बल्कि यह उन करोड़ों महिलाओं के समर्थ उनके संघर्ष और और उनकी अटूट समर्पण का सम्मान है जो घर की चार दिवारी से लेकर अंतरिक्ष के अभियान तक भारत का तिरंगा फहरा रही है। नारी शक्ति वंदन अधिनियम से देश के विकास में महिलाओं की भागीदारी बढ़ेगी। यह नारी शक्ति को सशक्त करने एवं समावेशी बनाने तथा विकसित भारत की ओर यह एक मजबूत और ऐतिहासिक कदम है। नारी शक्ति वंदन अधिनियम से महिलाओं को सम्मान, सुविधा, सुरक्षा और समृद्धि का जीवन मिलेगी। नारी शक्ति वंदन अधिनियम देश के भाग्य को बदलने का काम करेगा। नारी शक्ति वंदन अधिनियम देश की लोकतांत्रिक यात्रा में एक निर्णायक कदम होगा।

दीनदयाल उपाध्याय ऑडिटोरियम, रायपुर में आयोजित नारी शक्ति वंदन कार्यक्रम का दृश्य अत्यंत उत्साह और आत्मीयता से भरा रहा। कार्यक्रम में बड़ी संख्या में पहुँचीं महिलाओं में मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय के साथ सेल्फी लेने को लेकर खासा उत्साह देखने को मिला। महिलाओं की उमंग और उत्साह को देखते हुए मुख्यमंत्री जी ने भी बड़े सहज और स्नेहपूर्ण अंदाज़ में स्वयं उनके मोबाइल लेकर एक-एक के साथ सेल्फी ली। यह दृश्य न केवल उनके सरल स्वभाव को दर्शाता है, बल्कि नारी शक्ति के प्रति उनके सम्मान और अपनत्व की भावना को भी उजागर करता है। कार्यक्रम का संचालन महापौर मीनल चौबे ने किया एवं आभार महासमुंद सांसद रूप कुमारी चौधरी ने किया। इस अवसर पर मंच में वर्णिका शर्मा, विभा अवस्थी, पद्मश्री उषा बारले, नीता डूमरे, श्रीमती आदर्श वर्मा, नीलू त्रिपाठी, इला गुप्ता, सविता देवी जी, भार्वी वैष्णव, शीतल नायक, अस्मिता मक्कड़ सहित विभिन्न समाजिक संगठन की महिला विभूतियां मौजूद रही।

दर्शक दीर्घा में बैठे थे मुख्यमंत्री साय

नारी शक्ति वंदन टाऊन हॉल महासम्मेलन में मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय, बहनों के सम्मान में दर्शक दीर्घा के अंतिम कतार में बैठकर नारी शक्ति वंदन अभियान का अभिनंदन किया। इस दौरान उप मुख्यमंत्री अरूण साव, प्रदेश महामंत्री यशवंत जैन, डॉ. नवीन मार्कण्डेय, सांसद बृजमोहन अग्रवाल, विधायक पुरंदर मिश्रा, जिलाध्यक्ष रमेश सिंह ठाकुर मौजूद रहें । इस दौरान मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने पुष्पवर्षा करके बहनों का अभिनंदन किया। मुख्यमंत्री श्री साय के सुरक्षा में महिला सुरक्षाकर्मी जुटी हुई थी जो नारी शक्ति वंदन महासम्मेलन में चर्चा की विषय बनी रही।इससे पूर्व कार्यक्रम की शुरुआत नारी शक्ति वंदन अधिनियम के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का आभार व्यक्त करने के लिए महिला मोर्चा ने बाइक रैली के माध्यम से आभार व्यक्त किया। बाइक स्कूटी रैली राजधानी रायपुर के आजाद चौक से प्रारंभ हुई जो पंडित दीनदयाल उपाध्याय ऑडिटोरियम में संपन्न हुई। कार्यक्रम के बाद महिला मोर्चा की बहनों ने नारी शक्ति पदयात्रा निकालकर सदन में महिलाओं की 33 प्रतिशत आरक्षण के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को धन्यवाद ज्ञापित किया।

व्यक्तियों को रोजगार चाहने वाला बनने के बजाय रोजगार देने वाला बनाएं : केन्द्रीय मंत्री ओराम

- केंद्रीय जनजातीय मामलों के मंत्री ने (एनएसटीएफडीसी) को जनजातीय उद्यमिता के लिए एक उत्प्रेरक बताया

रायपुर। केंद्रीय जनजातीय मामलों के मंत्री जुएल ओराम ने देश भर में अनुसूचित जनजाति समुदायों को सशक्त बनाने में राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति वित्त एवं विकास निगम (एनएसटीएफडीसी) द्वारा निभाई गई परिवर्तनकारी भूमिका पर प्रकाश डाला है। उन्होंने कहा कि (एनएसटीएफडीसी) का दृष्टिकोण केवल रोजगार सृजन तक ही सीमित नहीं है, बल्कि इसका लक्ष्य उद्यमिता को बढ़ावा देना और व्यक्तियों को रोजगार चाहने वाला बनने के बजाय रोजगार देने वाला बनने में सक्षम बनाना है। नई दिल्ली में (एनएसटीएफडीसी) के 10 अप्रैल 2026 को आयोजित 25 वें स्थापना दिवस को संबोधित करते हुए श्री ओराम ने इस निगम को जनजातीय उद्यमिता के लिए एक उत्प्रेरक बताया।

केंद्रीय जनजाति मंत्री श्री जुएल ओराम द्वारा छत्तीसगढ़ से चयनित लाभार्थी जिला बेमेतरा से किशन ध्रुव ग्राम कुआं (किराना व्यवसाय) एवं धनराज ठाकुर ग्राम गातापार (फोटो स्टूडियो व्यवसाय) सहित छत्तीसगढ़ राज्य अंत्यावसायी सहकारी वित्त एवं विकास निगम के प्रतिनिधि (कार्यपालन अधिकारी) प्रवीण कुमार लाटा का स्वागत किया और (एनएसटीएफडीसी) सावधि ऋण योजना के तहत व्यावसायिक गतिविधियाँ संचालित करने में उनके प्रयासों की सराहना की। मंत्री जी द्वारा लाभार्थियों को प्रशस्ति पत्र एवं स्मृति चिन्ह देकर सम्मानित किया गया।

इसके जन-केंद्रित दृष्टिकोण पर जोर देते हुए

श्री ओराव ने निगम के उस मुख्य उद्देश्य को रेखांकित किया जिसके तहत वह बिना किसी गारंटी के वित्तीय सहायता प्रदान करता है, जिससे जनजातीय लाभार्थियों तक इसकी पहुँच और अधिक व्यापक हो सके। मीडिया से बात करते हुए श्री ओराम ने कहा कि निगम ने लाभार्थियों को 16 लाख से अधिक ऋण वितरित किए हैं और अब तक कुल संवितरण (वितरित राशि) 4,000 करोड़ रुपये से अधिक हो चुका है।

भारत सरकार के जनजातीय कार्य मंत्रालय के अंतर्गत आने वाले राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति वित्त एवं विकास निगम (एनएसटीएफडीसी) ने नई दिल्ली के विश्व युवा केंद्र में अपना 25 वां स्थापना दिवस मनाया। इस कार्यक्रम में जनजातीय कार्य मंत्रालय की सचिव श्रीमती रंजना चोपड़ा, संयुक्त सचिव श्री अनंत प्रकाश पांडे और (एनएसटीएफडीसी) के अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक श्री टी. रौमुआन पाइते, (एनएसटीएफडीसी) के प्रबंधक और मध्य क्षेत्र के प्रमुख श्री विकास रंजन साथ ही निगम के पूर्व अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक और देश भर की राज्य चौनलिंग एजेंसियों के प्रतिनिधियों उपस्थित रहे।

वेदांता पावर प्लांट ब्लास्ट : मृतकों की संख्या 17 पहुंची

घायलों के बेहतर उपचार हेतु कलेक्टर-एसपी मुस्तैद

रायपुर। मंगलवार दोपहर में सक्ती जिले के वेदांता पावर प्लांट में हुए बॉयलर ब्लास्ट में मृतकों की संख्या 17 तक पहुंच गई है तथा अभी भी अनेक मजदूरों की हालत गंभीर बनी हुई है। इस पूरे हादसे के लिए राज्य शासन ने इस हादसे के लिए एक ओर जहां न्यायिक जांच के आदेश दिए है वहीं दूसरी ओर घायल मजदूरों को बेहतर इलाज की जवाबदारी कलेक्टर और पलिस कप्तान को सौंपी है। साथ ही इस पूरी घटना पर उन्हें कड़ी नजर रखने के भी निर्देश भी दिए गए है। शासन ने बिलासपुर कमिश्नर को भी जांच करने को कहा है। घटना एवं घायलों के उपचार को लेकर कलेक्टर श्री अमृत विकास टोपनो तथा पुलिस अधीक्षक श्री प्रफुल्ल ठाकुर से लगातार संपर्क में हैं और आवश्यक दिशा-निर्देश प्रदान कर रहे हैं। सरकारी मुआवजे की घोषणा के बाद वेदांता प्रबंधन ने भी मृतको को 35-35 लाख रुपये मुआवजा और परिवार के एक सदस्य को नौकरी देने का ऐलान किया है। हादसे में जिन मजदूरों की मौत हो गई है उनकी शासन की ओर से उनके नामों की अधिकृत सूची जारी की गई है। मृतकों में छत्तीसगढ़ के 5, बिहार के 2, झारखंड के 3, पश्चिम बंगाल के 5 तथा उत्तर प्रदेश के 2 मजदूर शामिल हैं।

सक्ति जिले के सिंघीतराई स्थित वेदांता प्लांट में बॉयलर फटने से हुए भीषण हादसे के बाद जिला प्रशासन त्वरित रूप से सक्रिय हो गया है।

मुख्यमंत्री श्री विष्णु देव साय घटना एवं घायलों के उपचार को लेकर कलेक्टर श्री अमृत विकास टोपनो तथा पुलिस अधीक्षक श्री प्रफुल्ल ठाकुर से लगातार संपर्क में हैं और आवश्यक दिशा-निर्देश प्रदान कर रहे हैं। स्वास्थ्य मंत्री श्री श्यामबिहारी जायसवाल भी लगातार स्थिति की समीक्षा कर रहे हैं और कलेक्टर के साथ समन्वय बनाए हुए हैं।

घटना की सूचना मिलते ही कलेक्टर, एसपी तथा प्रशासन की टीम तुरंत घटनास्थल पर पहुँची और रेस्क्यू अभियान प्रारंभ किया गया। घायलों को प्राथमिकता के साथ रायगढ़ के फोर्टीस हॉस्पिटल, मेडिकल कॉलेज एवं अपेक्स अस्पताल भेजा गया। गंभीर रूप से घायलों को बेहतर उपचार हेतु रायपुर के कालड़ा अस्पताल रेफर किया गया। प्रशासन द्वारा घटनास्थल को बैरिकेड कर सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए।

कलेक्टर श्री टोपनो ने बताया कि मुख्यमंत्री के निर्देशानुसार घायलों को सर्वोत्तम उपचार उपलब्ध कराने के लिए हरसंभव प्रयास किए जा रहे हैं। मृतकों की पहचान कर उनके परिजनों से संपर्क स्थापित किया जा रहा है। पोस्टमार्टम उपरांत पार्थिव देह को उनके गृहग्राम तक एम्बुलेंस के माध्यम से भेजने और तात्कालिक सहायता राशि उपलब्ध कराने की व्यवस्था सुनिश्चित की गई है।

हादसे में घायल अथवा प्रभावित श्रमिकों को पूर्ण रूप से स्वस्थ होने तक बिना उपस्थिति के वेतन देने पर भी सहमति बनाई गई है। कलेक्टर ने बताया कि मुआवजा राशि को लेकर देर रात तक चर्चा कर सहमति स्थापित की गई है। घटना की मजिस्ट्रियल जांच के आदेश जारी कर दिए गए हैं तथा जांच टीम जल्द ही घटनास्थल का निरीक्षण करेगी। रेस्क्यू कार्य में एसडीआरएफ की टीम भी सक्रिय है।

मुख्यमंत्री द्वारा मृतकों के परिजनों को 5 लाख रुपये तथा घायलों को 50-50 हजार रुपये की सहायता राशि की घोषणा की गई है। इसी प्रकार, प्रधानमंत्री द्वारा मृतकों के परिजनों हेतु 2 लाख रुपये और घायलों के लिए 50 हजार रुपये की अनुग्रह सहायता स्वीकृत की गई है। पुलिस अधीक्षक श्री प्रफुल्ल ठाकुर ने जानकारी दी कि इस हादसे में कुल 36 श्रमिक प्रभावित हुए हैं, जिनमें से 17 की मृत्यु हो चुकी है तथा 19 घायल हैं, जिनका उपचार जारी है।

ई-ऑफिस से परिलक्षित हो रही है श्रेष्ठ कार्य संस्कृति : मुख्य सचिव

मंत्रालय में ई-ऑफिस एवं बायोमेट्रिक अटेंडेंस के लिए श्रेष्ठ कर्मचारियों को किया गया सम्मानित

रायपुर। मुख्य सचिव विकासशील ने आज यहां मंत्रालय महानदी भवन में मंत्रालयीन अधिकारी-कर्मचारियों को ई-ऑफिस पर श्रेष्ठ कार्य करने एवं बायोमेट्रिक उपस्थिति दर्ज कराने के लिए श्रेष्ठ कर्मचारियों को सम्मानित किया। मुख्य सचिव ने कहा है कि मंत्रालय में सभी अधिकारी-कर्मचारी ई-ऑफिस पर बढ़-चढ़कर काम कर रहें हैं। इससे अच्छी कार्य संस्कृति परिलक्षित हो रही है, वहीं पर अधिकारी-कर्मचारी कार्यालयीन समय पर अपनी उपस्थिति दर्ज करा रहें हैं। इससे मंत्रालय में समयबद्धता में सुधार आया है।

मुख्य सचिव ने सभी अधिकारी-कर्मचारियों से कहा है कि वे समय पर मंत्रालय में उपस्थित होकर अपनी बायोमेट्रिक उपस्थिति दर्ज कराएं, जिससे आगामी दिनों में शत् प्रतिशत समयबद्धता देखी जा सकेगी। मुख्य सचिव ने मंत्रालय में ई-फाईल सिस्टम के लिए अधिकारियों-कर्मचारियों को आवश्यकतानुसार प्रशिक्षण की आवश्यकता बतायी। अत- उन्होंने सामान्य प्रशासन विभाग के अधिकारियों को निर्देश दिए कि जिन कर्मचारियों-अधिकारियों को ट्रेनिंग की आवश्यकता है, उन्हें एक व्यापक प्रशिक्षण कार्यक्रम तैयार कर प्रशिक्षित करना सुनिश्चित करें।

मुख्य सचिव ने आज यहां मंत्रालय में विभिन्न श्रेणीयों में ई-ऑफिस, बायोमेट्रिक उपस्थिति और ई-फाईल प्रणाली में उत्कृष्ट प्रदर्शन के लिए सम्मानित किया। इसमें संयुक्त सचिव स्तर के आदिवासी विकास विभाग के प्रथम स्थान पर संयुक्त सचिव भूपेन्द्र कुमार राजपूत, दूसरे स्थान पर लोक निर्माण विभाग के अतिरिक्त सचिव सत्यनारायण वास्तव, तीसरे स्थान पर आदिम जाति विकास विभाग के संयुक्त सचिव अनुपम त्रिवेद्वी को सम्मानित

किया गया। उप सचिव स्तर के अधिकारियों में प्रथम स्थान पर जीएडी के किशोर कुमार भूआर्य, दूसरे स्थान पर वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग के दुर्देशी राम सोनटापर, तीसरे स्थान पर गृह विभाग के कांत वर्मा को सम्मानित किया गया।

अवर सचिव स्तर के अधिकारियों में प्रथम स्थान पर जीएडी के कैलाश कुमार नेताम रहें। द्वितीय स्थान पर वाणिज्य एवं उद्योग विभाग के एम.एल.पवार, तृतीय स्थान पर गृह विभाग के पूरन लाल साहू रहे। अनुभाग स्तर के अधिकारियों में प्रथम स्थान पर जीएडी के नंदकुमार मेश्राम, दूसरे स्थान पर वित्त विभाग के आशीष कुमार शर्मा, तीसरे स्थान पर नगरीय प्रशासन एवं विकास विभाग के मणिराम रात्रे रहे। सहायक अनुभाग अधिकारी स्तर के अधिकारियों में प्रथम स्थान पर मुख्यमंत्री सचिवालय के सूरज कुमार देवांगन रहे। वरिष्ठ सचिवालय सहायक स्तर पर प्रथम स्थान पर खेल एवं युवा कल्याण विभाग श्यामलाल साहू और दूसरे स्थान पर महिला एवं बाल विकास विभाग के दौलत राम वर्मा रहे।

कनिष्ठ सचिवालय सहायक स्तर पर प्रथम स्थान पर जीएडी के रामकुमार सिंह, दूसरे स्थान पर नगरीय प्रशासन एवं विकास विभाग के प्रमोद कुमार, तीसरे स्थान पर जीएडी के सुरेन्द्र कुमार रहे। डाटा एंट्री ऑपरेटर में प्रथम स्थान पर वन विभाग (तकनीकी शाखा) की माया देवांगन, द्वितीय स्थान पर सचिवालय (तकनीकी) के दीपेश कुमार साहू और तृतीय स्थान पर स्कूल शिक्षा विभाग के ललित साहू को सम्मानित किया गया।

बायोमेट्रिक अटेंडेंश के लिए समयबद्धता में उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाले अनुभाग अधिकारी अशीष कुमार अग्रवाल, उप सचिव मती क्लेमेन्टीना लकड़ा, सहायक अनुभाग अधिकारी सु कांती सूर्यवंशी, कनिष्ठ सचिवालय सहायक मुकेश राम प्रधान, सहायक अनुभाग अधिकारी पवन कुमार साहू, अवर सचिव राजीव कुमार झाड़े, अनुभाग अधिकारी राजेश कुमार जैन, वरिष्ठ सचिवालय सहायक राजेश कुमार टोप्पो, सहायक अनुभाग अधिकारी शार्दूल पटेल, वरिष्ठ सचिवालय सहायक सूरज कुमार साहू, वरिष्ठ सचिवालय सहायक तारा कुजूर, सहायक अनुभाग अधिकारी विनोद कुमार अथंकर को मुख्य सचिव ने सम्मानित किया।

कार्यालय कलेक्टर, जिला दक्षिण बस्तर दंतेवाड़ा (छ.ग.)
(खेल एवं युवा कल्याण विभाग)
परिशिष्ट-3
(नियम 4.4.2)
(तिथि संशोधित सूचना)
(तृतीय निविदा सूचना का प्रारूप)

क्रमांक / 22 / खेल-युवा/खेल परिसर/2026 दन्तेवाड़ा, दिनांक 15/04/2026

कार्यालयीन संक्षिप्त निविदा क्रमांक / 1040/ खेल-युवा/खेल परिसर / 2026 दन्तेवाड़ा दिनांक 12.03.2026 द्वारा एकलव्य खेल परिसर जावंगा, विकास खण्ड गीदम, जिला दक्षिण बस्तर दन्तेवाड़ा में शिक्षण सत्र 2026-27 हेतु पंजीकृत फर्मो/आपूर्तिकर्ताओं से किराना सामग्री, सब्जी-फल, बेकरी उत्पाद, दूग्ध उत्पाद, मांसाहार सामग्री की आपूर्ति हेतु पृथक-पृथक सील बंद निविदाएँ आमंत्रित की गई थी। प्रथम एवं द्वितीय निविदा में प्रर्याप्त निविदा प्राप्त नहीं होने के कारण तृतीय निविदा आमंत्रित किया जा रहा है। निविदा प्रपत्र एवं निविदा से संबंधित विस्तृत जानकारी तथा नियम व शर्तें जिले के वेबसाईट www.dantewada.gov.in पर देखी तथा दिनांक 21 अप्रैल 2026 तक डाउनलोड की जा सकती है, निविदा फीस रूपये 1,000.00 (शब्दों में एक हजार रूपये) का डिमांड ड्राफ्ट/ बैंक ड्राफ्ट निविदा के साथ जमा करना होगा । शेष शर्तें पूर्ववत रहेंगी ।

निविदा प्रपत्र डाउनलोड करने की अंतिम तिथि	21 अप्रैल 2026 समय शाम 5.00 बजे तक
निविदा प्रपत्र जमा करने की अंतिम तिथि	21 अप्रैल 2026 समय अपरान्ह 12.00 बजे तक
निविदा प्रपत्र खोलने की तिथि	22 अप्रैल 2026 समय अपरान्ह 4.00 बजे

स्थान कार्यालय कलेक्टर (खेल एवं युवा कल्याण विभाग) दन्तेवाड़ा (मुख्य कार्यपालन अधिकारी एवं जिला खेल अधिकारी महोदय द्वारा अनुमोदित)

सहायक खेल अधिकारी
खेल एवं युवा कल्याण विभाग दन्तेवाड़ा (छ.ग.)

जी-262700193/4

नारी शक्ति वंदन शंका व संग्राम

विनोद कुमार सिंह

विश्व का सबसे बड़े लोकतंत्र भारत वर्तमान परिपेक्ष में एक ऐसे संक्रमण काल से गुजर रहा है,जहाँ सामाजिक परिवर्तन और राजनीतिक रणनीति एक-दूसरे में गुंथकर नई दिशा तय कर रहे हैं। नारी शक्ति वंदन का उभरता विमर्श, संसद का तीन दिवसीय विशेष सत्र और इसके इर्द-गिर्द तेज होती राजनीतिक हलचल इस बात का संकेत है कि देश की आधी आबादी अब केवल चर्चा का विषय नहीं, बल्कि सत्ता-समीकरण का केंद्र बन चुकी है। यह वह काल है, जहाँ नारी शक्ति का प्रश्न भावनात्मक अपील से आगे बढ़कर ठोस राजनीतिक और संवैधानिक निर्णयों की कसौटी पर खड़ा है। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी द्वारा ऐतिहासिक विज्ञान भवन में दिए गए वक्तव्यों ने इस बहस को नई गति दी है। केन्द्र सरकार इसे ऐतिहासिक निर्णय की दिशा में निर्णायक कदम बता रही है, वहीं कांग्रेस व विपक्षी राजनीतिक दल इसे समय-प्रबंधन और राजनीतिक लाभ के नजरिये से देख रहा है। परिणाम स्वरूप यहीं से सत्ता और विपक्ष के बीच वह टकराव स्पष्ट रूप से उभरता है, जो भारतीय लोकतंत्र की पहचान भी और उसकी शक्ति भी है। भारतीय जनता पार्टी और राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन इस पूरे विमर्श को महिला सशक्तिकरण की दीर्घकालिक नीति का स्वाभाविक विस्तार मानते हैं। उनका तर्क है कि पिछले वर्षों में महिलाओं को आर्थिक, सामाजिक और स्वास्थ्य के स्तर पर मजबूत करने के लिए जो योजनाएं लागू की गईं,वे अब राजनीतिक प्रतिनिधित्व के रूप में परिणत होने जा रही हैं। जनधन योजना के माध्यम से बैंकिंग पहुँच, उज्ज्वला योजना के तहत गैस कनेक्शन, स्वयं सहायता समूहों के जरिए आर्थिक सशक्तिकरण और लखपति दीदी जैसी पहलों को इस परिवर्तन की पृष्ठभूमि के रूप में प्रस्तुत किया जा रहा है। उनका यह तर्क दिया जा रहा है कि जब आधार तैयार हो चुका है, तब राजनीतिक भागीदारी को बढ़ाना स्वाभाविक अगला कदम है। वहीं इसके विपरीत कांग्रेस और अन्य विपक्षी दल इस पूरी प्रक्रिया को अधूरा और प्रश्नों से घिरा हुआ मानते हैं। उनका कहना है कि यदि महिलाओं को वास्तविक सशक्तिकरण देना है, तो आरक्षण के भीतर भी सामाजिक न्याय सुनिश्चित किया जाना चाहिए, ताकि पिछड़े वर्गों, दलितों और आदिवासी समुदायों की महिलाओं को भी समान अवसर मिल सके। इसके साथ ही वे इस बात पर भी सवाल उठाते हैं कि क्रियान्वयन को भविष्य की समयसीमा से क्यों जोड़ा गया है। विपक्ष के अनुसार, यह देरी कहीं न कहीं इस मुद्दे को चुनावी लाभ के लिए उपयोग करने की रणनीति को दर्शाती है। यह टकराव केवल विधायी प्रक्रिया का नहीं, बल्कि राजनीतिक नैरेटिव का संघर्ष बन चुका है। एक ओर सत्ता पक्ष इसे उपलब्धियों की श्रृंखला के रूप में प्रस्तुत कर रहा है, तो दूसरी ओर विपक्ष इसे अधूरी प्रतिबद्धता और राजनीतिक गणित का परिणाम बताने में लगा है। इस पूरे परिदृश्य में सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि दोनों पक्ष नारी शक्ति को अपने-अपने तरीके से केंद्र में रख रहे हैं, जो इस बात का प्रमाण है कि महिलाओं का मुद्दा अब भारतीय राजनीति में निर्णायक बन चुका है। अगर हम इस पहलू के संभावित लाभों की चर्चा करें तो यह स्पष्ट है कि महिलाओं की बढ़ती भागीदारी से लोकतंत्र अधिक संतुलित और समावेशी बन सकता है। पंचायत स्तर पर महिलाओं की सक्रिय भूमिका पहले ही यह साबित कर चुकी है कि जब उन्हें अवसर मिलता है, तो वे विकास की प्राथमिकताओं को नई दिशा देती हैं। जल, स्वास्थ्य, शिक्षा और पोषण जैसे विषयों पर उनका दृष्टिकोण अधिक संवेदनशील और व्यावहारिक होता है। यदि यही अनुभव संसद और विधानसभाओं तक पहुंचता है, तो नीतियों में व्यापक बदलाव संभव है।

बिहार में भाजपा का युग: एक नया राजनीतिक अध्याय

सौरभ वार्ष्णेय

राजनीति भी ऐसा मौसम है पता नहीं कब क्या कुछ हो जाये ? ऐसे ही बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का कुछ नहीं कहा जा सकता कब उनका फैसला बदल जाये। वैसे भी बिहार की राजनीति लंबे समय तक जातीय समीकरणों, क्षेत्रीय दलों और गठबंधन की जटिलताओं के इर्द-गिर्द घूमती रही है। लेकिन हाल के वर्षों में भारतीय जनता पार्टी का उभार राज्य की राजनीति में एक नए अध्याय का संकेत दे रहा है। यह बदलाव केवल सत्ता परिवर्तन तक सीमित नहीं है, बल्कि राजनीतिक सोच, विकास के एजेंडे और नेतृत्व शैली में भी परिवर्तन का द्योतक है। ऐसे में बिहार में भारतीय जनता पार्टी ने सम्राट चौधरी को विधायक दल का नेता चुना जाना और बिहार के वह मुख्यमंत्री पद की शपथ लेंगे।

बिहार में भारतीय जनता पार्टी का विस्तार कोई अचानक हुई घटना नहीं है। यह एक लंबी रणनीतिक यात्रा का परिणाम है, जिसमें संगठन की मजबूती, जमीनी स्तर पर कार्यकर्ताओं का नेटवर्क और केंद्र की नीतियों का प्रभाव शामिल है। नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में केंद्र सरकार की योजनाओं—जैसे उज्ज्वला, आयुष्मान भारत और पीएम आवास योजना—ने राज्य के ग्रामीण और गरीब वर्गों में भाजपा की स्वीकार्यता बढ़ाई है। इससे पार्टी को एक मजबूत जनाधार बनाने में मदद मिली है।

हालांकि, बिहार की राजनीति में नीतीश कुमार जैसे अनुभवी नेता और राष्ट्रीय जनता दल जैसे प्रभावशाली दल अभी भी मजबूत स्थिति में हैं। ऐसे में भाजपा का यह उभार एक प्रतिस्पर्धात्मक राजनीतिक वातावरण तैयार करता है, जहां सत्ता की लड़ाई और अधिक दिलचस्प और जटिल हो गई है। भाजपा के सामने सबसे बड़ी चुनौती यह है कि वह अपने विकास के वादों को जमीन पर उतारे। बिहार आज भी बेरोजगारी, शिक्षा और स्वास्थ्य जैसी बुनियादी समस्याओं से जूझ रहा है। भाजपा को इन क्षेत्रों में ठोस सुधार करना होगा। यह उसके लिए एक स्थायी राजनीतिक आधार बनाने का अवसर हो सकता है। इसके अलावा, सामाजिक समरसता और जातीय संतुलन बनाए रखना भी भाजपा के लिए एक महत्वपूर्ण कसौटी होगी। बिहार की सामाजिक संरचना बेहद संवेदनशील है, जहां

छोटी-सी राजनीतिक चूक भी बड़े सामाजिक तनाव का कारण बन सकती है। बिहार में भाजपा का उभरता हुआ युग एक परिवर्तनशील दौर का प्रतीक है। यह देखना दिलचस्प होगा कि यह बदलाव राज्य को विकास और स्थिरता की ओर ले जाता है या फिर यह केवल सत्ता के नए समीकरणों तक ही सीमित रह जाता है। आने वाले समय में बिहार की राजनीति किस दिशा में जाएगी, यह न केवल राज्य बल्कि पूरे देश की राजनीतिक धारा को भी प्रभावित करेगा।

बिहार में सम्राट चौधरी का मुख्यमंत्री बनना

ऐसे में भाजपा ने सम्राट चौधरी को विधायक दल का नेता चुना है तो यह तय है कि सम्राट चौधरी मुख्यमंत्री बनते ही केवल नेतृत्व परिवर्तन नहीं बल्कि एक व्यापक राजनीतिक संदेश और रणनीतिक बदलाव का संकेत होगा। सबसे पहले, यह कदम भारतीय जनता पार्टी के उस प्रयास के रूप में देखा जाएगा, जिसमें वह बिहार में अपनी स्वतंत्र पहचान को और मजबूत करना चाहती है। लंबे समय तक नीतीश कुमार के नेतृत्व में गठबंधन की राजनीति करने के बाद, भाजपा अब अपने चेहरे के साथ चुनावी मैदान में उतार दिया है। सम्राट चौधरी का सामाजिक आधार भी इस चर्चा को महत्वपूर्ण बनाता है। वे पिछड़े वर्ग से आते हैं, जो बिहार की राजनीति में निर्णायक भूमिका निभाता है। ऐसे में उनका मुख्यमंत्री बनना सामाजिक प्रतिनिधित्व के नए समीकरण साध सकता है और भाजपा को उन वर्गों में और गहराई तक पहुंचाने में मदद कर सकता है, जहां अब तक अन्य दलों का प्रभाव रहा है। हालांकि, यह रास्ता आसान नहीं होगा। बिहार जैसे राज्य में प्रशासनिक अनुभव, गठबंधन संतुलन और जमीनी पकड़ बेहद महत्वपूर्ण होती है। लालू प्रसाद यादव और तेजस्वी यादव जैसे विपक्षी नेताओं की मजबूत राजनीतिक पकड़ के बीच सम्राट चौधरी को अपनी स्वीकार्यता साबित करनी होगी। इसके अलावा, यह भी देखना दिलचस्प होगा कि क्या भाजपा इस बदलाव के जरिए युवाओं और नए मतदाताओं को आकर्षित कर पाती है या नहीं। क्योंकि आज की राजनीति में केवल जातीय समीकरण ही नहीं, बल्कि विकास, रोजगार और सुशासन भी उतने ही अहम मुद्दे बन चुके हैं। सम्राट चौधरी का मुख्यमंत्री बनना बिहार की राजनीति में एक नए अध्याय की शुरुआत हो सकता है, लेकिन इसकी सफलता इस बात पर निर्भर करेगी कि वे उम्मीदों पर कितना खरे उतरते हैं। यह केवल सत्ता परिवर्तन नहीं, बल्कि विश्वास और प्रदर्शन की एक बड़ी परीक्षा होगी।

अगर हम सम्राट चौधरी के राजनीतिक करियर की बात करे तो बिहार की समकालीन राजनीति में तेजी से उभरते नेतृत्व का उदाहरण माना जाता है। उनका सफर छात्र राजनीति से लेकर राज्य की सत्ता के शीर्ष तक पहुंचने का रहा है।

सम्राट चौधरी का जन्म बिहार के एक राजनीतिक परिवार में हुआ। उनके पिता शकुनी चौधरी भी राज्य की राजनीति में सक्रिय रहे। सम्राट चौधरी ने अपने राजनीतिक करियर की शुरुआत छात्र राजनीति से की और धीरे-धीरे मुख्यधारा की राजनीति में मजबूत पहचान बनाई। सम्राट चौधरी ने अपने करियर में कई राजनीतिक दलों के साथ काम किया। सम्राट चौधरी बिहार सरकार में मंत्री भी रह चुके हैं और संगठन में उनकी पकड़ मजबूत मानी जाती है। बीजेपी में उन्होंने प्रदेश अध्यक्ष जैसे महत्वपूर्ण पद संभाले, जिससे उनकी राजनीतिक स्थिति और मजबूत हुई। राजनीतिक परिस्थितियों और पार्टी के रणनीतिक निर्णयों के चलते सम्राट चौधरी को बिहार की राजनीति में प्रमुख चेहरा बनाया गया। मुख्यमंत्री बने तो यह उनके लंबे राजनीतिक अनुभव, संगठनात्मक कौशल और सामाजिक समीकरणों को साधने की क्षमता का परिणाम माना जाएगा।

उनकी राजनीतिक विशेषताएं। ओबीसी (पिछड़ा वर्ग) नेतृत्व का प्रतिनिधित्व करते हैं। आक्रामक और स्पष्ट वक्ता सहित संगठन और जनाधार दोनों पर पकड़ रखते हैं।

सम्राट चौधरी का करियर यह दिखाता है कि बिहार की राजनीति में लगातार सक्रियता, रणनीति और समय के अनुसार निर्णय लेना कितना महत्वपूर्ण है। वे आज राज्य की राजनीति में एक महत्वपूर्ण और प्रभावशाली नेता के रूप में स्थापित हो चुके हैं। 2026 के अनुसार भाजपा के 16 वें राज्य के मुख्यमंत्री होंगे सम्राट चौधरी।

नीतीश कुमार युग का अंत

नीतीश कुमार का नाम बिहार की राजनीति में एक लंबे समय तक स्थिरता, सुशासन और सामाजिक संतुलन के प्रतीक के रूप में लिया जाता रहा है। लगभग दो दशकों तक विभिन्न चरणों में सत्ता संभालने वाले नीतीश कुमार ने राज्य की राजनीति को नई दिशा दी। लेकिन अब बदलते राजनीतिक समीकरण और नेतृत्व की नई मांगों के बीच उनके युग के अंत की चर्चा तेज हो रही है। नीतीश कुमार का उदय ऐसे समय में हुआ जब बिहार राजनीतिक अस्थिरता और पिछड़ेपन की छवि से जूझ रहा था। उन्होंने सड़कों, शिक्षा, स्वास्थ्य और कानून-व्यवस्था के क्षेत्र में उल्लेखनीय सुधार किए। सुशासन बाबू के रूप में उनकी पहचान बनी, जो प्रशासनिक दक्षता और विकास के प्रति प्रतिबद्धता का प्रतीक थी। हालांकि, समय के साथ उनकी राजनीतिक रणनीतियों में बार-बार बदलाव—कभी के साथ गठबंधन, तो कभी किसी के साथ—ने उनकी विश्वसनीयता पर सवाल खड़े किए। गठबंधनों की इस राजनीति ने उन्हें सत्ता में बनाए रखा, लेकिन जनता के एक वर्ग में असमंजस और असंतोष भी पैदा किया। आज बिहार की राजनीति में युवा नेतृत्व, नई सोच और स्पष्ट वैचारिक दिशा की मांग बढ़ रही है। ऐसे में नीतीश कुमार का नेतृत्व पहले जैसा प्रभावशाली नहीं दिखता। उनकी उम्र, बदलते राजनीतिक हालात और लगातार बदलते समीकरण इस बात का संकेत देते हैं कि राज्य अब एक नए नेतृत्व की ओर बढ़ रहा है। यह भी सच है कि किसी भी नेता का राजनीतिक जीवन स्थायी नहीं होता। हर युग का एक अंत होता है और एक नई शुरुआत भी। नीतीश कुमार के योगदान को नकारा नहीं जा सकता—उन्होंने बिहार को एक मजबूत आधार दिया, जिस पर आगे का विकास संभव है। नीतीश युग का अंत केवल एक व्यक्ति का राजनीतिक अवसान नहीं, बल्कि बिहार की राजनीति में एक नए अध्याय की शुरुआत का संकेत है। आने वाला समय यह तय करेगा कि यह परिवर्तन राज्य के लिए कितना सकारात्मक साबित होता है।

पुराण दिग्दर्शन ....

सन्देहाभासनिकारणाध्यायः (नौवां अध्याय)

(गतांक से आगे...)

(ङ) अथ (त्वष्टा) यदब्रवीदिन्द्रशत्रुर्वर्द्धस्वेति तस्मा-दुहैनमिन्द्र एव जघानाथ यद्ध शश्वदवक्ष्यदिन्द्रस्य शत्रुर्वर्द्धस्वेति शश्वदुह स एवेन्द्रमहनिष्यत् ।

(शतपथ 1 ।6 ।3 ।10)

(च) एष ह वै साक्षान्मृत्युर्यद् ब्रह्महत्या ।

(शतपथ 13 ।3 ।5 ।3)

(छ) अष्टापदी चतुरक्षी चतुःश्रोत्रा चतुर्हनुः।

द्वयास्या द्विजिह्वा भूत्वा सा राष्ट्रमवधूनुते ब्रह्मज्यस्य।।

(अथर्व 5 ।16 ।7)

(ज) तरति सर्व पाप्मानं तरति ब्रह्महत्यां योऽश्वमेधेन यजते।

(शतपथ 13 ।3 ।1 ।1)

(झ) इन्द्रो दधोचो अस्थिभिर्वृत्राण्यप्रतिष्कुत जघान नवतीर्नव।

(अथर्व 20 ।41 ।1)

अर्थात् (क) इन्द्र ने मृत्यु के महान् साधनभूत वज्र से अत्यन्त प्रवृद्ध वृत्रासुर को मार कर कन्धों से रहित कर दिया। वज्र से कटे हुये वृत्रासुर के अङ्ग वृक्षों के टहनों के भाँति (गिरे) (इसतरह) अहि = पाँवों के कट जाने पर वह असुर पृथ्वी पर (सदा के लिये) सो गया। (ख) वृत्रासुर इस समस्त भूमण्डल को घेर कर सो गया, क्योंकि उसने द्यो से पृथ्वी तक का सब प्रदेश ढक दिया था इसलिये उसे वृत्र कहते हैं । (ग) यह जो पर्वत और पत्थर हैं, यह सब वृत्र का शरीर हैं (घ) इन्द्र ने वृत्र पर वज्र का प्रहार किया (ङ.) [वृत्र के पिता] त्वष्टा ने जो बार 2 इन्द्रशत्रुर्वर्द्धत्व ऐसा (आद्युदात्त) बोला तो (स्वर-व्यत्यय के पाप से) इन्द्र ने ही वृत्र को मार डाला। यदि इन्द्रस्य शत्रुर्वर्द्धस्व- ऐसा (अल्तोदात्त) निरन्तर कहा जाता तो वह वृत्र ही इन्द्र को मार डालता।

क्रमशः ...

हाथी बचाओ दिवस

सुनील कुमार महला

पृथ्वी के सबसे बुद्धिमान, विशालकाय और सामाजिक जीवों में से एक हाथी को 'पारिस्थितिकी तंत्र का इंजीनियर' कहा जाता है। इनके संरक्षण के प्रति जागरूकता फैलाने और इनके घटते अस्तित्व को बचाने के उद्देश्य से प्रतिवर्ष 16 अप्रैल को 'हाथी बचाओ दिवस' मनाया जाता है। यहां पाठकों को जानकारी देना चाहूंगा कि वर्तमान समय में हाथी अनेक गंभीर खतरों का सामना कर रहे हैं, जिनमें अवैध शिकार (विशेषकर हाथीदांत के लिए), वनों की कटाई, प्राकृतिक आवास का विनाश, मानव-हाथी संघर्ष तथा जलवायु परिवर्तन प्रमुख हैं। हाथी जंगलों, घासभूमियों और जल स्रोतों के संतुलन में अत्यंत महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं, इसलिए उनका संरक्षण पारिस्थितिकी तंत्र के लिए अनिवार्य है।

पाठकों को जानकारी देता चलूं कि हाथी पारिस्थितिकी तंत्र(इको-सिस्टम) को कई तरीकों से समृद्ध करते हैं।मसलन, वे फलों और पौधों को खाकर लंबी दूरी तय करते हैं और अपने मल(लीद) के माध्यम से बीजों का प्रसार करते हैं, जिससे नए पौधों का विकास होता है और वनों का विस्तार बना रहता है। घने जंगलों में चलते समय वे टहनियाँ और झाड़ियाँ तोड़ते हैं, जिससे वन का घनत्व कम होता है और सूर्य का प्रकाश जमीन तक पहुँचता है, जिससे छोटे पौधों और घास को बढ़ने का अवसर मिलता है और जैव विविधता बनी रहती है। सूखे के समय हाथी अपनी सूंड और पैरों से जमीन खोदकर पानी निकालते हैं, जिससे बने गड्ढे अन्य जानवरों के लिए भी जल स्रोत बन जाते हैं। इसके अलावा हाथियों के चलने से प्राकृतिक मार्ग (कॉरिडोर) बनते हैं, जो अन्य जीवों की आवाजाही को सरल बनाते हैं। उनका मल मिट्टी को पोषक तत्व प्रदान कर उसे उर्वर बनाता है और पौधों की वृद्धि में सहायक होता है।

बहरहाल, यदि हम यहां पर हाथियों से संबंधित आंकड़ों की बात करें तो भारत में हाथियों की उपस्थिति मुख्य रूप से कर्नाटक, असम, केरल, तमिलनाडु और ओडिशा में पाई जाती है। प्रोजेक्ट एलिफेंट (2017) के अनुसार भारत में लगभग 29,000-30,000 जंगली हाथियों का अनुमान था, जबकि 2025 की नवीनतम डीएनए आधारित गणना के अनुसार इनकी संख्या लगभग 22,446 आंकी गई है। डीएनए आधारित गणना का अर्थ है जानवरों की संख्या का अनुमान उनके आनुवंशिक पदार्थ (जेनेटिक मैटेरियल) के आधार पर लगाना, न कि केवल प्रत्यक्ष रूप से देखकर गिनना। विश्व में हाथियों की दो प्रमुख प्रजातियाँ पाई जाती हैं-अफ्रीकी हाथी जिनकी संख्या लगभग 4-5 लाख है तथा एशियाई हाथी जिनकी संख्या लगभग 50,000-60,000 के बीच है। भारत विश्व के कुल एशियाई हाथियों का 60% से अधिक हिस्सा रखता है। हाल फिलहाल, यहां यह कहना ग़लत नहीं होगा कि आज के समय में मानव-हाथी संघर्ष वर्तमान समय की एक गंभीर पर्यावरणीय और सामाजिक समस्या बन चुका है। इसका मुख्य कारण वनों का सिकुड़ना, कृषि विस्तार, मानव बस्तियों का बढ़ना और हाथियों के प्राकृतिक मार्गों (कॉरिडोर) का टूटना है। इसके परिणामस्वरूप हर वर्ष औसतन 500 से अधिक लोगों की मृत्यु हाथियों के हमलों में होती है।

स्थायी शांति के लिए दोनों पक्षों को कुछ समझौते करने पड़ेंगे

आनंद कुमार

इस्लामाबाद में संयुक्त राज्य अमेरिका और ईरान के बीच हालिया वार्ता एक बार फिर यह स्पष्ट करती है कि आज की खंडित वैश्विक व्यवस्था में कूटनीति की सीमाएं कितनी गहरी हो चुकी हैं। जिस बातचीत को शुरुआत में एक संभावित बड़ी सफलता के रूप में देखा जा रहा था—जिसे पाकिस्तान ने आयोजित किया और चीन तथा कुछ खाड़ी देशों का समर्थन प्राप्त था—वह अंततः विफलता में समाप्त हुई। लेकिन इस विफलता के पीछे एक जटिल कहानी छिपी है, जो बदलते भू-राजनीतिक समीकरणों, प्रतिस्पर्धी रणनीतिक हितों और स्थायी शांति की राह में मौजूद संरचनात्मक बाधाओं को उजागर करती है।

पाकिस्तान द्वारा मध्यस्थ की भूमिका निभाने का प्रयास उसकी महत्वाकांक्षा और आवश्यकता, दोनों को दर्शाता है। आंतरिक राजनीतिक अस्थिरता और आर्थिक संकट से जूझ रहे इस देश के लिए कूटनीति अंतरराष्ट्रीय मंच पर अपनी प्रासंगिकता पुनः स्थापित करने का एक साधन है। उच्च-स्तरीय वार्ताओं की मेजबानी करके और बैकचैनल संवाद को प्रोत्साहित कर इस्लामाबाद ने वैश्विक ध्यान आकर्षित करने में सफलता तो हासिल की, लेकिन ठोस परिणाम देने में असफल रहा। यह भूमिका उसके लिए नई नहीं है। 1971 में अमेरिकाङ्चीन निकटता के दौरान हेनरी किसिंजर की गुप्त बीजिंग यात्रा, जिसे याह्या खान ने संभव बनाया, और जिसने आगे चलकर रिचर्ड निक्सन की ऐतिहासिक चीन यात्रा का मार्ग प्रशस्त किया, इसका प्रमुख उदाहरण है। इसके अलावा, पाकिस्तान ने अमेरिका और तालिबान के बीच वार्ताओं में भी मध्यस्थ की भूमिका निभाई थी।

हालांकि, इस बार स्थिति कहीं अधिक जटिल है। शीत युद्ध के दौर की अपेक्षाकृत स्पष्ट रणनीतिक पुनर्संरचना के विपरीत, अमेरिका-ईरान संघर्ष क्षेत्रीय प्रतिद्वंद्विताओं, वैचारिक टकरावों और सुरक्षा चिंताओं के जटिल जाल में उलझा हुआ है। यहां तक कि संघर्ष विराम की परिभाषा भी सभी पक्षों के लिए अलग-अलग है। ऐसे परिदृश्य में पाकिस्तान की

भूमिका सीमित रहना तय था—वह एक सुगमकर्ता (facilitator) तो बन सकता था, लेकिन निर्णायक मध्यस्थ नहीं।

इस्लामाबाद में हुई वार्ता की विफलता, जिसमें जेडी वेंस को लंबी बातचीत के बाद लौटना पड़ा, मुख्यतः ईरान के परमाणु कार्यक्रम को लेकर गहरे मतभेदों का परिणाम थी। अमेरिका के लिए यह सुनिश्चित करना कि ईरान परमाणु हथियार न बनाए, एक अनिवार्य शर्त है। वहीं, ईरान इन मांगों को अपनी संप्रभुता और रणनीतिक स्वतंत्रता पर हमला मानता है। यही मूलभूत असहमति वार्ता को आगे बढ़ने से रोकती है। इसके अलावा, तेहरान द्वारा रखी गई अन्य शर्तें—जैसे होर्मुज जलडमरूमध्य पर नियंत्रण, जमे हुए धन की रिहाई और युद्ध क्षतिपूर्ति—स्थिति को और जटिल बनाती हैं।

होर्मुज जलडमरूमध्य इस पूरे संकट का केंद्र है। यह मार्ग वैश्विक ऊर्जा आपूर्ति का लगभग पांचवां हिस्सा वहन करता है, और इसका बंद होना अंतरराष्ट्रीय अर्थव्यवस्था पर सीधा प्रभाव डालता है। संघर्ष के दौरान इसके अवरुद्ध होने से तेल की कीमतों में तेज वृद्धि हुई और वैश्विक आर्थिक अस्थिरता की आशंकाएं बढ़ गईं। अस्थायी संघर्ष विराम ने इस मार्ग के फिर से खुलने की उम्मीद जगाई थी, लेकिन व्यापक समझौते के अभाव में यह अनिश्चित बना हुआ है। इससे स्पष्ट होता है कि क्षेत्रीय संघर्ष अब वैश्विक आर्थिक स्थिरता से गहराई से जुड़े हुए हैं।

इस परिप्रेक्ष्य में चीन की भूमिका भी महत्वपूर्ण है, हालांकि अक्सर उसे गलत तरीके से समझा जाता है। बीजिंग के 'सक्रिय प्रयास' वास्तव में भू-राजनीतिक महत्वाकांक्षा से अधिक आर्थिक व्यावहारिकता से प्रेरित हैं। एक निर्यात-आधारित अर्थव्यवस्था होने के कारण, जो खाड़ी क्षेत्र से ऊर्जा आयात पर निर्भर है, चीन के लिए क्षेत्रीय स्थिरता अत्यंत महत्वपूर्ण है। ऊर्जा कीमतों में वृद्धि और व्यापार मार्गों में बाधा उसके आर्थिक विकास के लिए गंभीर चुनौती बन सकती है।

इसके बावजूद, चीन ने प्रत्यक्ष मध्यस्थ की भूमिका निभाने से परहेज किया है। उसने संवाद को प्रोत्साहित करने, पाकिस्तान जैसे देशों का समर्थन करने और किसी एक पक्ष के साथ खुलकर खड़े होने से बचने की रणनीति अपनाई है। यह दृष्टिकोण चीन की व्यापक विदेश नीति को दर्शाता है। वह कूटनीतिक पहलों को समर्थन देने और सुविधा प्रदान करने के लिए तैयार रहता है, लेकिन किसी भी पक्ष पर दबाव डालने से बचता है। ईरान और सऊदी अरब के बीच संबंधों की बहाली में उसकी सफलता एक अलग परिस्थिति का परिणाम थी, जहां सभी पक्षों के हितों में कुछ समानता थी। वर्तमान संकट में ऐसा कोई साझा आधार नहीं दिखता।

पाकिस्तान के लिए यह घटनाक्रम अवसर और सीमा, दोनों को उजागर करता है। एक ओर, उसने अमेरिका और ईरान जैसे प्रतिद्वंद्वियों को बातचीत की मेज पर लाकर अपनी कूटनीतिक क्षमता का प्रदर्शन किया है। दूसरी ओर, ठोस परिणाम न निकाल पाने से यह भी स्पष्ट हो गया कि उसकी प्रभाव क्षमता सीमित है। बिना पर्याप्त आर्थिक या सैन्य शक्ति के, वह केवल संवाद की सुविधा दे सकता है, उसे दिशा नहीं दे सकता। इस पूरे घटनाक्रम का निहितार्थ यह है कि वैश्विक कूटनीति का स्वरूप बदल रहा है। जैसे-जैसे बड़ी शक्तियां अपनी-अपनी प्रतिस्पर्धाओं में उलझी हैं, मध्य शक्तियों के लिए अवसर बढ़ रहे हैं। पर यह जरूरी नहीं कि वे संघर्षों का समाधान भी कर सकें। अमेरिकाङ्कईरान वार्ता यह दिखाती है कि बातचीत की शुरुआत कराना एक बात है, और स्थायी समाधान निकालना बिल्कुल अलग।

भारत की भूमिका इस संदर्भ में उल्लेखनीय है। नई दिल्ली ने संतुलित और सतर्क रुख अपनाया है, जिससे वह सभी पक्षों के साथ अपने संबंध बनाए रखने में सफल रहा है। यह रणनीति उसे अनावश्यक जोखिम से बचाती है और बहुध्रुवीय विश्व व्यवस्था में उसके हितों की रक्षा करती है। अंततः, इस्लामाबाद की वार्ता की विफलता को एक अलग घटना के रूप में नहीं देखा जाना चाहिए, बल्कि इसे एक व्यापक प्रवृत्ति के रूप में समझना होगा। अमेरिका और ईरान के बीच गहरे अविश्वास, क्षेत्रीय राजनीति और वैश्विक आर्थिक दबावों के कारण त्वरित समाधान की संभावना कम है। संघर्ष विराम अस्थायी राहत दे सकता है, लेकिन स्थायी शांति के लिए दोनों पक्षों को अपनी कठोर स्थितियों से पीछे हटना होगा, जो फिलहाल कठिन प्रतीत होता है।

इस पूरे घटनाक्रम से यह स्पष्ट है कि पाकिस्तान ने भले ही खुद को एक कूटनीतिक मंच के रूप में पुनः स्थापित किया हो, लेकिन प्रभावी मध्यस्थ बनने की उसकी राह अभी लंबी है। चीन के लिए यह संकट उसके आर्थिक हितों की प्राथमिकता को रेखांकित करता है। और वैश्विक समुदाय के लिए यह एक चेतावनी है कि आज की दुनिया में शांति स्थापित करना पहले से कहीं अधिक जटिल और अनिश्चित हो गया है।

आज का इतिहास

1889 दूसरे विश्व युद्ध की त्रासदी के बीच दुनिया को हंसाने वाले चार्ली चैपलिन का जन्म।
1894 मैनचेस्टर सिटी फुटबॉल क्लब इंग्लैंड में बनाया गया।
1912 अमेरिकन हैरियट क्वेम्बी एक ऐसी महिला बन गई जो इंग्लिश चैनल एक्रॉसिस्ट की उड़ान भरने वाली थी।
1917 व्लादिमीर लेनिन स्विट्जरलैंड से पेत्रोग्राद लौटे, और रूस में बोल्शेविक आंदोलन में शामिल हो गए।
1919 पोलिश-सोवियत युद्ध-पोलिश सेना ने आधुनिक लिथुआनिया में विनियस को पकड़ने के लिए विल्ना को शुरू किया।
1922 इटली में रूस और जर्मनी के बीच एक संधि पर हस्ताक्षर किये गये।
1924 लॉस एंजिल्स में अमेरिकी मीडिया कंपनी मेट्रो-गोल्डविन-मेयर (एमजीएम) की स्थापना की गई।
1941 द्वितीय विश्व युद्ध-यूगोस्लाविया के एक्सिस आक्रमण के दस दिनों के बाद, एनेट पावेलिक ने फासिस्ट उस्ताई के नेतृत्व में क्रोएशिया में एक नई सरकार की घोषणा की।
1945 द्वितीय विश्व युद्ध-लगभग एक मिलियन सोवियत सैनिकों ने गेट्स ऑफ बर्लिन के खिलाफ सेलो हाइट्स की लड़ाई शुरू की।
1947 अमेरिकी फाइनेंसर और राष्ट्रपति के सलाहकार बर्नार्ड बरुचफर्स्ट ने सोवियत संघ और संयुक्त राज्य अमेरिका के बीच द्वितीय विश्व युद्ध के बाद के तनावों को शीत युद्ध के रूप में वर्णित किया।
1955 शेक्सपियर के रिचर्ड तृतीय के सर लॉरेंस ओलिवियर की फिल्म संस्करण, ब्रिटेन में जारी की गयी।
1963 मार्टिन लूथर किंग, जूनियर ने चार दिन पहले श्वेत पादरी द्वारा लिखे गए एक खुले पत्र के जवाब में बर्मिंघम जेलिन से अपना पत्र लिखा था।
1970 यूरोपीय देश फ्रांस में बर्फीले तूफान से 70 लोगों की मौत।
1980 अमेरिका ने नेवादा में परमाणु परीक्षण किया।
1989 कोस्टो रिका ने टूर्नामेंट जीतने के लिए फुटबॉल विश्व कप के आरडी दौर में यूएस को हरा दिया।
1990 19 वीं बोस्टन महिला मैराथन को रोजा मोटा द्वारा जीता गया था। वह पुर्तगाल से है। उसने 2 घंटे 25 मिनट और 30 सेकंड में मैराथन पूरी की।
1992 अफगानिस्तान के राष्ट्रपति नजीबुल्लाह ने इस्तीफा दिया।
1992 मेट्रो न्यूयॉर्क शहर के मिन्स्कॉफ़ थियेटर में रिलीज़ हुई थी। यह 13 दिनों तक हाउसफुल चला।
1992 न्यूयॉर्क रेंजर्स ने 50 खेलों में रिकॉर्ड तोड़ जीत दर्ज की।

विशेष संसद सत्र में नारी शक्ति वंदन अधिनियम 2023

किशन सनमुखदास भावनानी

वैश्विक स्तरपर भारत ने नारी शक्ति वंदन अधिनियम 2023 के माध्यम से लोकतांत्रिक इतिहास में एक निर्णायक कदम उठाया है, जिसका उद्देश्य संसद और विधानसभाओं में महिलाओं को 33 प्रतिशत आरक्षण प्रदान कर राजनीतिक प्रतिनिधित्व में लैंगिक संतुलन स्थापित करना है। यह कदम केवल सांख्यिकीय प्रतिनिधित्व बढ़ाने का प्रयास नहीं है, बल्कि सामाजिक न्याय, समावेशी विकास और लोकतंत्र की गुणवत्ता को मजबूत करने का एक व्यापक दृष्टिकोण भी है। किंतु इस ऐतिहासिक पहल के साथ कई गंभीर प्रश्न और आशंकाएँ भी उभरकर सामने आई हैंविशेषकर प्रॉक्सी नेतृत्व या बैक-डोर कंट्रोल का खतरा, जिसमें निर्वाचित महिला प्रतिनिधि के स्थान पर वास्तविक सत्ता उनके पति या अन्य पुरुष रिश्तेदारों के हाथों में होती है। मैं यह मानता हूं कि यह समस्या भारत तक सीमित नहीं है; विश्व के कई लोकतंत्रों में महिला आरक्षण या कोटा लागू होने के बाद इसी प्रकार की चुनौतियाँ सामने आई हैंइसलिए यह आवश्यक हो जाता है कि हम इस अधिनियम के निहितार्थों, संभावित जोखिमों और सुधारात्मक उपायों का गहन विश्लेषण करें। ताकि नारी शक्ति वंदन अधिनियम 2023 के दूरगामी सकारात्मक प्रभाव हमारे विज़न 2047 के लिए सटीक रूप से मील का पत्थर साबित हो।

साथियों बात अगर हम मुद्दों का विश्लेषण करें तो सबसे पहला और बुनियादी प्रश्न यह है कि क्या महिला जनप्रतिनिधियों का पारिवारिक पुरुषों द्वारा नियंत्रित होना मतदाताओं के विश्वास का हनन है?लोकतंत्र की मूल आत्माप्रतिनिधित्व और उत्तरदायित्व पर आधारित होती है। जब मतदाता किसी महिला को उसकी ईमानदार छवि, सामाजिक संवेदनशीलता और नेतृत्व क्षमता के आधार पर चुनते हैं, तब वे अपेक्षा करते हैं कि वही महिला नीति-निर्माण और निर्णय लेने की प्रक्रिया में सक्रिय भूमिका निभाएगी। लेकिन यदि वास्तविक निर्णय उसके पति या परिवार के पुरुष सदस्य लेते हैं, तो यह न केवल मतदाता के विश्वास के साथ धोखा है, बल्कि लोकतंत्र की पारदर्शिता और जवाबदेही को भी कमजोर करता है। भारत के कई राज्यों में पंचायत स्तर पर सरपंच पति की प्रवृत्ति एक स्थापित वास्तविकता बन चुकी है, जहाँ निर्वाचित महिला केवल नाममात्र की मुखिया होती है और वास्तविक शक्ति पुरुषों के हाथों में रहती है। यह स्थिति महिलाओं के सशक्तिकरण के मूल उद्देश्य को ही निष्प्रभावी कर देती है और उन्हें मात्र एक तुच्छ राजनीतिक औजार बना देती है।

साथियों दूसरा महत्वपूर्ण पहलू यह है कि नारी शक्ति वंदन अधिनियम के लागू होने के बाद बैक-डोर नेतृत्व की संभावनाएँ बढ़ सकती हैं। जब किसी क्षेत्र को महिलाओं के लिए आरक्षित कर दिया जाता है,तोराजनीतिक दल और प्रभावशाली पुरुष नेता अपने परिवार की महिलाओं को उम्मीदवार बनाकर अप्रत्यक्ष रूप से सत्ता पर नियंत्रण बनाए रखने का प्रयास कर सकते हैं। यह प्रवृत्ति पहले से ही स्थानीय निकायों में देखी जा चुकी है और यह संभावना है कि यह अब राज्य और राष्ट्रीय स्तर तक भी फैल सकती है। इस संदर्भ में अंतरराष्ट्रीय अनुभव भी महत्वपूर्ण हैं। उदाहरण के लिए, कुछ अफ्रीकी और दक्षिण एशियाई देशों में महिला कोटा लागू होने के बाद

प्रारंभिक वर्षों में प्रॉक्सी पॉलिटिक्स का चलन बढ़ा,जहाँ महिलाएँ केवल प्रतीकात्मक प्रतिनिधि थीं। हालांकि समय के साथ, शिक्षा, राजनीतिक प्रशिक्षण और सामाजिक जागरूकता के बढ़ने से यह प्रवृत्ति धीरे-धीरे कम हुई। इससे यह स्पष्ट होता है कि केवल आरक्षण देना पर्याप्त नहीं है; उसके साथ संस्थागत और सामाजिक सुधार भी आवश्यक हैं।

साथियों तीसरा बिंदु यह है कि क्या अयोग्य या अक्षम पुरुष नेता, जो स्वयं चुनाव नहीं लड़ सकते, महिलाओं को आगे कर बैक-डोर से सत्ता पर नियंत्रण बनाए रखेंगे? यह आशंका पूरी तरह निराधार नहीं है। भारतीय राजनीति में परिवारवाद और वंशवाद पहले से ही एक महत्वपूर्ण कारक रहा है। ऐसे में, यदि किसी पुरुष नेता पर कानूनी या राजनीतिक प्रतिबंध है, तो वह अपनी पत्नी, बेटी या अन्य महिला रिश्तेदार को उम्मीदवार बनाकर अप्रत्यक्ष रूप से सत्ता का उपयोग कर सकता है। यह न केवल लोकतांत्रिक प्रतिस्पर्धा को कमजोर करता है, बल्कि योग्य और स्वतंत्र महिला नेताओं के उभरने में भी बाधा डालता है। इस समस्या का समाधान केवल कानूनी प्रावधानों से नहीं, बल्कि राजनीतिक दलों की आंतरिक लोकतांत्रिक संरचना और उम्मीदवार चयन प्रक्रिया में अति अति सतर्कता व पारदर्शिता से ही संभव है।

साथियों चौथा और अत्यंत महत्वपूर्ण पहलू अपराध और न्याय व्यवस्था से जुड़ा है। इंस्टीट्यूट फॉर क्राइम एंड जस्टिस पॉलिसी रिसर्च की रिपोर्ट के अनुसार, भारत में महिला कैदियों की संख्या पिछले दो दशकों में 162 प्रतिशत बढ़ी है, जो पुरुष कैदियों की वृद्धि दर (77 प्रतिशत) से कहीं अधिक है। यह असंतुलन कई गंभीर सवाल खड़े करता है। क्या महिलाओं में अपराध की प्रवृत्ति बढ़ रही है, या उन्हें आपराधिक नेटवर्क द्वारा जानबूझकर इस्तेमाल किया जा रहा है? कई मामलों में यह पाया गया है कि मादक पदार्थों की तस्करी, मानव तस्करी और अवैध प्रवास जैसे अपराधों में महिलाओं को इसलिए शामिल किया जाता है क्योंकि उन्हें कम संदेहास्पद माना जाता है। यह स्थिति और भी चिंताजनक हो जाती है जब हम इसे राजनीतिक संदर्भ में देखते हैं। यदि आपराधिक तत्व महिलाओं को राजनीतिक ढाल के रूप में इस्तेमाल करने लगें, तो यह लोकतंत्र और कानून व्यवस्था दोनों के लिए गंभीर खतरा बन सकता है। विशेष रूप से सीमावर्ती राज्यों में, जहाँ अवैध प्रवास और तस्करी की समस्या अधिक है, यह जोखिम और भी बढ़ जाता है।

साथियों पाँचवाँ मुद्दा आरक्षण के व्यावहारिक प्रभाव से जुड़ा है। यदि किसी विधानसभा या लोकसभा क्षेत्र को महिलाओं के लिए आरक्षित कर दिया जाता है,और वहाँ पर्याप्त योग्य महिला उम्मीदवार उपलब्ध नहीं हैं, तो यह संभावना है कि अपेक्षाकृत कम सक्षम उम्मीदवार ही निर्वाचित हो जाएँ। यह स्थिति मतदाताओं के लिए भी अन्यायपूर्ण हो सकती है,क्योंकि उन्हें अपनी पसंद के सर्वश्रेष्ठ उम्मीदवार का चयन करने का अवसर नहीं मिलता। हालांकि यह तर्क आंशिक रूप से सही है, लेकिन इसे व्यापक संदर्भ में देखना आवश्यक है। इतिहास गवाह है कि जब भी किसी वंचित वर्ग को अवसर दिया जाता है, तो प्रारंभिक वर्षों में चुनौतियाँ होती हैं, लेकिन समय के साथ वह वर्ग अपनी क्षमता विकसित कर लेता है। इसलिए, इस समस्या का समाधान आरक्षण को समाप्त करना नहीं, बल्कि महिलाओं के लिए शिक्षा, नेतृत्व प्रशिक्षण और राजनीतिक सहभागिता के अवसर बढ़ाना है।

साथियों छठा और अंतिम बिंदु संवैधानिक संतुलन से जुड़ा है। यह सुनिश्चित करना आवश्यक है कि महिला आरक्षण के कारण पुरुषों के मौलिक अधिकारों, विशेष रूप से समानता के अधिकार, का उल्लंघन न हो। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 14 और 15 समानता और गैर-भेदभाव की गारंटी देते हैं, लेकिन साथ ही अनुच्छेद 15 (3) राज्य को महिलाओं और बच्चों के लिए विशेष प्रावधान करने की अनुमति भी देता है। इसलिए, महिला आरक्षण संवैधानिक रूप से वैध है, बशर्ते कि यह समान अवसर और न्याय के व्यापक सिद्धांतों के अनुरूप हो। यहाँ संतुलन बनाना अत्यंत आवश्यक है, ताकि यह नीति सामाजिक न्याय को बढ़ावा दे, न कि नए प्रकार के असंतुलन पैदा करे। इन सभी चुनौतियों को ध्यान में रखते हुए, यह आवश्यक हो जाता है कि नारी शक्ति वंदन अधिनियम में कुछ ठोस दंडात्मक व सुधारात्मक उपाय जोड़े जाएँ।

साथियों सबसे पहले, प्रॉक्सी नेतृत्व को रोकने के लिए स्पष्ट कानूनी प्रावधान होने चाहिए, जिनमें आर्थिक और आपराधिक दंड शामिल हों। यदि यह साबित होता है कि कोई निर्वाचित महिला प्रतिनिधि केवल नाममात्र की है और वास्तविक निर्णय कोई अन्य व्यक्ति ले रहा है, तो उस पर और संबंधित व्यक्ति पर कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए। दूसरा, महिला प्रतिनिधियों के लिए अनिवार्य राजनीतिक और प्रशासनिक प्रशिक्षण कार्यक्रम शुरू किए जाने चाहिए, ताकि वे आत्मनिर्भर और सक्षम नेता बन सकें। तीसरा, राजनीतिक दलों को अपने आंतरिक ढांचे में सुधार करना होगा और महिलाओं को केवल टोकन उम्मीदवार के रूप में नहीं, बल्कि वास्तविक नेता के रूप में आगे बढ़ाना होगा। चौथा, नागरिक समाज और मीडिया की भूमिका भी महत्वपूर्ण है; उन्हें ऐसे मामलों को उजागर करना चाहिए जहाँ महिलाओं का दुरुपयोग किया जा रहा हो।

अंतरराष्ट्रीय स्तर पर भी यह देखा गया है कि महिला आरक्षण तभी सफल होता है जब उसे व्यापक सामाजिक और संस्थागत सुधारों के साथ जोड़ा जाए। रवांडा, नॉर्वे और फ्रांस जैसे देशों में महिला प्रतिनिधित्व बढ़ने के साथ-साथ महिलाओं की वास्तविक भागीदारी भी बढ़ी है, क्योंकि वहाँ शिक्षा, आर्थिक स्वतंत्रता और सामाजिक स्वीकृति का स्तर उच्च है। भारत को भी इस दिशा में समग्र दृष्टिकोण अपनाने की आवश्यकता है।

अंततः, नारी शक्ति वंदन अधिनियम 2023 भारत के लोकतांत्रिक विकास की दिशा में एक ऐतिहासिक और आवश्यक कदम है, लेकिन इसकी सफलता इस बात पर निर्भर करेगी कि हम संख्यात्मक प्रतिनिधित्व को वास्तविक सशक्तिकरण में कैसे बदलते हैं।

महिला आरक्षण विधेयक : भारत की लोकतांत्रिक यात्रा में एक शांत क्रांति

न्योमा गुप्ता

महिला आरक्षण विधेयक—औपचारिक रूप से नारी शक्ति वंदन अधिनियम, 2023—को अक्सर संख्याओं, कोटा और राजनीतिक गणित के संदर्भ में चर्चा किया जाता है। लेकिन सुर्खियों और विधायी शब्दजाल से परे इसमें एक से अधिक परिवर्तनकारी पहलू निहित हैं- यह एक शांत तरीके से इस बात को पुनर्परिभाषित कर रहा है कि भारतीय लोकतंत्र कैसा दिख सकता है, जब वह अपनी आधी आबादी के लिए केवल लाभार्थी के रूप में नहीं, बल्कि निर्णयकर्ता के रूप में स्थान बनाता है।

सकारात्मक दृष्टिकोण से देखें तो यह विधेयक केवल आरक्षण का प्रावधान नहीं है—यह संस्थागत विश्वास का प्रतीक है। यह उस धारणा से बदलाव को दर्शाता है कि महिलाओं को अस्थायी सहारे की आवश्यकता है, और इस स्वीकार्यता की ओर बढ़ता है कि वे शासन व्यवस्था की मूल आधारशिला हैं।

लोकसभा और राज्य विधानसभाओं में एक-तिहाई सीटें महिलाओं के लिए आरक्षित करके, भारत केवल ऐतिहासिक बहिष्कार को सुधार नहीं रहा है, बल्कि नेतृत्व की परिभाषा को भी विस्तृत कर रहा है।

आलोचक अक्सर यह तर्क देते हैं कि आरक्षण स्वत: सशक्तिकरण में परिवर्तित नहीं हो सकता। यह चिंता उचित है, परंतु अधूरी है। लोकतंत्र में हर संरचनात्मक बदलाव—चाहे वह सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार हो या सत्ता का विकेंद्रीकरण—वास्तविकता बनने से पहले विश्वास की एक छलांग की मांग करता है। महिला आरक्षण विधेयक भी इसी लोकतांत्रिक विस्तार की परंपरा का हिस्सा है। यह एक पाइपलाइन प्रभाव उत्पन्न करता है। आज विधानसभाओं में अधिक महिलाएं होंगी, तो कल नेतृत्व के हर स्तर—पंचायत से संसद तक—में उनकी भागीदारी बढ़ेगी। इसके साथ ही एक सूक्ष्म सांस्कृतिक परिवर्तन भी चल रहा है।

प्रतिनिधित्व केवल प्रतीकात्मक नहीं होता। यह शिक्षाप्रद भी होता है। जब युवा लड़कियां महिलाओं को बजट पर चर्चा करते, कानून बनाते और राष्ट्रीय प्राथमिकताओं को निर्धारित करते हुए देखती हैं, तो महत्वाकांक्षा असाधारण नहीं रहती, बल्कि सामान्य बन जाती है। राजनीति, जिसे लंबे समय तक पुरुषों के प्रभुत्व वाले क्षेत्र के रूप में देखा गया, अब एक साझा नागरिक मंच के रूप में उभरने लगती है।

सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि यह सुधार शासन की अवधारणा को भी पुनर्परिभाषित करता है। भारत में स्थानीय निकायों के अनुभव से यह स्पष्ट हुआ है कि महिला नेतृत्व अक्सर स्वास्थ्य, शिक्षा, जल और सुरक्षा जैसे मुद्दों को प्राथमिकता देता है—जो सामाजिक संरचना को सुदृढ़ करते हैं। इस उपस्थिति का राष्ट्रीय स्तर पर विस्तार नीतियों को मानव-केंद्रित विकास की ओर अग्रसर कर सकता है। अत: महिला आरक्षण विधेयक केवल संसद में सीटों तक सीमित नहीं है। यह लोकतंत्र की नैतिक कल्पना का विस्तार है—जहां समावेशन कोई अपवाद नहीं, बल्कि मूल सिद्धांत है।

होर्मुज में आमने-सामने आ सकते हैं अमेरिका और चीन

जाहिद खान

होर्मुज को अब सिर्फ ईरान और अमेरिका के बीच की तनातनी मानना बड़ी भूल होगी। असली खतरा अब इससे भी बड़ा है। अगर इस रास्ते में किसी चीनी टैंकर को रोक लिया गया, तो मामला सिर्फ एक जहाज, एक समुद्री जांच या एक दबाव भरी कार्रवाई तक सीमित नहीं रहेगा। वह सीधे अमेरिका और चीन के बीच टकराव का दरवाजा खोल सकता है और जब दुनिया की दो सबसे बड़ी ताकतें आमने-सामने आती हैं, तो असर सिर्फ समंदर तक नहीं रहता बल्कि पूरी दुनिया उसकी चपेट में आ जाती है।

अब हालात धीरे-धीरे उसी दिशा में बढ़ते दिख रहे हैं, जहां ईरान पीछे छूट सकता है और सामने सीधी तस्वीर अमेरिका और चीन की बन सकती है। वजह साफ है। होर्मुज वह रास्ता है, जिससे दुनिया का बड़ा तेल गुजरता है और चीन इस पूरी कहानी में कोई किनारे बैठा तमाशबीन नहीं है। उसकी ऊर्जा जरूरत, उसका व्यापार, उसकी फैक्ट्रियां, उसका समुद्री कारोबार, सब किसी न किसी तरह इस रास्ते से जुड़े हुए हैं। ऐसे में अगर अमेरिका यहां अपनी ताकत दिखाने के लिए किसी चीनी टैंकर को रोकता है, तो चीन इसे मामूली घटना मानकर आगे नहीं बढ़ जाएगा। वह इसे सीधी चुनौती मानेगा।

यहीं से मामला भारी हो जाता है क्योंकि यह सिर्फ समुद्र में एक रोक नहीं होगी, यह संदेश होगा और चीन ऐसे संदेशों को बहुत ध्यान से पढ़ता है। वह समझेगा कि अमेरिका अब ईरान पर दबाव बनाते-बनाते चीन के हितों तक पहुंच गया है। इसका मतलब यह होगा कि अब बात सिर्फ पश्चिम एशिया की नहीं रही, अब इसमें दुनिया की बड़ी ताकतों का अहंकार, असर और दबदबा भी शामिल हो गया है और जहां यह चीजें शामिल हो जाएं, वहां मामला जल्दी शांत नहीं होता।

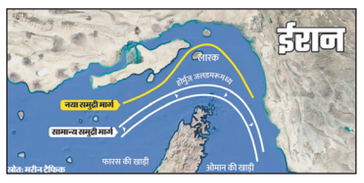

चीन की ताकत सिर्फ उसकी फौज में नहीं है। उसकी सबसे बड़ी ताकत उसका फैलाव है। कारोबार में, बाजार में, बंदरगाहों में, माल ढुलाई में, कारखानों में, दुनिया की सप्लाई व्यवस्था में, हर जगह उसकी पकड़ है इसलिए उसका जवाब सिर्फ बंदूक से नहीं आएगा। वह व्यापार से जवाब दे सकता है। वह दबाव से जवाब दे सकता है। वह अपने बाजार का इस्तेमाल कर सकता है। वह दुनिया को यह भी दिखा सकता है कि अगर उसके हितों को छेड़ा गया, तो इसकी कीमत सिर्फ एक देश नहीं, कई देश चुकाएंगे। यही वजह है कि अमेरिका और चीन के बीच सीधे फौजी टकराव नहीं दिखता, लेकिन उसका असर बहुत दूर तक जाता है।

अमेरिका भी यह बात अच्छी तरह जानता है। उसे मालूम है कि चीन को छूना और चीन को ललकारना दो अलग बातें हैं इसलिए होर्मुज में उठाया गया एक कदम केवल समुद्री कार्रवाई नहीं होगा, वह एक तरह का इम्तिहान होगा। देखना यह होगा कि चीन सिर्फ बयान देता है या जवाब की नई लाइन खींचता है और अगर चीन ने जवाब में अपनी मौजूदगी बढ़ाई, अपने जहाजों की सुरक्षा बढ़ाई या अपने असर वाले मुल्कों को साथ खड़ा करना शुरू कर दिया, तो मामला और खुल जाएगा।

फिर दुनिया का मिजाज बदलना शुरू होगा। छोटे देश चुप नहीं रह पाएंगे। उन्हें देखना होगा कि किस तरफ खड़ा होना है। बाजार पहले ही डर जाएंगे। तेल पर असर पड़ेगा। माल ढुलाई पर असर पड़ेगा। बीमा महंगा होगा। कारोबार धीमा होगा और फिर वही कहानी शुरू होगी, जिसका सबसे बुरा असर आम आदमी पर आता है। पेट्रोल महंगा, गैस महंगी, सामान महंगा, और ऊपर से डर अलग। बड़ी ताकतें अपने-अपने हिसाब से चाल चलती हैं, लेकिन उनकी कीमत आखिर में वही आदमी चुकाता है, जो न वॉशिंगटन में बैठा है, न बीजिंग में।

सबसे खतरनाक बात यह है कि ऐसे टकराव हमेशा बड़े ऐलान से शुरू नहीं होते। कई बार सिर्फ एक रोक, एक तलाशी, एक चेतावनी, एक गलत अंदाजा और हालात वहां पहुंच जाते हैं, जहां से वापसी मुश्किल हो जाती है। इतिहास में कई तनाव ऐसे रहे हैं, जो पहले दबाव के खेल की तरह शुरू हुए, लेकिन बाद में बड़े संकट में बदल गए। अभी भी ऊपर से सब कुछ नपा-तुला लग रहा है। हर पक्ष अपने कदम सोच-समझकर रख रहा है, लेकिन यही वह दौर होता है, जिसमें एक छोटी भूल बहुत बड़ी आग भड़का सकती है।

इसलिए होर्मुज को सिर्फ तेल का रास्ता समझना अब काफी नहीं है। यह अब दुनिया की बड़ी ताकतों के बीच नब्ज टटोलने की जगह बनता जा रहा है। यहां अमेरिका अगर बहुत आगे बढ़ा तो चीन पीछे हटने वाला नहीं दिखेगा और अगर चीन ने जवाब में अपने हितों की खुली हिफाजत शुरू कर दी तो फिर मामला सिर्फ ईरान, इस्राइल, लेबनान या खाड़ी तक सीमित नहीं रहेगा। फिर यह साफ अमेरिका-चीन टकराव की कहानी बन जाएगी।

ऐसे में होर्मुज में किसी चीनी टैंकर को रोकना मामूली समुद्री घटना नहीं होगी। यह वह चिंगारी बन सकती है, जो ईरान-अमेरिका तनाव को पीछे छोड़कर सीधे अमेरिका-चीन टकराव का रास्ता खोल दे और जब दो बड़ी ताकतें आमने-सामने आती हैं तो समंदर से उठी हलचल दुनिया की हर जेब तक पहुंचती है।

असफल अमेरिका-ईरान वार्ता ने बढ़ायी चिंता

शशांक

इस्लामाबाद में हुई अमेरिका-ईरान वार्ता का बेनतीजा रहना बहुत आश्चर्यजनक नहीं है। वार्ता के बिल्कुल शुरुआती चरण में इससे ज्यादा उम्मीद की भी नहीं जा सकती थी। हालांकि इससे क्षेत्रीय और वैश्विक स्तर पर चिंता जरूर बढ़ गयी है। स्पष्ट है कि अमेरिका की सख्त शर्तों और ईरान के इनकार ने समझौते की राह मुश्किल बना दी। ऐसे में आने वाले समय में तनाव बढ़ने और कूटनीतिक कोशिशों के और जटिल होने की आशंका भी जतायी जा रही है। अलबत्ता ईरान और अमेरिका के बीच हुई बातचीत अगर किसी नतीजे पर नहीं पहुंच पायी, तो यह नाउम्मीदी का भी कारण नहीं होना चाहिए। यह मानने का कारण है कि दोनों ही पक्ष फिलहाल वार्ता को अंजाम तक पहुंचाने के लिए पूरी तरह तैयार नहीं थे। साथ ही, यह भी सच है कि आपसी मुलाकातों का सिलसिला अगर जारी रहता है, तो पश्चिम एशिया के संकट का हल निकल सकता है। पाकिस्तान में संपन्न हुई इस वार्ता के प्रति बेशक हमें भरोसा नहीं था, लेकिन ईरान और अमेरिका को निश्चित तौर पर था।

ईरान ने हालांकि कई मौके पर पाकिस्तान के मध्यस्थ होने के खिलाफ टिप्पणी की, लेकिन ईरानी वार्ताकार पाकिस्तान पहुंचे थे, तो कहीं न कहीं कुछ उम्मीद तो थी ही। दूसरी ओर, अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और पाकिस्तान के सेनाध्यक्ष फील्ड मार्शल असलम मुनीर की गाढ़ी दोस्ती को देखते हुए अमेरिकी वार्ताकार इस्लामाबाद में ठोस उम्मीदों के साथ पहुंचे थे। और ईरान भले ही पाकिस्तान पर भरोसा न करने की बात कह चुका हो, लेकिन खुद पाकिस्तान इस युद्ध को खत्म करना चाहता है, क्योंकि वह जानता है कि ट्रंप के नेतृत्व में अमेरिकी आक्रामकता अगर जारी रही, तो ईरान के खिलाफ उसकी कार्रवाई कहीं न कहीं पाकिस्तान पर भी असर डाल सकती है।

इस्लामाबाद में दोनों ही पक्ष जिन भी उम्मीदों

के साथ आये हों, लेकिन लगभग इक्कीस घंटे की बातचीत के बाद दोनों पक्षों का रवैया बिल्कुल स्पष्ट है। ईरान दरअसल किसी जल्दबाजी में नहीं है और उसके हक में कदम न उठाये जाने पर वह युद्ध खत्म नहीं करेगा। इस लिहाज से देखें, तो युद्ध शुरू होने से अब तक उसके रवैये में कोई खास बदलाव नहीं आया है, भले ही इस दौरान उसे भारी नुकसान पहुंचा है। वार्ता बेनतीजा रहने के बाद ईरान के रुख से यह भी लगता है कि वह बहुत निराश नहीं हैं। ईरान के विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता का कहना है कि कूटनीति कभी खत्म नहीं होती, प्रयास जारी रहते हैं। ऐसी बातचीत में आसानी से हल तक नहीं पहुंचा जाता। याद रखना चाहिए कि वियतनाम के साथ वार्ता में समाधान तक पहुंचने में अमेरिका को कई साल लग गये थे।

ईरान के विपरीत अमेरिका के रवैये में फर्क दिखा। अमेरिका वार्ताकारों का नेतृत्व कर रहे उपराष्ट्रपति जेडी वेंस ने कहा कि ईरान के परमाणु हथियारों और उसके परमाणु कार्यक्रम पर कोई सहमति नहीं बन पायी। यानी परमाणु कार्यक्रम को लेकर दोनों देशों के बीच मतभेद दूर नहीं हो सके। क्या वेंस का यह रुख अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के रुख के अनुकूल है, जो कुछ दिन पहले तक भी ईरान की सभ्यता को निर्मूल कर देने की बात कर रहे थे? क्या अमेरिका सिर्फ ईरान के परमाणु हथियारों के बारे में बातचीत करने के लिए पाकिस्तान गया था? क्या अमेरिका के एजेंडे में और दूसरे मुद्दे नहीं थे? अगर सिर्फ ईरान के परमाणु हथियारों पर ही बात अटकी हुई है, जैसा कि वेंस का कहना है, तो इसके लिए पाकिस्तान की मध्यस्थता की तो कोई जरूरत ही नहीं है। अगर अमेरिका को ईरान के परमाणु हथियारों की चिंता है, तो उसे रूस और चीन के साथ बातचीत करनी चाहिए। यही दोनों देश इस मामले में अमेरिका की चिंता दूर कर सकते हैं।

अमेरिका ने बातचीत टूटने को निराशाजनक बताया। क्या वह वार्ता के बिल्कुल शुरुआती चरण में ही समस्या का हल निकल जाने के प्रति आश्वस्त था? अमेरिका ने जिस तरह बातचीत खत्म की, वह भी बेहद चौंकाने वाली रही। पहले ऐसा लग रहा था कि ईरान और अमेरिका के बीच वार्ता रविवार को भी जारी रहेगी। लेकिन अमेरिकी उपराष्ट्रपति जेडी वेंस ने रविवार की सुबह समझौता न होने से संबंधित एक बयान अचानक प्रेस को जारी किया और फिर पाकिस्तान से निकल गये। वेंस की यह प्रतिक्रिया चौंकाने वाली रही। हो सकता है कि पूरी स्थिति पर बेहद नजदीकी नजर रख रहे अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप ने उन्हें ऐसा निर्देश दिया हो। वार्ता के नतीजे तक न पहुंचने के कई कारण रहे। वार्ता के दौरान ईरान ने होर्मुज पर अपना नियंत्रण बनाये रखने की बात कही, जबकि अमेरिका इसे अंतरराष्ट्रीय जलमार्ग के रूप में पूरी तरह खोलने पर जोर दे रहा था। लेकिन होर्मुज के मुद्दे पर अमेरिकी मांग ईरान के लिए स्वीकार्य नहीं थी। अमेरिका के साथ वार्ता विफल होने के बाद ईरान की सैन्य संस्था इस्लामिक रिवॉल्यूशनरी गार्ड्स कॉर्प्स ने स्पष्ट कर दिया है कि होर्मुज जलडमरुमध्य की स्थिति में कोई बदलाव नहीं किया जायेगा। यानी जो स्थिति पहले बनी हुई थी, वह आगे भी जारी रहेगी। दरअसल ईरान ने अमेरिका और इस्राइल के हमले के बाद होर्मुज जलडमरुमध्य को बंद कर दिया और भारत समेत गिने-चुने देशों के तेल टैंकर ही वहां से गुजर रहे हैं।

नारी शक्ति वंदन : आधी आबादी का हक या चुनावी दांव?

दिलीप कुमार पाठक

यदि महिलाएं सशक्त होती हैं और देश के शासन-प्रशासन में उनकी भागीदारी बढ़ती है, तो हमारे लोकतंत्र और समाज के लिए इससे बेहतर भला और क्या होगा। आधी आबादी को उनका हक मिलना सिर्फ न्याय नहीं, बल्कि राष्ट्र की प्रगति के लिए अनिवार्य है। लेकिन जब हम महिला आरक्षण से जुड़े हालिया घटनाक्रमों और इसके कानूनी पेचीदगियों को देखते हैं, तो साफ नजर आता है कि सरकार की मंशा इस मुद्दे पर पूरी तरह स्पष्ट नहीं है। ऐसा लगता है कि इसे वास्तविक सशक्तिकरण के बजाय एक राजनीतिक हथियार के तौर पर अधिक इस्तेमाल किया जा रहा है। इस कानून की सबसे बड़ी और बुनियादी कमी इसका शर्तों में बंधा होना है। सरकार ने बिल तो पास कर दिया, लेकिन इसके साथ एक ऐसी शर्त जोड़ दी जिसने इसे फिलहाल एक भविष्य का वादा बनाकर छोड़ दिया है। कानून के मुताबिक, आरक्षण तभी लागू होगा जब नई जनगणना होगी और उसके आधार पर सीटों का नया बंटवारा यानी परिसीमन होगा।

विशेषज्ञों का मानना है कि इस लंबी प्रक्रिया के कारण यह आरक्षण 2029 या शायद 2034 तक खिंच सकता है। सवाल यह उठता है कि अगर नीयत साफ थी, तो इसे तुरंत मौजूदा सीटों पर ही क्यों लागू नहीं किया गया? जनगणना और परिसीमन जैसी उलझी हुई प्रक्रियाओं के साथ जोड़कर सरकार ने इसे एक ऐसे रास्ते पर डाल दिया है, जिसकी मंजिल का फिलहाल कोई पता नहीं है। जैसे ही सरकार सीटों के नए बंटवारे की बात करती है, दक्षिण भारतीय राज्यों की चिंता बढ़ जाती है। तमिलनाडु, केरल, कर्नाटक और आंध्र प्रदेश जैसे राज्यों ने पिछले कई सालों में जनसंख्या को काबू करने के लिए बहुत अच्छा काम किया है। अब तकनीकी दिक्कत यह है कि यदि सीटों का फैसला केवल आबादी के आधार पर होता है, तो उत्तर प्रदेश और बिहार जैसे राज्यों की लोकसभा सीटें बहुत ज्यादा बढ़ जाएंगी और दक्षिण का राजनीतिक वजन कम हो जाएगा। आंकड़ों के हिसाब से देखें तो उत्तर भारत के कुछ राज्यों में सीटें अस्सी प्रतिशत तक बढ़ सकती हैं, जबकि दक्षिण में यह बढ़ोतरी बहुत कम होगी। दक्षिण के राज्यों का कहना है कि उन्हें अच्छा काम करने की सजा दी जा रही है। सरकार ने इस क्षेत्रीय विवाद को सुलझाने का कोई पक्का रास्ता बताए बिना ही महिला आरक्षण को सीटों के बंटवारे से जोड़ दिया। इससे यह डर पैदा हो गया है कि महिलाओं को हक देने के नाम पर कहीं देश के अलग-अलग हिस्सों के बीच का तालमेल ही न बिगड़ जाए।

इस बिल की एक और बड़ी व्यावहारिक चिंता प्रॉक्सी संस्कृति और रसूखदार राजनीतिक घरानों का कब्जा है। इसे आसान भाषा में समझें तो यह नाम महिला का और काम पुरुष का वाली स्थिति है। गाँवों की पंचायतों में हमने अक्सर देखा है कि महिला चुनाव तो जीत जाती है, लेकिन दफ्तर में उसके पति, पिता या भाई बैठते हैं और सारे फैसले वही लेते हैं। इसे ही पति-सरपंच संस्कृति कहा जाता है। अब डर यह है कि विधानसभा और संसद में भी यही होगा। राजनीतिक पार्टियां जमीन से जुड़ी संघर्षशील महिलाओं के बजाय उन्हीं महिलाओं को टिकट देंगी जो पहले से ताकतवर राजनीतिक परिवारों से आती हैं। यानी एक आम महिला के लिए संसद के दरवाजे अभी भी बंद रह सकते हैं, क्योंकि आज के दौर में चुनाव लड़ना बहुत महंगा हो चुका है और महिलाओं के पास अपने खर्च के लिए पैसे नहीं होते। बिना सरकारी मदद या चुनावी खर्च में छूट के, यह आरक्षण केवल अमीर वर्ग की महिलाओं तक सिमट कर रह जाएगा। इसके अलावा, राज्यसभा और राज्यों की विधान परिषदों को इस आरक्षण से बाहर रखना भी एक बड़ी खामी है। लोकसभा में महिला सांसदों की संख्या अभी बहुत कम है, फिर भी बड़े सदनों में उनकी भागीदारी पर चुप रहना सरकार की सोच पर सवाल उठाता है। साथ ही, पार्टियों के भीतर लोकतंत्र की कमी एक और कड़वा सच है। जब तक टिकट बांटने वाली मुख्य कमेटियों में महिलाओं को जगह नहीं मिलती, तब तक चुनी गई महिला प्रतिनिधियों की ताकत केवल कागजों तक ही रहेगी। एक और कमी सीटों के बदलने का नियम है। हर चुनाव के बाद आरक्षित सीटें बदलने से नेताओं की अपने इलाके के प्रति जिम्मेदारी खत्म हो जाएगी, क्योंकि उन्हें पता होगा कि अगला चुनाव उन्हें वहां से लड़ना ही नहीं है।

कुल मिलाकर, सरकार ने बिल पास करके सुर्खियां तो बटोर लीं, लेकिन इसे लागू करने में जो रुकावटें छोड़ी हैं, वे इसे एक अधूरा और जल्दबाजी में लिया गया फैसला साबित करती हैं। बिना किसी ठोस तैयारी के, केवल चुनाव की हवा को देखते हुए कानून बना देना लोकतंत्र के लिए सही संकेत नहीं है।

कार्डियोलॉजिस्ट बनकर रखें लोगों के दिलों का ख्याल

एक बेहतरीन हृदय रोग विशेषज्ञ बनने के लिए छात्रों के पास ना सिर्फ चिकित्सा और विज्ञान में संबंधित ज्ञान होना चाहिए, बल्कि रोगियों की सेवा करने, दूसरों के प्रति दया करने, आत्म-प्रेरित होने और चिकित्सा शिक्षा और अभ्यास के लंबे समय तक जीवित रहने में सक्षम होना चाहिए। हृदय हमारे शरीर का एक बेहद महत्वपूर्ण आंतरिक अंग है और एक हेल्दी लाइफस्टाइल जीने के लिए जरूरी है कि आप इसका पूरी तरह ख्याल रखें।

आमतौर पर लोग अपने दिल का ख्याल रखने के लिए खानपान से लेकर अन्य कई उपाय अपनाते हैं, लेकिन फिर भी कई बार लोगों को कुछ समस्याओं का सामना करना पड़ता है। इस स्थिति में व्यक्ति को कार्डियोलॉजिस्ट को कंसल्ट करने की जरूरत पड़ती है। कार्डियोलॉजी चिकित्सा का एक प्रभाग है जो हृदय विकारों से संबंधित निदान और उपचार से संबंधित है। दिल के विकारों से निपटने वाले चिकित्सा चिकित्सकों को आमतौर पर कार्डियोलॉजिस्ट या हृदय रोग विशेषज्ञ कहा जाता है। चिकित्सा विज्ञान की इस शाखा का बेहद महत्व है और अगर आप चाहें तो इस दिशा में अपना कदम बढ़ा सकते हैं-

क्या होता है काम

एक हृदय रोग विशेषज्ञ हृदय, धमनियों और नसों का डॉक्टर है। एक्सपर्ट्स के अनुसार, हृदय रोग विशेषज्ञ हृदय की विफलता, जन्मजात हृदय दोष और कोरोनरी धमनी रोग का निदान और उपचार प्रदान करते हैं। इसमें धमनियों के संकीर्ण होने, हृदय के वाल्व में समस्याएं, मांसपेशियों के ऊतकों को नुकसान और पेरिकार्डियम के विकार के कारण प्रतिबंधित परिसंचरण के कारण होने वाली समस्याएं शामिल हैं।

स्किल्स

एजुकेशन एक्सपर्ट्स का मानना है कि एक बेहतरीन हृदय रोग विशेषज्ञ बनने के लिए छात्रों के पास ना सिर्फ चिकित्सा और विज्ञान में संबंधित ज्ञान होना चाहिए, बल्कि रोगियों की सेवा करने, दूसरों के प्रति दया करने, आत्म-प्रेरित होने और चिकित्सा शिक्षा और अभ्यास के लंबे समय तक जीवित रहने में सक्षम होना चाहिए। कार्डियोलॉजिस्ट बनने के लिए अनुशासन, धैर्य, उत्कृष्टता के लिए प्रतिबद्धता और आत्मविश्वास का होना भी उतना ही आवश्यक है। उनके पास जीवन की खतरनाक स्थितियों में निर्णय लेने की क्षमता होनी चाहिए। कैरियर कोच कहते हैं कि हृदय रोग विशेषज्ञ को भी आहार और व्यायाम विशेषज्ञ भी होना चाहिए।

योग्यता

एक कार्डियोलॉजिस्ट बनने के लिए एमबीबीएस की डिग्री के अलावा कई सालों की प्रैक्टिस, लाइसेंस व बोर्ड सर्टिफिकेशन होना चाहिए। कार्डियोलॉजिस्ट बनने के लिए एमडी/एमएस या डीएनबी की डिग्री लेने के बाद इस क्षेत्र में स्पेशलाइजेशन के लिए डीएम इन कार्डियोलॉजी की डिग्री लेनी होगी। इस डिग्री की अवधि लगभग तीन साल की होती है।

अवसर

कॅरियर काउंसलर के अनुसार, एक प्रोफेशनल कार्डियोलॉजिस्ट के लिए अवसरों की कोई कमी नहीं है। आप सरकारी या प्राइवेट हास्पिटल में बतौर डॉक्टर काम कर सकते हैं। इसके अलावा आप कार्डियक रिहैबिलेशन सेंटर या क्लीनिक टेस्टिंग सेंटर्स में भी काम कर सकते हैं। वहीं आप खुद की प्रैक्टिस भी शुरू कर सकते हैं और खुद का क्लीनिक खोल सकते हैं। जो कार्डियोलॉजिस्ट पढ़ाना पसंद करते हैं, वे मेडिकल कॉलेजों में बतौर लेक्चरर भी अपनी सेवाएं दे सकते हैं।

आमदनी

एक कार्डियोलॉजिस्ट की आमदनी उसके अनुभव व भौगोलिक स्थान पर मुख्य रूप से निर्धारित होती है। जो कार्डियोलॉजिस्ट शहर में काम करते हैं, उन्हें अपेक्षाकृत अधिक सैलरी मिलती है, वहीं ग्रामीण क्षेत्रों में आमदनी का स्तर कम हो सकता है। हालांकि अगर आप किसी सरकारी अस्पताल में बतौर फ्रेशर काम शुरू करते हैं, तब भी शुरूआती दौर में आप 25000 रूपए आसानी से कमा सकते हैं। जबकि निजी अस्पतालों में वेतन अधिक हो सकता है। वहीं कुछ वर्षों के अनुभव के बाद आपकी आमदनी लाखों में हो सकती है।

प्रमुख संस्थान

- गोविंद वल्लभ पंत इंस्टीट्यूटी ऑफ पोस्ट ग्रेजुएट मेडिकल एजुकेशन एंड रिसर्च, नई दिल्ली
- रविन्द्रनाथ टैगोर इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ कार्डियक साइंस, कोलकाता
- मौलाना आजाद मेडिकल कॉलेज, नई दिल्ली
- ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस, नई दिल्ली
- आर्म्ड फोर्स मेडिकल कॉलेज, पुणे
- संजय गांधी पोस्टग्रेजुएट इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस, लखनऊ

फॉरेंसिक साइंस के क्षेत्र में कॅरियर कैसे बनाएं? कोर्स, जॉब और सैलरी

फॉरेंसिक साइंस की फील्ड में काम करने वाले प्रोफेशनल फॉरेंसिक साइंस साइंटिस्ट या फॉरेंसिक साइंस एक्सपर्ट्स कहलाते हैं। फॉरेंसिक साइंस साइंटिस्ट्स टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करके क्राइम स्पॉट पर मौजूद सबूतों की जाँच करते हैं और अपराधियों को पकड़ने में मदद करते हैं। इसके लिए वे क्राइम सीन, ब्लड सेंपल, डीएनए प्रोफाइलिंग आदि की जांच करते हैं।

फॉरेंसिक साइंस का इस्तेमाल आपराधिक मामलों की जांच और कानूनी प्रक्रियाओं के लिए किया जाता है। फॉरेंसिक साइंस में केमिस्ट्री, बायोलॉजी, फिजिक्स, जियोलोजी, साइकोलॉजी, सोशल साइंस, इंजीनियरिंग आदि फील्ड्स शामिल होती हैं। इस फील्ड में काम करने वाले प्रोफेशनल फॉरेंसिक साइंस साइंटिस्ट या फॉरेंसिक साइंस एक्सपर्ट्स कहलाते हैं। फॉरेंसिक साइंस साइंटिस्ट्स टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करके क्राइम स्पॉट पर मौजूद सबूतों की जाँच करते हैं और अपराधियों को पकड़ने में मदद करते हैं। इसके लिए वे क्राइम सीन, ब्लड सेंपल, डीएनए प्रोफाइलिंग आदि की जांच करते हैं।

कोर्स

फॉरेंसिक साइंस में करियर बनाने के लिए 12प्द्ध में साइंस होनी जरूरी है। आप फोरेंसिक साइंस एंड क्रिमिनोलॉजी या फॉरेंसिक साइंस एंड लॉ में एक वर्षीय डिप्लोमा कर सकते हैं। आप फॉरेंसिक साइंस 3 साल की बीएससी, 2 साल की एमएससी भी कर सकते हैं। इस फील्ड में स्पेशलाइजेशन और रिसर्च करने के इच्छुक हों तो फॉरेंसिक साइंस में पीएचडी और एमफिल भी कर सकते हैं।

जरूरी स्किल्स

एक फॉरेंसिक साइंस साइंटिस्ट को जिज्ञासु होना चाहिए और साहसिक कार्यों में दिलचस्पी होनी चाहिए। इस फील्ड में हर कदम पर चुनौती है इसलिए आपको दिमागी तौर पर मजबूत होना जरूर है। इसके साथ ही आपके अंदर मजबूत कम्युनिकेशन स्किल्स होना भी बेहद जरूरी है। एक फॉरेंसिक साइंस साइंटिस्ट को कई तरह की टेस्ट रिपोर्ट लिखनी होती हैं इसलिए आपकी राइटिंग स्किल्स भी अच्छी होनी चाहिए।फॉरेंसिक साइंस साइंटिस्ट को सबूतों की जाँच करनी होती है इसलिए आपको एकाग्रता और सतर्कता के साथ काम करना आना चाहिए।

कहां मिलेगी नौकरी

इस फील्ड में सरकारी और प्राइवेट जॉब्स की भरमार है। फॉरेंसिक साइंस में डिग्री हासिल करने के बाद आपको पुलिस, लीगल सिस्टम, इंवेस्टिगेटिव सर्विस जैसी जगहों पर जॉब मिल सकती है। वहीं, कोई प्राइवेट एजेंसी भी आपको बतौर फॉरेंसिक साइंटिस्ट्स जॉब ऑफर कर सकती है। अगर आप में योग्यता है तो आपको फॉरेंसिक साइंटिस्ट इंटेलि ?जेंस ब्यूरो और सीबीआई में भी नौकरी का अवसर प्राप्त हो सकता है। इसके अलावा आप किसी फॉरेंसिक साइंस शिक्षण संस्थान में टीचर के रूप पढ़ा कर अच्छी सैलरी कमा सकते हैं।

सैलरी

योग्यता के आधार पर आपको शुरुआत में 20-50 हजार रुपये प्रतिमाह तक सैलरी मिल सकती है। समय के साथ अनुभव होने पर आप 6 से 8 लाख रुपये तक महीना कमा सकते हैं।

विदेशों में स्कॉलरशिप के लिए अप्लाई करने से पहले इन बातों का रखें ध्यान

विदेशों से हायर एजुकेशन प्राप्त करना कई लोगों की टू-डू लिस्ट में शामिल होता है। कई लोग इसे प्राप्त कर लेते हैं और कई लोग इसे प्राप्त करने से वंचित भी रह जाते हैं। विदेशों से हायर एजुकेशन की पढ़ाई करने पर जीवन में कई अवसर मिलते हैं। हालांकि हायर एजुकेशन जितने बेहतर अवसर देता है उतना ही खर्चीला भी है। विदेशों में पढ़ाई करने के लिए एक बेहतर प्लानिंग की आवश्यकता तो होते ही है साथ ही आवश्यकता होती है नॉलेज की। उसी नॉलेज और प्लानिंग में से एक है स्कॉलरशिप के लिए अप्लाई करना। जब स्कॉलरशिप की बात आती है तो हमें कई बातों को ध्यान में रखना पड़ता है। आइए जानते हैं कुछ महत्वपूर्ण बातों को जिन्हें स्कॉलरशिप प्राप्त करने से पहले ध्यान में रखना पड़ता है।

स्ट्रांग प्रोफाइल बनाएं

हालांकि स्कॉलरशिप के लिए एकेडमिक स्ट्रेन्थ आवश्यक है। अगर मास्टर्स करने का आप प्लान बना रहे हैं तो आपका जीपीए 70 से अधिक है तो स्कोर बेहतर माना जाता है। लेकिन केवल इतना ही आवश्यक नहीं है। स्कॉलरशिप के लिए अप्लाई करते वक्त इस बात का ध्यान रखें कि आपका प्रोफाइल बेहद स्ट्रांग होना चाहिए। इसके लिए आप इसमें एक्स्ट्रा करिकुलम एक्टिविटी जैसे स्पोर्टस, म्यूजिक, ड्रामा इत्यादि की डिटेल जरूर लिखें। इससे आपका प्रोफाइल बेहद स्ट्रांग बनेगा।

यूनिवर्सिटी स्कॉलरशिप से आगे बढ़कर सोचें

ध्यान रखें कि विदेशों में पढ़ने के लिए केवल यूनिवर्सिटी ही नहीं बल्कि कई संस्था स्कॉलरशिप प्रदान करती है। ये स्कॉलरशिप सरकारी के साथ-साथ प्राइवेट संस्थाओं द्वारा भी दिया जाता है। अगर आप भारत में हैं तो कई संस्था जैसे टाटा आपको विदेश में पढ़ने के लिए स्कॉलरशिप देगी। इसके साथ ही अगर आप विदेश में हैं तो वो देश भी विदेशों छात्रों के लिए कई स्कॉलरशिप प्लान पर कार्य करता है। इन स्कॉलरशिप के बारे में दोनें देशों के एजुकेशन डिपार्टमेंट से जानकारी प्राप्त की जा सकती है।

कोर्स से पहले कर दें अप्लाई

आप जो कोर्स करना चाहते हैं उसके शुरू होने से 18 महीने पहले आप अप्लाई करने की प्रक्रिया शुरू कर दें। ऐसा इसलिए क्योंकि आवेदन करने के बाद डॉक्यूमेंट सबमिशन और वेरिफिकेशन में काफी वक्त लगता है। ऐसे में आपको समय पर स्कॉलरशिप भी मिल जाएगा और कोर्स में भी कोई समस्या नहीं होगी।

एप्लीकेशन का कराएं रिव्यू

एप्लीकेशन फॉर्म भरने के बाद यह सबसे बेहतर आइडिया है कि उसका रिव्यू करा लिया जाए। रिव्यू कराने से एप्लीकेशन की कमियां सामने आएगी और उसके बाद सुधार किया जा सकेगा। अपना एप्लीकेशन और डॉक्यूमेंट लें और उसे किसी प्रोफेशनल के पास ले जाएं। ये प्रोफेशनल आपके शिक्षक या कोई अन्य एक्सपर्ट भी हो सकते हैं। इससे आपको रिव्यू मिलेगा और आप एप्लीकेशन में सुधार कर पाएंगे।

अधिक से अधिक रियल रहने का प्रयास करें

जब एप्लीकेशन लिखे तो ज्यादा से ज्यादा रियल रहने का प्रयास करें। यूनिवर्सिटी में आप खुद को निखारने और खुद को बेहतर बनाने के लिए जाते हैं इसी कारण एप्लीकेशन में खुद को ज्यादा बढ़ा-चढ़ा कर ना लिखें। जो हैं वह ईमानदारी के साथ लिखें और अपने स्किल, पैशन और इंटरेस्ट आदि के विषय में लिखें।

पेंट टेक्नोलॉजिस्ट बनकर कॅरियर को दें एक रंगीन दिशा

एक पेंट टेक्नोलॉजिस्ट अलग-अलग एप्लीकेशन के लिए विभिन्न पेंट की उपयुक्तता की पहचान और मूल्यांकन करता है। पेंट टेक्नोलॉजिस्ट ग्राहकों को पेंट के सही उपयोग के बारे में समझाता है और उत्पादों के लिए नए बाजारों की पहचान करता है। रंगों का जीवन से एक गहरा नाता है। रंगों के बिना दुनिया की कल्पना भी नहीं की जा सकती। कपड़ों से लेकर घर तक हर जगह तरह-तरह के रंगों का इस्तेमाल किया जाता है। लेकिन क्या आपने कभी इन्हीं रंगों में अपना करियर बनाने की सोची है। अगर नहीं, तो अब आप इस क्षेत्र में भी अपना भविष्य बना सकते हैं। जी हां, पेंट टेक्नोलॉजी एक ऐसा ही क्षेत्र है। अगर आप भी चाहें तो इस क्षेत्र में अपना सफल भविष्य बना सकते हैं। तो चलिए विस्तार से जानते हैं इस क्षेत्र के बारे में

क्या है पेंट टेक्नोलॉजी

पेंट टेक्नोलॉजी एक ऐसा क्षेत्र है, जिसमें पेंट बनाने के लिए इस्तेमाल होने वाले विभिन्न इंग्रीडिएंट जैसे रॉल, पॉलिमर व पिगमेंट आदि के बारे में अध्ययन किया जाता है। पेंट टेक्नोलॉजी में, विभिन्न प्रकार के पेंट, उनके निर्माण, विभिन्न प्रकार के पेंट के उपयोग और पेंट के अनुप्रयोग के लिए उपयोग की जाने वाली तकनीकों के बारे में अध्ययन किया जाता है। इस विषय क्षेत्र में स्नातक करने वालों को पेंट टेक्नोलॉजिस्ट के रूप में जाना जाता है।

क्या होता है काम

एक पेंट टेक्नोलॉजिस्ट अलग-अलग एप्लीकेशन के लिए विभिन्न पेंट की उपयुक्तता की पहचान और मूल्यांकन करता है। पेंट टेक्नोलॉजिस्ट ग्राहकों को पेंट के सही उपयोग के बारे में समझाता है और उत्पादों के लिए नए बाजारों की पहचान करता है। उनके काम में पेंट के नए रंग और बनावट विकसित करना, पेंट एप्लीकेशन के लिए नई तकनीक को विकसित करना आदि शामिल हैं। सरल भाषा में, वे नए उत्पादों को विकसित करने के साथ-साथ उन उत्पादों के गुणों को बढ़ाने और उन्नत करने के लिए जिम्मेदार हैं जो पहले से ही विकसित किए गए हैं।

पर्सनल स्किल्स

एक पेंट टेक्नोलॉजिस्ट को रंगों से बेहद प्यार होना चाहिए। साथ ही उसमें कई तरह के एक्सपेरिमेंटल स्किल्स भी होने चाहिए, ताकि वह नए रंगों के साथ-साथ उनके टेक्टचर को भी बेहतर बना सके। एक पेंट टेक्नोलॉजिस्ट को मेहनती होना चाहिए। इसके अलावा, आपमें अच्छी संचार कौशल और टीम भावना होनी चाहिए, क्योंकि आपको इस उद्योग में अन्य पेशेवरों के साथ मिलकर काम करने की आवश्यकता होगी। साथ ही विभिन्न विभागों में टीमों का नेतृत्व करने के लिए पेंट टेक्नोलॉजिस्ट में प्रबंधकीय कौशल भी आवश्यक है।

योग्यता

इस क्षेत्र में कदम रखने के लिए आपको बीटेक इन पेंट टेक्नोलॉजी करना होगा। बीटेक के बाद आप एमटेक कर सकते हैं। अधिकांश संस्थानों द्वारा पेंट इंजीनियरिंग पाठ्यक्रमों को केमिकल इंजीनियरिंग में एक विषय के रूप में भी पेश किया जाता है।

संभावनाएं

पेंट उद्योग के विभिन्न विभागों में पेंट टेक्नोलॉजिस्ट की आवश्यकता होती है। वे पेंट निर्माण कंपनियों के किसी भी विभाग में काम पा सकते हैं। पेंट उद्योग मुख्य रूप से ऑटोमोबाइल और रियल एस्टेट उद्योग पर निर्भर है। कई बड़ी-बड़ी पेंट मैन्युफैक्चिरिंग कंपनियों जैसे एशियन पेंट्स इंडिया लिमिटेड, शालीमार पेंट्स, बर्जर पेंट्स इंडिया लिमिटेड, नेरोलैक पेंट्स लिमिटेड आदि में पेंट टेक्नोलॉजिस्ट की हमेशा ही जरूरत होती है। पेंट टेक्नोलॉजिस्ट ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री, होम फर्निशिंग इंडस्ट्री आदि में भी कार्य कर सकते हैं।

आमदनी

इस क्षेत्र में वेतन आपके अनुभव और उस सेक्टर पर निर्भर करता है, जिसके लिए आप काम कर रहे हैं। इस क्षेत्र में शुरुआत करने वाले व्यक्ति प्रारंभ में 1,25000 रूपए से 2,00000 रूपए प्रति वर्ष कमा सकते हैं। इसके अलावा अगर आप किसी प्रतिष्ठित ब्रांड के साथ काम कर रहे हैं तो आपको आकर्षक वेतन मिल सकता है। वहीं, अनुभव बढ़ने के साथ-साथ आपका वेतन भी बढ़ता जाता है।

प्रमुख संस्थान

हरकोर्ट बटलर तकनीकी विश्वविद्यालय, कानपुर
यूनिवर्सिटी इंस्टीट्यूट ऑफ केमिकल टेक्नोलॉजी, जलगांव, महाराष्ट्र
गार्वेयर इंस्टीट्यूट ऑफ कॅरियर एजुकेशन एंड डेवलपमेंट, सांताक्रूज, महाराष्ट्र
लक्ष्मीनारायण इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, नागपुर

राष्ट्रीय/अंतरराष्ट्रीय
प्रमुख समाचार

नारी शक्ति अधिनियम पर पहली महिला राष्ट्रपति का समर्थन

नईदिल्ली। भारत की पूर्व राष्ट्रपति प्रतिभा पाटिल ने 11 अप्रैल को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को पत्र लिखकर नारी शक्ति वंदन अधिनियम (महिला आरक्षण अधिनियम) के प्रति अपना समर्थन व्यक्त किया। उन्होंने कहा कि यह कानून विधायी निकायों में महिलाओं की अधिक भागीदारी सुनिश्चित करके संवैधानिक ढांचे को मजबूत करेगा। पत्र में लिखा था कि नारी शक्ति वंदन अधिनियम के ऐतिहासिक कार्यान्वयन की पहल के लिए मैं हार्दिक आभार व्यक्त करता हूं। यह ऐतिहासिक संवैधानिक संशोधन विधायी निकायों में महिलाओं के अधिक प्रतिनिधित्व और भागीदारी को सुनिश्चित करके भारत के लोकतांत्रिक ढांचे को मजबूत करने की दिशा में एक परिवर्तनकारी कदम है। पाटिल ने कहा कि पहली महिला राष्ट्रपति के रूप में उन्होंने समान अवसर सुनिश्चित करके महिलाओं के सशक्तिकरण का समर्थन किया। उन्होंने इस प्रयास में योगदान देने वाले सभी हितधारकों की भी सराहना की।

कांग्रेस नेता पवन खेड़ा को सुप्रीम कोर्ट से झटका

नईदिल्ली। सुप्रीम कोर्ट ने एक सप्ताह की अग्रिम जमानत देने के तेलंगाना हाई कोर्ट के आदेश को चुनौती देने वाली असम सरकार की याचिका पर कांग्रेस नेता पवन खेड़ा को नोटिस जारी किया है। खेड़ा द्वारा हाई कोर्ट में जमानत के लिए याचिका दायर करने पर असम सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में कहा कि यह प्रक्रिया का पूर्ण दुरुपयोग है। यह मामला एक एफआईआर से जुड़ा है, जिसमें आरोप है कि उन्होंने असम के मुख्यमंत्री हिमंत बिस्वा सरमा की पत्नी पर कई पासपोर्ट रखने का बयान दिया था। न्यायमूर्ति जेके माहेश्वरी और अतुल एस. चंदुरकर की बेंच ने असम सरकार की याचिका पर नोटिस जारी किया और खेड़ा से तीन हफ्ते में जवाब मांगा है। असम सरकार ने तेलंगाना हाईकोर्ट द्वारा दी गई ट्रांजिट बेल को चुनौती दी थी। हालांकि कोर्ट ने यह भी साफ किया कि अगर खेड़ा असम में अग्रिम जमानत के लिए आवेदन करते हैं, तो यह आदेश उनके रास्ते में बाधा नहीं बनेगा। कोर्ट ने कहा कि अगली सुनवाई तीन हफ्ते बाद होगी।

पंजाब सरकार ने राघव चड्ढा की वापस ली जेड+ सुरक्षा

चंडीगढ़। आम आदमी पार्टी (आप) के राज्यसभा सांसद राघव चड्ढा की जेड+ सुरक्षा पंजाब पुलिस द्वारा वापस ले ली गई है। सूत्रों के अनुसार, केंद्रीय सुरक्षा व्यवस्था पर काम चल रहा है। खबरों के मुताबिक, राज्यसभा में पंजाब का प्रतिनिधित्व करने वाले चड्ढा को राज्य सरकार द्वारा जेड+ श्रेणी की सुरक्षा प्रदान की गई थी। हालांकि, पिछले सप्ताह यह सुरक्षा वापस ले ली गई, जबकि आम आदमी पार्टी के भीतर आंतरिक मतभेद की चर्चाएं तेज होती जा रही हैं। पंजाब से चुने गए राघव चड्ढा को राज्य सरकार ने जेड+ सुरक्षा दी थी। यह सुरक्षा पिछले हफ्ते हटा ली गई थी। अब उन्हें केंद्र सरकार की ओर सुरक्षा दी गई है। सूत्रों के अनुसार, केंद्रीय सुरक्षा व्यवस्था की औपचारिक पुष्टि होने तक दिल्ली पुलिस को उनकी सुरक्षा का जिम्मा सौंपा गया है। पार्टी ने हाल ही में उन्हें राज्यसभा में अपने उप-नेता के पद से हटा दिया था। इस कदम पर प्रतिक्रिया देते हुए चड्ढा ने कहा कि उन्हें खामोश किया गया है, हराया नहीं।

परिसीमन दक्षिण भारत के साथ ऐतिहासिक अन्याय : स्टालिन

चेन्नई। तमिलनाडु के मुख्यमंत्री एम.के. स्टालिन ने बुधवार को अपनी पार्टी डीएमके के सांसदों की आपातकालीन बैठक की अध्यक्षता की, क्योंकि वे सरकार द्वारा प्रस्तावित परिसीमन संशोधन विधेयक का लगातार विरोध कर रहे थे। खबरों के अनुसार, उन्होंने राज्य भर में काले झंडे के साथ विरोध प्रदर्शन का आह्वान किया और कहा कि प्रस्तावित संशोधन दक्षिण के खिलाफ एक भयानक ऐतिहासिक अन्याय है। मुख्यमंत्री ने परिसीमन संबंधी चिंताओं को लेकर परिणामों की चेतावनी दी और कहा कि वे ऐसा एक आत्मसम्मानित तमिल और डीएमके प्रमुख के रूप में कर रहे हैं। उन्होंने एक्स पर एक पोस्ट में कहा कि क्या तमिलनाडु और दक्षिणी राज्यों को भारत के विकास के लिए प्रयास करने के अपराध के लिए दंडित किया जा रहा है? केंद्र सरकार द्वारा आज संसद में पेश किया जाने वाला परिसीमन संशोधन विधेयक तमिलनाडु और दक्षिणी राज्यों पर किया गया एक बड़ा ऐतिहासिक अन्याय है।

बंगाल में विधानसभा की 57 सीट पर कांटे का मुकाबला

कोलकाता। पश्चिम बंगाल में विधानसभा की 57 सीटों कड़ा मुकाबला है। पिछले चुनावों में भी इन सीटों पर जीत हार का फासला बेहद कम था। राज्य में हुए एसआईआर के बाद यहां समीकरण बदल सकते हैं और परिणाम को प्रभावित कर सकते हैं। इसके अलावा, इस बार का चुनाव बड़े मुद्दों और नारों के साथ-साथ बूथ मैनेजमेंट पर भी टिका है। 2021 के विधानसभा चुनावों में तृणमूल ने 213 और भाजपा 77 सीटों पर जीत हासिल की थी। 2021 के चुनावों की बात करें तो 57 सीटों पर महज 8,000 वोटों से हार-जीत का फैसला हुआ था। इस बार भी इन्हीं सीटों पर सभी की नजरें टिकी हैं। इन सीटों पर वोट प्रतिशत का थोड़ा बदलाव जीत हार में बड़ा अंतर पैदा कर सकता है। पिछली बार इन 57 में से 29 सीटें ममता बनर्जी और 28 सीटें नरेंद्र मोदी के पाले में गई थीं। इनमें से 19 सीटें ऐसी थीं, जहां प्रत्याशियों की हार-जीत का अंतर 3,000 से भी कम वोटों का रहा था। उन 19 में से 12 भाजपा और 7 सीट तृणमूल के खाते में गई। यानी पिछले मुकाबले में भाजपा का प्रदर्शन बढ़िया रहा।

बिहार में पहली बार भाजपा का मुख्यमंत्री

मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी बोले- मोदी-नीतीश मॉडल ही चलेगा

पटना। सम्राट चौधरी ने बिहार के मुख्यमंत्री के रूप में कार्यभार संभाला, मोदी-नीतीश मॉडल का अनुसरण करने का संकल्प लिया बिहार के नव निर्वाचित मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने शपथ ग्रहण करते ही राज्य के लिए काम शुरू करने की घोषणा की और जोर देकर कहा कि बिहार में शासन मोदी-नीतीश मॉडल पर आधारित होगा। शपथ ग्रहण समारोह के बाद उन्होंने कहा कि मैं आज से ही बिहार के लिए काम शुरू कर दूंगा। बिहार में केवल मोदी-नीतीश मॉडल ही सफल होगा।

नीतीश कुमार के इस्तीफे और राज्यसभा में जाने के बाद चौधरी ने आधिकारिक तौर पर कार्यभार संभाला, जो राज्य में भाजपा के सत्ता में आने के साथ एक महत्वपूर्ण बदलाव का संकेत था। समारोह के तुरंत बाद उन्होंने प्रशासनिक कार्य शुरू कर दिया। पटना में लोक भवन के बाहर समर्थकों ने नारे भी लगाए, हालांकि चौधरी ने दोहराया कि शासन व्यवस्था पूरी तरह से मोदी-नीतीश ढांचे के अनुरूप होगी।केंद्रीय मंत्री जीतन राम मांझी ने नए मुख्यमंत्री पर भरोसा जताते हुए कहा कि चौधरी नीतीश कुमार की विरासत को आगे बढ़ाएंगे और सभी कमियों को दूर करेंगे।

उन्होंने कहा कि चूंकि नीतीश कुमार ने 20 वर्षों तक सरकार चलाई, इसलिए हमें विश्वास है कि अगर कोई खामी रही होगी, तो सम्राट चौधरी उसे पूरा करेंगे और बिहार को आगे ले जाएंगे। उन्होंने यह भी कहा कि उनकी अपनी राजनीतिक यात्रा कुमार के समर्थन से ही तय हुई है। भाजपा नेता दिलीप जायसवाल ने भी इस घटनाक्रम का स्वागत करते हुए कहा कि चौधरी नीतीश कुमार के मार्गदर्शन में विकसित बिहार के सपने को साकार करने की दिशा में काम करेंगे।

यह घटनाक्रम बिहार में पहली बार है जब भाजपा ने वर्षों तक सत्तारूढ़ एनडीए गठबंधन का हिस्सा रहने के बावजूद मुख्यमंत्री का पद हासिल किया है। इससे पहले, नीतीश कुमार चुनावी जीत के बाद भी मुख्यमंत्री बने रहे, लेकिन राज्यसभा में उनके जाने से भाजपा को नेतृत्व संभालने का मौका मिला। चौधरी इससे पहले नीतीश कुमार सरकार में उपमुख्यमंत्री रह चुके हैं। उनके पदोन्नति के बाद, जेडीयू नेता विजय कुमार चौधरी और बिजेंद्र कुमार यादव ने उपमुख्यमंत्री के रूप में शपथ ली। नीतीश कुमार ने लंबे समय से यह संकेत दिया था कि वह चाहते हैं कि चौधरी राज्य में एक बड़ी नेतृत्व भूमिका निभाएं।

मुख्यमंत्री सम्राट दिलाएंगे सफलता, पर नीतीश याद आएंगे : चिराग पासवान

केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान ने बुधवार को बिहार के नए मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी को बधाई देते हुए कहा कि उनके नेतृत्व में राज्य नई ऊंचाइयों को छुएगा और पूर्व मुख्यमंत्री वयोवृद्ध नेता नीतीश कुमार के प्रयासों को आगे बढ़ाएगा। पटना में पत्रकारों से बात करते हुए चिराग पासवान ने कहा कि बिहार के नेता नीतीश कुमार की कमी महसूस करेंगे क्योंकि वे जेडीयू के राज्यसभा सांसद के रूप में अपनी नई भूमिका में जा रहे हैं। पासवान ने कहा कि सम्राट चौधरी को हार्दिक बधाई और शुभकामनाएं। वे मेरे बिहार को अगले चरण में ले जाएंगे। मुझे विश्वास है कि सम्राट चौधरी के नेतृत्व में बिहार यहां से नई ऊंचाइयों को छुएगा। जिस तरह नीतीश कुमार ने बिहार को जंगल राज के दौर से निकालकर आज की स्थिर स्थिति में पहुंचाया, निस्संदेह सम्राट चौधरी के नेतृत्व में हमारी सरकार उनके प्रयासों को आगे बढ़ाएगी। हम निश्चित रूप से नीतीश कुमार की उपस्थिति और राज्य में उनकी सक्रिय भूमिका को याद करेंगे। केंद्रीय राजनीति में उनकी सक्रियता के लिए मैं उन्हें शुभकामनाएं देता हूं। एलजेपी (आरवी) प्रमुख ने कहा कि सम्राट चौधरी ने गठबंधन के सभी साझेदारों के साथ सहमति बनाने के लिए काम किया है। मुझे विश्वास है कि यह क्षमता उनमें है। मुझे उम्मीद है कि वे नीतीश कुमार के कार्यों को आगे बढ़ाएंगे और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के विकसित भारत के लिए विकसित बिहार के निर्माण के संकल्प को पूरा करेंगे।

दक्षिण भारत की चिंता खत्म!

परिसीमन पर केंद्र का वादा, नहीं होगा भेदभाव

नईदिल्ली। केंद्र सरकार ने महिला आरक्षण कानून के कार्यान्वयन को लेकर कई राज्यों द्वारा उठाई गई चिंताओं को दूर करने का प्रयास किया है और आश्वासन दिया है कि इसके लागू होने पर किसी भी क्षेत्र को नुकसान नहीं होगा। केंद्र ने स्पष्ट किया है कि संसदीय सीटों में वृद्धि सभी राज्यों के लिए संतुलित और समानुपातिक तरीके से की जाएगी। सरकारी सूत्रों के अनुसार, प्रस्तावित बदलावों से यह सुनिश्चित होगा कि प्रत्येक राज्य में प्रतिनिधित्व में समान वृद्धि हो। केंद्र ने संकेत दिया है कि राज्यों में सीटों की संख्या में लगभग 50 प्रतिशत की वृद्धि हो सकती है, जिससे विशेष रूप से दक्षिणी राज्यों की उन आशंकाओं का समाधान होगा कि बिहार और उत्तर प्रदेश जैसे अधिक आबादी वाले क्षेत्रों को अनुचित लाभ मिल सकता है।

ये आश्वासन ऐसे समय में आए हैं जब सरकार 16 अप्रैल को संसद में एक महत्वपूर्ण संवैधानिक संशोधन विधेयक पेश करने की तैयारी कर रही है। इस विधेयक का उद्देश्य लोकसभा की सीटों की संख्या को वर्तमान 543 से बढ़ाकर लगभग 850 करना है। प्रस्तावित विधेयक लोकसभा और राज्य विधानसभाओं में महिलाओं के लिए 33 प्रतिशत आरक्षण लागू करने के प्रयासों का हिस्सा है। इसे संभव बनाने के लिए, केंद्र सरकार संविधान के अनुच्छेद 81 में संशोधन करने की योजना बना रही है, जिससे राज्यों से 815 और केंद्र शासित प्रदेशों से 35 तक सदस्य निर्वाचित हो सकेंगे।

महिलाओं के लिए आरक्षण लागू होने से पहले परिसीमन प्रक्रिया होने की उम्मीद है, जिसके तहत जनसंख्या और अन्य कारकों के आधार पर निर्वाचन क्षेत्रों की सीमाओं का पुनर्निर्धारण किया जाएगा। इस प्रक्रिया को लेकर कुछ राज्यों में राजनीतिक प्रतिनिधित्व में संभावित बदलाव को लेकर चिंताएं जताई गई थीं। सरकार ने कहा कि विधेयक से संबंधित विस्तृत जानकारी और स्पष्टीकरण संसद में चर्चा के दौरान साझा किए जाएंगे।

संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने परिसीमन के मुद्दे पर दक्षिण भारतीय राज्यों को गुमराह करने वालों के खिलाफ चेतावनी जारी की है। उन्होंने ङ्क पर पोस्ट किया कि कुछ लोग गलत परिसीमन आंकड़े देकर दक्षिण भारतीय राज्यों को महिला आरक्षण के मुद्दे पर गुमराह करने की कोशिश कर रहे हैं। लोकसभा और विधानसभाओं में महिलाओं को आरक्षण देने में राजनीति नहीं होनी चाहिए। सभी राजनीतिक दल नारी शक्ति के लिए एकजुट हैं।

दिल्ली छीन रही जनता से वोट देने का अधिकार: ममता

मुख्यमंत्री ने बंगाली नववर्ष पर लोगों को दी बधाई

कोलकाता। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ने बंगाली नववर्ष के खास मौके पर राज्य के लोगों से बड़ी अपील की है। उन्होंने लोगों से केंद्र सरकार की मनमानी का विरोध करने और बंगाल की आपसी भाईचारे की परंपरा को बनाए रखने को कहा।

ममता बनर्जी ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म %एक्स% पर राज्य के लोगों को बंगाली नववर्ष की शुभकामनाएं दीं। उन्होंने लिखा कि नए साल की इस सुबह में हर किसी का जीवन दुखों से मुक्त हो। उन्होंने कामना की कि इस नई पुकार के साथ हर इंसान का मन पवित्रता से भर जाए।

इसके साथ ही मुख्यमंत्री ने केंद्र सरकार पर निशाना साधते हुए केंद्र सरकार पर जनता के वोट देने के अधिकार को कम करने का आरोप लगाया। उन्होंने नागरिकों से कहा कि वे इसका जवाब लोकतांत्रिक तरीके से दें। ममता ने कहा कि हमारा बंगाल कला और संस्कृति का केंद्र होने के साथ-साथ सभी धर्मों के बीच सद्भाव की धरती भी है। उन्होंने चेतावनी दी कि कुछ बुरी ताकतें बंगाल को भ्रष्ट करने के लिए खड़ी हो गई हैं। उन्होंने कहा कि दिल्ली में बैठे शासक लोगों के अधिकार छीन रहे हैं, जिन्हें सबक सिखाना जरूरी है।

ममता बनर्जी ने लोगों से विभाजनकारी और तानाशाही प्रवृत्तियों को रोकने का संकल्प लेने को कहा। उन्होंने अपील की कि इस शुभ दिन पर हम सब मिलकर एक शपथ लें। हमें हर तरह की संकीर्ण सोच की दीवारों को तोड़कर आगे बढ़ना होगा। उन्होंने उम्मीद जताई कि कोई भी विभाजनकारी ताकत हमारी शांति, पारंपरिक सद्भाव और दोस्ती के बंधन को नहीं तोड़ पाएगी।

अंत में मुख्यमंत्री ने आने वाले विधानसभा चुनावों में तृणमूल कांग्रेस (टीएमसी) के उम्मीदवारों को समर्थन देने की अपील की। उन्होंने मतदाताओं से कहा कि अपने लोकतांत्रिक अधिकारों की रक्षा के लिए जोड़ा फूल के निशान पर वोट दें। साथ ही उन्होंने विश्वास जताया कि तृणमूल कांग्रेस के सभी उम्मीदवार भारी अंतर से जीत हासिल करेंगे।

पश्चिम बंगाल में 2026 के चुनावों से पहले ममता बनर्जी और बीजेपी के बीच जुबानी जंग तेज हो गई है। ममता ने बीजेपी पर लोकतंत्र को कमजोर करने का आरोप लगाया है। वहीं, बीजेपी ने घुसपैठ और खराब शासन का मुद्दा उठाकर उन पर पलटवार किया है।

खेल
प्रमुख समाचार

बैडमिंटन खिलाड़ी विक्टर एक्सेलसन ने लिया संन्यास

कोपेनहेगन। दो बार के ओलंपिक और विश्व चैंपियन डेनमार्क के दिग्गज बैडमिंटन खिलाड़ी विक्टर एक्सेलसन ने बुधवार को अचानक संन्यास का ऐलान कर दिया है। लगातार चोटिल होने के कारण उन्हें यह फैसला करना पड़ा। 32 वर्षीय इस खिलाड़ी ने पिछले साल अक्टूबर से पीठ की समस्या के कारण किसी भी प्रतियोगिता में भाग नहीं लिया था। उन्होंने इसके लिए सर्जरी भी कराई लेकिन उनका दर्द अब भी बना रहता है।

तीन बार के यूरोपीय चैंपियन एक्सेलसन ने 'बैडमिंटन यूरोप' से कहा कि, जैसा कि अधिकतर लोग जानते हैं कि मैं काफी समय से अपनी पीठ की समस्या से जूझ रहा हूं। पिछले साल अप्रैल में सर्जरी कराने और लंबे समय तक 'रिहैबिलिटेशन' से गुजरने के बाद दुर्भाग्य से अक्टूबर में यह दर्द फिर से उबर गया।

उन्होंने कहा कि, दर्द के कारण मैं खेल नहीं पा रहा हूं और अभ्यास भी नहीं कर पा रहा हूं। इस कारण मुझे यह बेहद मुश्किल फैसला लेने के लिए मजबूर होना पड़ा। एक्सलसेन 183 सप्ताह तक विश्व में नंबर एक खिलाड़ी रहे हैं और वह इस मामले में तीसरे स्थान पर काबिज हैं। उन्होंने कहा कि दर्द कम न होने और डॉक्टरों का खेल जारी रखने पर एक और सर्जरी की चेतावनी दिए जाने के बाद आखिर में उन्हें अपने शरीर की बात सुननी पड़ी।

एक्सेलसन ने तोक्यो और पेरिस ओलंपिक में लगातार गोल्ड मेडल जीते और 2017 और 2022 विश्व चैंपियनशिप में शीर्ष स्थान हासिल किया। वह यूरोपीय चैंपियनशिप में गोल्ड जीतने वाली डेनमार्क की छह टीमों का भी हिस्सा रहे। उन्होंने कहा कि, मैंने यह फैसला डॉक्टरों से परामर्श करने के बाद लिया है। उनका कहना है कि मुझे अभी जो दर्द हो रहा है, उसके लिए शायद एक और सर्जरी करवानी पड़े। अगर सर्जरी सफल नहीं रही तो इससे भी गंभीर प्रक्रिया से गुजरना पड़ सकता है।

आर्थिक/वाणिज्य/विज्ञान/
प्रमुख समाचार

सेंसेक्स 1263 अंक चढ़ा निफ्टी 24231 पर बंद

नईदिल्ली। एशियाई बाजारों में पॉजिटिव रुख के बीच भारतीय शेयर बाजार बुधवार (15 अप्रैल) को जोरदार बढ़त के साथ बंद हुए। अमेरिका और ईरान के बीच बातचीत एक बार शुरू होने की खबरों का निवेशकों के सेंटीमेंट्स पर पॉजिटिव असर पड़ा। तीस शेयरों वाला बीएसई सेंसेक्स 77,981 अंक पर खुला। जबकि सोमवार को यह 76,847 पर बंद हुआ था। कारोबार के दौरान यह 78,270 अंक तक चढ़ गया था। अंत में यह 1263.67 अंक या 1.64 फीसदी की बढ़त लेकर 78,111.24 पर बंद हुआ। इसी तरह, नैशनल स्टॉक एक्सचेंज का निफ्टी-50 भी जोरदार मजबूती के साथ 24,163 पर खुला और इसी के साथ 24 हजार के मनोवैज्ञानिक स्तर के पार निकल गया। कारोबार के दौरान इसने 24,280 अंक का इंट्रा-डे हाई बनाया। अंत में 388.65 अंक या 1.63 फीसदी की बढ़त के साथ 24,231 पर बंद हुआ।

मार्च में थोक महंगाई 3.88% पर पहुंची, 3 साल का उच्च स्तर

नईदिल्ली। भारत में थोक कीमतें मार्च महीने में सालाना आधार पर 3.88 प्रतिशत बढ़ गईं, जो तीन साल से ज्यादा समय में सबसे तेज बढ़ोतरी है। सरकार की तरफ जारी आंकड़ों के अनुसार, तेल, खाने-पीने की चीजों और मैन्युफैक्चर्ड सामान की कीमतों में बढ़ोतरी की वजह से मार्च के दौरान महंगाई बढ़ी है। यह आंकड़ा फरवरी के 2.13 प्रतिशत से ज्यादा है और अर्थशास्त्रियों के 3.04 प्रतिशत के अनुमान से भी ऊपर रहा। थोक मूल्य सूचकांक आधारित महंगाई दर पिछले महीने 2.13 प्रतिशत थी, जबकि पिछले साल मार्च में यह 2.25 प्रतिशत रही थी। उद्योग मंत्रालय ने एक बयान में कहा कि मार्च 2026 में महंगाई की सकारात्मक दर मुख्य रूप से कच्चे पेट्रोलियम और नैचुरल गैस, अन्य मैन्युफैक्चर्ड उत्पादों, गैर-खाद्य वस्तुओं, बेसिक मेटल्स और खाद्य वस्तुओं की कीमतों में बढ़ोतरी के कारण रही है।

आईएमएफ ने बढ़ाया भारतीय अर्थव्यवस्था का ग्रोथ रेट अनुमान

नईदिल्ली। अंतरराष्ट्रीय मुद्राकोष (आईएमएफ) ने कहा कि पश्चिम एशिया में बढ़ते तनाव के बावजूद भारत की अर्थव्यवस्था वर्ष 2026 में 6.5 प्रतिशत की दर से बढ़ने की संभावना है। आईएमएफ ने अपनी वैश्विक आर्थिक परिदृश्य रिपोर्ट में यह अनुमान जताते हुए कहा कि इस साल 6.5 प्रतिशत की वृद्धि दर के साथ भारत प्रमुख अर्थव्यवस्थाओं में सबसे तेजी से बढ़ने वाली अर्थव्यवस्था बना रहेगा। मुद्राकोष ने भारत के संदर्भ में कहा, वर्ष 2026 के लिए वृद्धि अनुमान में 0.3 प्रतिशत अंक की हल्की बढ़ोतरी की गई है। इसके पीछे 2025 के मजबूत प्रदर्शन का असर और भारतीय वस्तुओं पर अमेरिकी शुल्क को 50 प्रतिशत से घटाकर 10 प्रतिशत किए जाने जैसे कारक हैं। इन कारकों ने पश्चिम एशिया संघर्ष के नकारात्मक प्रभाव को काफी हद तक संतुलित कर दिया है।

स्टील कंपनियों को चौथी तिमाही में मुनाफा की उम्मीद

नईदिल्ली। लंबे समय की सुस्ती और दबाव के बाद अब मेटल सेक्टर में जबरदस्त वापसी के संकेत मिल रहे हैं। चौथी तिमाही (Q4FY26) स्टील कंपनियों के लिए खास तौर पर मजबूत साबित हो सकती है। कीमतों में तेजी, मजबूत मांग और बेहतर बिक्री के कारण कंपनियों की आय और मुनाफे में बड़ा सुधार देखने को मिल सकता है। हालांकि एल्युमिनियम सेक्टर की तस्वीर अभी भी पूरी तरह साफ नहीं है और वहां कंपनी-विशेष चुनौतियां बनी हुई हैं। इस तिमाही में स्टील की कीमतों ने बाजार का पूरा माहौल बदल दिया है। दिसंबर 2025 में जहां कीमतें करीब 46,500 रुपये प्रति टन तक गिर गई थीं, वहीं अब वे बढ़कर लगभग 57,500 रुपये प्रति टन तक पहुंच चुकी हैं। स्टील की मांग में लगातार मजबूती बनी हुई है।

समृद्धि का सुपर-एक्सप्रेस-वे है दिल्ली-देहरादून इकोनॉमिक कॉरिडोर

जयसिंह रावत

राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली से उत्तर प्रदेश के पश्चिमी अंचल होते हुए उत्तराखंड की वादियों तक पहुंचने वाला दिल्ली-देहरादून इकोनॉमिक कॉरिडोर केवल एक सड़क परियोजना नहीं, बल्कि उत्तर भारत की नई इकोनॉमिक आर्टरी (आर्थिक धमनी) है।

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा राष्ट्र को समर्पित यह कॉरिडोर तीन राज्यों के आपसी समन्वय, व्यापार और पर्यटन के अंतर्संबंधों को एक नया धरातल प्रदान करता है। 11,963 करोड़ रुपए की भारी-भरकम लागत से तैयार यह 213 किलोमीटर लंबा एक्सप्रेस-वे न केवल भौगोलिक दूरियों को कम करेगा, बल्कि दिल्ली, उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड के सामाजिक-आर्थिक ताने-बाने को एक सूत्र में पिरोएगा। यह कॉरिडोर दिल्ली की भीड़भाड़ और प्रदूषण को कम करने, उत्तर प्रदेश के पश्चिमी जिलों (बागपत, शामली, सहारनपुर) में औद्योगिक गतिविधियों को गति देने और उत्तराखंड की आर्थिकी को संजीवनी देने का एक साझा मंच है। दिल्ली के व्यापारियों के लिए अब उत्तराखंड और पश्चिमी यूपी की मंडियां महज कुछ घंटों की दूरी पर होंगी। उत्तर प्रदेश के जिन जिलों से यह कॉरिडोर गुजर रहा है, वहां के कृषि आधारित उद्योगों और लघु उद्योगों (एमएसएमई) के लिए यह एक वरदान है।

सहारनपुर के लकड़ी शिल्प से लेकर पश्चिमी यूपी के चीनी और कृषि बेल्ट तक, लॉजिस्टिक लागत में होने वाली 19 प्रतिशत की कमी सीधे तौर पर उत्पादकों की जेब में मुनाफे के रूप में जाएगी। यह कॉरिडोर भारत के उस ग्रोथ इंजन को शक्ति देगा जो राज्यों की सीमाओं से परे साझा विकास की बात करता है। उत्तराखंड की आर्थिकी के लिए यह ग्रीन हाईवे एक क्रांतिकारी बदलाव है। पहाड़ के उत्पाद—चाहे वे हर्षिल के सेब हों, चकराता की राजमा हो या बुरांश का जूस—अब दिल्ली और एनसीआर के ड्राइंग रूम तक अपनी ताज़गी खोए बिना पहुंच सकेंगे।

यह कॉरिडोर केवल माल की ढुलाई नहीं करेगा, बल्कि पलायन जैसी गंभीर समस्या का समाधान भी लाएगा। जब गाँव के उत्पाद को शहर की मंडी तेजी से मिलेगी, तो किसान आत्मनिर्भर बनेगा। कॉरिडोर के किनारे विकसित होने वाले एग्री-लॉजिस्टिक्स हब और वेयरहाउसिंग प्रोजेक्ट्स स्थानीय युवाओं के लिए रोजगार के वे अवसर पैदा करेंगे, जिनकी तलाश में उन्हें अब तक महानगरों का रुख करना पड़ता था। दिल्ली और उत्तर प्रदेश के निवासियों के लिए उत्तराखंड हमेशा से एक पसंदीदा पर्यटन स्थल रहा है, लेकिन सड़कों का भारी दबाव और यात्रा की लंबी अवधि अक्सर बाधा बनती थी। अब दिल्ली से देहरादून का सफर ढाई घंटे में सिमटने से वीकेंड टूरिज्म को अभूतपूर्व बढ़ावा मिलेगा।

इसका लाभ केवल मसूरी या ऋषिकेश तक सीमित नहीं रहेगा, बल्कि यह पर्यटकों को उत्तराखंड के अनछुए गंतव्यों—जैसे टिहरी की झील, उत्तरकाशी की घाटियाँ और राजाजी नेशनल पार्क के बफर जोन तक—आसानी से पहुँचाएगा। सुगम कनेक्टिविटी का सीधा अर्थ है—होटल, होमस्टे, टैक्सी और हस्तशिल्प व्यवसाय में निवेश की नई लहर। इस प्रोजेक्ट की जो बात इसे वैश्विक स्तर पर खास बनाती है, वह है विकास और पर्यावरण के बीच का संतुलन। एक्सप्रेस-वे का आखिरी 20 किलोमीटर का हिस्सा घने वन क्षेत्रों से गुजरता है। यहां इंजीनियरिंग का चमत्कार दिखता है—12 किलोमीटर लंबा एलिवेटेड वाइल्ड लाइफ कॉरिडोर। यह एशिया का सबसे लंबा ऐसा कॉरिडोर है जहाँ ऊपर से गाड़ियाँ दौड़ेंगी और नीचे बिना किसी बाधा या शोर के हाथी, गुलदार और अन्य वन्यजीव स्वच्छंद विचरण करेंगे। भारतीय वन्य जीव संस्थान के सहयोग से तैयार यह मॉडल भविष्य की सड़क परियोजनाओं के लिए एक मिसाल है। यह कॉरिडोर न केवल ध्वनि और वायु प्रदूषण को न्यूनतम करता है, बल्कि अगले 20 वर्षों में 2.44 मिलियन टन कार्बन उत्सर्जन कम कर पर्यावरण संरक्षण के प्रति भारत की प्रतिबद्धता को भी दोहराता है। देहरादून में प्रधानमंत्री के भव्य स्वागत और 12 किलोमीटर लंबी मानव श्रृंखला ने यह स्पष्ट कर दिया है कि जनता इस कॉरिडोर को अपने सुनहरे भविष्य के मार्ग के रूप में देख रही है।

शिक्षा के अधिकार को पारदर्शी डिजिटल प्रक्रिया से मिला नया विस्तार: सीएम साय

■ आरटीई के तहत 14,403 बच्चों को निजी स्कूलों में मिला प्रवेश, ऑनलाइन लॉटरी बनी सुशासन का उदाहरण

रायपुर। छत्तीसगढ़ में समावेशी और गुणवत्तापूर्ण शिक्षा को सशक्त आधार देने की दिशा में एक महत्वपूर्ण और दूरदर्शी पहल करते हुए मुख्यमंत्री श्री विष्णु देव साय ने शिक्षा का अधिकार (आरटीई) अधिनियम के अंतर्गत निजी विद्यालयों में प्रवेश हेतु ऑनलाइन लॉटरी प्रक्रिया के माध्यम से 14,403 बच्चों का चयन सुनिश्चित किया। मंत्रालय महानदी भवन से वर्चुअल माध्यम से प्रारंभ हुई यह प्रक्रिया पारदर्शिता, समान अवसर और डिजिटल सुशासन की प्रतिबद्धता का सशक्त उदाहरण बनकर सामने आई है।

राज्यभर से प्राप्त कुल 38,439 आवेदनों में से 27,203 आवेदन निर्धारित मानकों के अनुरूप पात्र पाए गए, जिनमें से ऑनलाइन लॉटरी के माध्यम से 14,403 बच्चों को निजी विद्यालयों में प्रवेश प्रदान किया गया। यह पूरी प्रक्रिया पूर्व निर्धारित समय-सारिणी के अनुसार राज्य स्तर पर सुव्यवस्थित रूप से संपन्न हुई, जिसमें शिक्षा मंत्री श्री गजेंद्र यादव सहित विभागीय वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित थे। मुख्यमंत्री साय ने कहा कि शिक्षा प्रत्येक बच्चे का मौलिक अधिकार है और राज्य सरकार यह सुनिश्चित करने के लिए पूरी तरह प्रतिबद्ध है कि किसी भी बच्चे की प्रगति आर्थिक अभाव के कारण बाधित न हो। हमारी प्राथमिकता है कि हर बच्चे को समान अवसर के साथ गुणवत्तापूर्ण शिक्षा प्राप्त हो।

उल्लेखनीय है कि आरटीई प्रावधानों के तहत निजी विद्यालयों में 25 प्रतिशत सीटें आर्थिक रूप से कमजोर एवं वंचित वर्ग के बच्चों के लिए आरक्षित की गई हैं। इस योजना के माध्यम से राज्य सरकार समाज के अंतिम छोर पर खड़े बच्चों तक शिक्षा की रोशनी पहुंचाने का सतत प्रयास कर रही है। वर्तमान में इस योजना के अंतर्गत प्रदेश के 3 लाख 63 हजार से अधिक विद्यार्थी लाभान्वित हो रहे हैं।

राज्य सरकार द्वारा वर्ष 2026-27 के लिए इस योजना के अंतर्गत शुल्क प्रतिपूर्ति राशि को बढ़ाकर 300 करोड़ रुपये कर दिया गया है, जिससे अधिक से अधिक बच्चों को इस योजना का लाभ मिल सके और निजी विद्यालयों में उनके प्रवेश की प्रक्रिया और सुदृढ़ हो। पूरी प्रवेश प्रक्रिया को डिजिटल माध्यम से संचालित किया जा रहा है, जिसमें आवेदन से लेकर दस्तावेज सत्यापन और चयन तक के सभी चरण पूर्णतः पारदर्शी और तकनीक आधारित हैं। अभिभावक स्वयं या चॉइस सेंटर के माध्यम से आवेदन कर सकते हैं। आवेदन के दौरान ही सिस्टम द्वारा निवास क्षेत्र से 1.5 किलोमीटर के दायरे में स्थित निजी विद्यालयों की जानकारी एवं उपलब्ध सीटों का विवरण प्रदर्शित किया जाता है, जिससे अभिभावकों को सूचित एवं सहज चयन का अवसर प्राप्त होता है। पात्रता के अनुसार 5.5 से 6.5 वर्ष आयु वर्ग के बच्चों को कक्षा पहली में प्रवेश दिया जाएगा, जबकि अनुसूचित जाति, जनजाति, दिव्यांग एवं अन्य कमजोर वर्गों को प्राथमिकता प्रदान की जाती है।

पीएनबी ने कुलदीप निगम वृद्धाश्रम में किया अन्नदान

रायपुर । राजधानी रायपुर में सामाजिक सरोकार की एक प्रेरणादायक पहल देखने को मिली, जहां पंजाब नेशनल बैंक ने माना स्थित कुलदीप निगम वृद्धाश्रम में अन्नदान कर बुजुर्गों के प्रति अपनी जिम्मेदारी निभाई।

बैंक के रायपुर द्वारा आयोजित इस सेवा कार्य के तहत आश्रम में चावल, दाल, आटा, खाने का तेल, सोया बड़ी, छोले, राजमा, आलू सहित अन्य आवश्यक खाद्य सामग्री प्रदान की गई। इसके अलावा कुकर और पीवीसी पाइप जैसी उपयोगी वस्तुएं भी दान में दी गई।इस अवसर पर मंडल प्रमुख वीरेंद्र कुमार शर्मा ने आश्रम परिसर का निरीक्षण किया और वहां रह रहे बुजुर्गों से मुलाकात कर उनका हालचाल जाना। उन्हें आश्रम की स्थापना से लेकर अब तक की गतिविधियों की जानकारी दी गई। उन्होंने बुजुर्गों की सेवा के लिए संचालित कार्यों की सराहना करते हुए भविष्य में भी हर संभव सहयोग का भरोसा दिलाया।

कार्यक्रम में आश्रम के पदाधिकारी और अन्य लोग भी मौजूद रहे। यह पहल न केवल जरूरतमंदों की मदद का उदाहरण है, बल्कि समाज में सेवा और संवेदनशीलता का संदेश भी देती है।

बोर्ड के नाम पर धोखाधड़ी करने वाले स्कूलों पर होगी कार्रवाई: मंत्री गजेंद्र

रायपुर। छत्तीसगढ़ में निजी स्कूलों द्वारा सीजी बोर्ड की मान्यता लेकर ष्टक्चस्श्व पैटर्न का झांसा देकर मनमानी फीस वसूली का मामला लल्लूराम डॉट कॉम ने प्रमुखता से उठाया था। इस मामले में लोक शिक्षण संचालनालय ने संज्ञान लिया है और सभी संभागीय संयुक्त संचालक शिक्षा को पत्र जारी कर मान्यता प्राप्त निजी स्कूलों की तीन सालों की फीस निर्धारण की रिपोर्ट मांगी है। बता दें कि निजी स्कूलों में हर साल शुल्क, पुस्तक और ड्रेस के नाम पर सैकड़ों करोड़ वसूली की जा रही है, जिससे पालक परेशान हैं।

वहीं इस मामले में शिक्षा मंत्री गजेंद्र यादव ने कहा है कि सीजी बोर्ड की मान्यता में सीबीएसई पाठ्यक्रम बताकर धोखा देना अपराध है। पूरा 400 क्चष्ट का मामला है। ष्टक्चस्श्व पैटर्न बताकर कोई भी धोखा नहीं दे सकता। ऐसे स्कूलों पर जल्द ही कार्रवाई की जाएगी। इसके लिए अधिकारियों को निर्देशित किया जा चुका है। मंत्री ने कहा, सीजी बोर्ड के स्कूलों में सीबीएसई का किताब ही चलेगा। बाहरी प्रकाशनों के किताब के नाम पर दुकानदारी नहीं चलेगी। जो निर्धारित पुस्तक है उसी पाठ्यक्रम में पढ़ाई होगी।

चौंकाने वाले आंकड़े

राज्य में कुल 57053 स्कूल हैं, जिनमें 6800 निजी स्कूल है। इनमें 6100 सीजी बोर्ड हिंदी-अंग्रेजी माध्यम है, 520 वास्तविक ष्टक्चस्श्व संबद्ध और मात्र 24 ढ्ढष्टस्श्व हैं। नवंबर में पाठ्य पुस्तक निगम के अध्यक्ष ने 1784 सीजी बोर्ड मान्यता प्राप्त स्कूलों की सूची जारी की थी, जिसमें लिखा है कि इन स्कूलों ने निशुल्क किताबें नहीं लीं है. बदले में महंगी किताबें बेची गई है।

प्रदेशभर में सीजी बोर्ड की निःशुल्क पुस्तक नहीं लेने वाले स्कूलों की संख्या: रायपुर -107, बिलासपुर 157, दुर्ग 135, जांजगीर-चंपा 106, सूरजपुर 106, सरगुजा 85, बलौदाबाजार-भाटापारा -43, गरियाबंद 25, धमतरी-31 महासमुंद 66, मुंगेली 74, रायगढ़ 73, कोरबा- 89, गौरेला-पेंड्रा-मरवाही -23, सक्ती 89, सारंगढ़-बिलाईगढ़-45, बालोद 36, बेमेतरा, 43, कबीरधाम (कवर्धा), 36, राजनांदगांव 51, खैरागढ़-छुईखदान-गंडई, 15, मोहला-मानपुर-अंबागढ़ चौकी 12, कोरिया 30, बलरामपुर-रामानुजगंज 39, जशपुर 72, मनेंद्रगढ़-चिरमिरी-भरतपुर 42, बस्तर 40, कोंडागांव 17, नारायणपुर 6, कांकेर 47, दंतेवाड़ा, बीजापुर 7, सुकमा 4.

सड़क सुरक्षा के साथ शिक्षा की राह भी रोशन कर रहा एनएचएआई

रायपुर। भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण क्षेत्रीय कार्यालय, रायपुर और एनएचआईटी ने सामाजिक सरोकार की दिशा में शासकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय, तरपोंगी में विद्यार्थियों को निशुल्क पावर चश्मों का वितरण किया। गौरतलब है कि सड़क सुरक्षा अभियान के तहत पूर्व में विद्यालय परिसर में नेत्र जांच शिविर का आयोजन किया गया था, जिसमें कुल 517 विद्यार्थियों की आंखों का विशेषज्ञों द्वारा परीक्षण किया गया। इस जांच के दौरान जिन 42 बच्चों की दृष्टि कमजोर पाई गई थी, आज उन्हें उनकी आवश्यकता और निर्धारित पावर के अनुसार उच्च गुणवत्ता वाले चश्मे सौंपे गए। एनएचएआई के क्षेत्रीय अधिकारी प्रदीप कुमार लाल ने कहा कि एनएचएआई का उद्देश्य केवल सड़कों का निर्माण करना नहीं है। बल्कि उन सड़कों पर चलने वाली अगली पीढ़ी के भविष्य को भी सुरक्षित और उज्ज्वल बनाना है।

हर छात्र बनेगा बच्चों के अधिकारों का प्रहरी : डॉ. वर्णिका

रायपुर। छत्तीसगढ़ राज्य बाल अधिकार संरक्षण आयोग, रायपुर द्वारा रक्षक पाठ्यक्रम को राज्य में प्रभावी रूप से लागू करने की दिशा में सतत प्रयास किए जा रहे हैं। रक्षक पाठ्यक्रम एक विशेष शैक्षणिक पहल है, जिसका उद्देश्य महाविद्यालयीन विद्यार्थियों के माध्यम से बाल अधिकारों के प्रति जागरूकता बढ़ाना, बच्चों की सुरक्षा सुनिश्चित करना तथा समाज में बाल संरक्षण के प्रति संवेदनशीलता विकसित करना है। इस पाठ्यक्रम के क्रियान्वयन हेतु पूर्व में मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय की उपस्थिति में महिला एवं बाल विकास मंत्री श्रीमती लक्ष्मी रजवाड़े तथा उच्च शिक्षा मंत्री टंक राम वर्मा के सहयोग से एमओयू संपन्न किया गया था। यह एमओयू राज्य के उच्च शिक्षण संस्थानों में रक्षक पाठ्यक्रम को लागू करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम रहा है, जिससे विद्यार्थियों को बाल अधिकारों और सुरक्षा संबंधी विषयों में प्रशिक्षित किया जा सके। इसी क्रम में बुधवार को एक निजी होटल में रक्षक पाठ्यक्रम के अंतर्गत तैयार उप-इकाइयों को अंतिम रूप प्रदान करने हेतु विश्वविद्यालयीन परामर्श बैठक का आयोजन किया गया। बाल सुरक्षा की पढ़ाईकार्यक्रम की शुरुआत दीप प्रज्वलन के साथ हुई, जिसके पश्चात आयोग के सचिव प्रतीक खरे एवं आयोग की डायरेक्टर संगीता बिंद द्वारा उपस्थित कुलपतियों, कुलसचिवों एवं प्रतिनिधियों का स्वागत किया गया। जिसके पश्चात आयोग की अध्यक्ष डॉ. वर्णिका शर्मा ने अपने संबोधन में कहा कि रक्षक पाठ्यक्रम केवल एक शैक्षणिक कार्यक्रम नहीं, बल्कि बच्चों के अधिकारों की सुरक्षा के लिए एक सशक्त सामाजिक अभियान है।

छत्तीसगढ़/राजधानी

प्रमुख समाचार

अधिकारों पर डाका डालने की कोशिश: दीपक बैज

रायपुर। साय मंत्रिमंडल ने यूसीसी लागू करने के लिए एक कमेटी का गठन किया है। प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष दीपक बैज ने कहा कि अगर छत्तीसगढ़ में यूसीसी लागू होता तो सबसे बड़ा नुकसान छत्तीसगढ़ के आदिवासियों को होगा। यूसीसी छत्तीसगढ़ के आदिवासियां के खिलाफ है,

राज्य में केवल आदिवासी ही ऐसे है जिन्हें प्रदेश में निवासरत अन्य लोगों की अपेक्षा विशेष संवैधानिक संरक्षण मिला हुआ है। इसके अलावा कोई भी वर्ग छत्तीसगढ़ में नहीं है जिसके लिए विशेष नागरिक प्रावधान लागू है। छत्तीसगढ़ में 32 प्रतिशत से अधिक आबादी आदिवासियों की है, संरक्षित जनजातियां है, जिन्हें संविधान में कुछ विशेष अधिकार मिले है। उनकी रक्षा के लिए पेसा कानून लागू है और 5 अनुसूची लागू है और भाजपा यूसीसी लाकर आदिवासियों के हितों में डकैती डालने की कोशिश में है। जब से बस्तर में नक्सलवाद खत्म होने की घोषणा हुई है उसके बाद से ही भाजपा के समर्थित उद्योगपति बस्तर में आदिवासियों की जमीन पर नजरे गड़ाये हुए है। बस्तर में भाजपा के समर्थित उद्योगपतियों की नजर लग चुकी है और वह आदिवासियों की जमीन हड़पना चाहते है। यूसीसी लाने की कवायद इसीलिए है।

नारी शक्ति वंदन अधिनियम कार्यक्रम झूठा : शुक्ला

रायपुर। नारी शक्ति वंदन अधिनियम के लिए भाजपा के द्वारा किये जा रहे कार्यक्रम का झूठा श्रेय लेने की कवायद है। प्रदेश कांग्रेस संचार विभाग के अध्यक्ष सुशील आनंद शुक्ला ने कहा कि महिलाओं की विधानमंडलों में आरक्षण कांग्रेस की समतावादी सोच का परिणाम है। भाजपा की विचारधारा तो महिला आरक्षण की विरोधी रही है। कांग्रेस की पूर्व

राष्ट्रीय अध्यक्ष सोनिया गांधी और राहुल गांधी हमेशा से प्रयत्नशील थे कि महिलाओं को उनका पूरा अधिकार मिले। कांग्रेस की यूपीए सरकार ने इस हेतु ठोस प्रयास भी किया था। महिलाओं के लिए संसद और राज्यों की विधानसभाओं में एक तिहाई आरक्षण के लिए तत्कालीन प्रधानमंत्री डॉ. मनमोहन सिंह संविधान संशोधन विधेयक लाए। विधेयक 9 मार्च 2010 को राज्यसभा में पारित हुआ।प्रदेश कांग्रेस संचार विभाग के अध्यक्ष सुशील आनंद शुक्ला ने कहा कि भाजपा राजनैतिक मजबूरी के कारण आरक्षण बिल लाने जा रही है। भाजपा की नरेंद्र मोदी सरकार अपनी जनविरोधी नीतियों के कारण अलोकप्रिय हो चुकी हे। मोदी सरकार के विफलता के कारण देश में महंगाई, बेरोजगारी चरम पर है। महंगाई से सबसे ज्यादा परेशान महिलाएं है। महिलाओं की नाराजगी दूर करने नारी शक्ति वंदन अधिनियम लाया जा रहा है।

गैस की कमी नहीं फिर एजेंसियों में लाइन क्यों : ठाकुर

रायपुर। रसोई गैस संकट पर सवाल खड़ा करते हुए प्रदेश कांग्रेस के वरिष्ठ प्रवक्ता धनंजय सिंह ठाकुर ने कहा कि सरकार दावा कर रही है कि रसोई गैस की कोई कमी नही है, फिर शहरी क्षेत्रों में रसोई गैस के लिए जनता लाईन में क्यों खड़ी है? 25 दिन की समय सीमा तय लेकिन 30 दिन

बाद भी रसोई गैस की आपूर्ति क्यों नही हो रही है? शहरी क्षेत्रों को 25 दिन और ग्रामीण क्षेत्रों को 45 दिन बाद दोबारा रसोई गैस की समय सीमा क्यों? ये भेदभाव क्यों? रसोई गैस की कमी नहीं फिर कई गैस एजेंसियां में ताला क्यों लगा है? जनता विरोध प्रदर्शन क्यों कर रही है? विवाद हो रहा है? ग्रामीण क्षेत्रों में भी पूरा खाना रसोई गैस से बनता है, एक सिलेंडर 25-से 28 दिन में खत्म हो जा रहे है ऐसे में सिलेंडर खत्म होने के बाद ग्रामीण भोजन किसमें बनाये? लकड़ी वैसे ही नहीं मिल रहा है? धुंआ के चलते अब चूल्हा में खाना बनाना भी लगभग बंद हो चुका है? सरकार खुद मानती है चूल्हा में खाना बनाने से धुआं के कारण महिलाओं का स्वास्थ्य खराब होता है फिर रसोई गैस क्यों नहीं दिया जा रहा है? रसोई गैस की दुबारा रिफलिंग में 25 दिन और 45 दिन की समय सीमा समाप्त कर पूर्व की तरह 21 दिन किया जाये।

रसोई गैस की कालाबाजारी रोकने में सरकार

नकली पनीर सरकार की चुप्पी चुभने वाली है : वर्मा

रायपुर। कांग्रेस ने नकली पनीर पर सरकार के रवैये पर आक्रोश व्यक्त किया है। प्रदेश कांग्रेस के वरिष्ठ प्रवक्ता सुरेन्द्र वर्मा ने कहा कि सरकार की नाक के नीचे नागरिकों की मौत का सामान बिक रहा है। राजधानी सहित पूरे प्रदेश में पकड़ा रही नकली पनीर पकड़ाने पर प्रदेश के मुख्यमंत्री,

स्वास्थ्य मंत्री, खाद्य मंत्री की चुप्पी नागरिको को परेशान करने वाली है। यह सामान्य बात नहीं है कि राज्य की राजधानी में सरकार की नाक के नीचे सबसे लोकप्रिय खाद्य सामग्री बड़ी मात्रा में बनाया जा रहा और खपाया जा रहा, सरकार के जिम्मेदार मौन है। यह सरकार के खाद्य एवं औषधि विभाग की लापरवाही है कि लगातार प्रदेश में नकली पनीर खुलेआम बन रही है और बिक रही है। जानवरो की चर्बी और तेल तथा सोडे से पनीर बनाया जा रहा, सरकार क्या रही है? कांग्रेस पार्टी मांग करती है कि नकली पनीर के निर्माण और बिक्री पर रोकथाम के लिये सरकार विशेष दल का गठन करें और प्रदेश के किसी भी कोने में बन रही नकली खाद्य सामाग्री पर कड़ाई से रोक लगाई जाये।प्रदेश कांग्रेस के वरिष्ठ प्रवक्ता सुरेन्द्र वर्मा ने कहा कि ने कहा कि भाजपा के कुशासन में आम जनता की सेहत भगवान भरोसे है।

वेदांता पावर प्लाटः आप ने गठित की जांच समिति

रायपुर। आम आदमी पार्टी ने सक्ति जिले के सिंघीतराई में स्थित वेदान्ता पावर प्लांट में हुई भयानक दुर्घटना की कठोर निंदा की है आपको बता दे 14 अप्रैल 2026 के दोपहर को बायलर फटने से कई मजदूरों की जान गई और अनेक घायल हुए। यह हादसा, एक उच्च-दबाव वाली

स्टीम ट्यूब के फटने से हुआ, जो संभावित रूप से सुरक्षा मानकों की अनदेखी और मेंटेनेंस की कमी के कारण था।उत्तम जायसवाल ने कहा कि हम वेदांता समूह की सुरक्षा प्रोटोकॉल की कड़ी आलोचना करते हैं, जिनका दावा था कि वे उच्च मानकों का पालन करते हैं। लेकिन यह हादसा साफ तौर पर दर्शाता है कि सुरक्षा में बड़ी चूक हुई है। हम मांग करते हैं कि राज्य सरकार एक स्वतंत्र और गहन जांच करे, जिसमें यह देखा जाए कि आखिरी बार सुरक्षा अधिकारियों ने बॉयलर का निरीक्षण कब किया था, और क्या सभी मानक सही तरीके से फॉलो किए गए थे। उन्होंने कहा है कि वेदांता समूह के जिम्मेदार लोगो पर और सरकार में पदस्त औद्योगिक सुरक्षा अधिकारियों के ऊपर हत्या का केस दर्ज हो पूर्व में भी आर के एम पवार प्लांट में इसी तरह की घटना हुई थी जिसमे बहुत से मजदूर असमय काल के गाल में समा गए।

मुख्यमंत्री साय ने सुशासन तिहार 2026 के आयोजन को लेकर कलेक्टरों को लिखी चिट्ठी

1 मई से 10 जून तक लगेंगे ग्रामीण एवं शहरी इलाकों में लगेंगे शिविर

रायपुर। छत्तीसगढ़ शासन द्वारा आमजन की समस्याओं के त्वरित एवं प्रभावी निराकरण के उद्देश्य से इस वर्ष भी सुशासन तिहार 2026 के आयोजन व्यापक पैमाने पर किया जाएगा। इस संबंध में मुख्यमंत्री श्री विष्णु देव साय ने प्रदेश के सभी जिला कलेक्टरों को पत्र जारी कर इस अभियान सफल आयोजन को लेकर विस्तृत दिशा-निर्देश दिए हैं।

मुख्यमंत्री ने अपने पत्र में कहा है कि जन शिकायतों का समयबद्ध निराकरण सुशासन की आधारशिला है तथा आम नागरिकों को पारदर्शी, सरल एवं त्वरित सेवाएं उपलब्ध कराना राज्य शासन की सर्वोच्च प्राथमिकता है। गत वर्ष आयोजित सुशासन तिहार के सकारात्मक परिणामों को देखते हुए इस वर्ष इसे और अधिक व्यापक रूप में संचालित किया जाएगा।

30 अप्रैल तक निराकरण के निर्देश

मुख्यमंत्री ने कलेक्टरों को निर्देशित किया है कि 30 अप्रैल 2026 तक जिले में लंबित प्रकरणों के निराकरण हेतु विशेष अभियान चलाया जाए। इसके अंतर्गत भूमि संबंधी प्रकरण जैसे नामांतरण, बंटवारा, सीमांकन, मनरेगा अंतर्गत लंबित मजदूरी भुगतान, हितग्राहीमूलक योजनाओं के लंबित भुगतान, आय-जाति-निवास प्रमाण पत्र, बिजली एवं

ट्रांसफार्मर संबंधी समस्याएं तथा हैंडपंप सुधार जैसे मुद्दों का प्राथमिकता से समाधान सुनिश्चित किया जाए। साथ ही पात्र हितग्राहियों को उज्ज्वला योजना, राशन कार्ड, आयुष्मान भारत एवं सामाजिक सुरक्षा पेंशन जैसी योजनाओं का लाभ दिलाने पर विशेष ध्यान देने के निर्देश दिए गए हैं।

सुशासन तिहार के अंतर्गत 01 मई से 10 जून 2026 तक प्रदेशभर में जन समस्या निवारण शिविरों का आयोजन किया जाएगा। ग्रामीण क्षेत्रों में 15 से 20 ग्राम पंचायतों के समूह तथा शहरी क्षेत्रों में वार्ड क्लस्टर के आधार पर शिविर आयोजित होंगे। इन शिविरों में शासन की विभिन्न योजनाओं के संबंध में व्यापक जन-जागरूकता अभियान चलाया जाएगा तथा पात्र हितग्राहियों को मौके पर ही लाभ वितरण किया जाएगा। शिविरों में प्राप्त आवेदनों का अधिकतम एक माह के भीतर निराकरण सुनिश्चित करने तथा प्रत्येक आवेदक को उसके आवेदन की स्थिति की जानकारी देने के निर्देश भी दिए गए हैं। मुख्यमंत्री ने निर्देश दिए हैं कि अभियान के दौरान मंत्रीगण, सांसद एवं विधायकगण, मुख्य सचिव एवं प्रभारी सचिव समय-समय पर शिविरों में शामिल होकर व्यवस्थाओं का निरीक्षण करेंगे और आमजन से संवाद स्थापित करेंगे। अभियान के दौरान मुख्यमंत्री श्री साय स्वयं विभिन्न जिलों में पहुंचकर विकास कार्यों और योजनाओं के क्रियान्वयन का औचक निरीक्षण करेंगे। तथा हितग्राहियों से फीडबैक लेंगे। इसके साथ ही जिला मुख्यालयों पर अधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक आयोजित कर समाधान शिविरों में प्राप्त आवेदनों के निराकरण की स्थिति एवं योजनाओं की प्रगति की समीक्षा की जाएगी।

गुमास्ता में उम्रभर छूट, क्लीनिक लाइसेंस पर डबल मार, 20 हजार जुर्माना, 3600 वेस्ट चार्ज

रायपुर। आयुष चिकित्सकों ने क्लीनिक लाइसेंसिंग की जटिल प्रक्रिया, भारी जुर्माना और नए भवन नियमों को लेकर बड़ा सवाल खड़ा किया है. 30-35 साल पुराने किराये के भवनों में चल रहे क्लीनिकों से अब अनुमोदित नक्शा, ले-आउट और भवन अनुज्ञा मांगी जा रही है, जिसे डॉक्टर अव्यावहारिक बता रहे हैं. नागपुर नगर निगम के सिंगल डॉक्टर क्लीनिक की 3 साल में 6000 फीस और बायो-मेडिकल वेस्ट के 3600 शुल्क का उदाहरण देते हुए डॉक्टरों ने छत्तीसगढ़ में भी एकमुश्त और डबल लाइसेंसीकरण मुक्त व्यवस्था लागू करने की मांग तेज कर दी है.आयुष चिकित्सकों का

कहना है कि उन्होंने समय-समय पर पंजीयन और अनुज्ञा के लिए आवेदन किया, लेकिन फायर सेफ्टी, अनुज्ञप्ति, किरायानामा और अन्य तकनीकी कारणों से कई फाइलें लंबित रहीं. इसी देरी के चलते विभाग ने बिना अनुज्ञा संचालन का हवाला देकर 20,000 का जुर्माना लगा दिया. डॉक्टरों का आरोप है कि यह स्थिति उनकी लापरवाही नहीं बल्कि जटिल प्रक्रिया और विभागीय विलंब का परिणाम है.रायपुर के कई क्लीनिक नजूल भूमि पर बने किराये के भवनों में 30-35 वर्षों से संचालित हैं. अब 2026 के नए नियमों के तहत उनसे अनुमोदित नक्शा, ले-आउट प्लान और भवन निर्माण अनुज्ञा मांगी जा रही है।

आर.एन.आई.रजि. क्र. CHHHIN/2021/80529, स्वत्वाधिकारी, मुद्रक एवं प्रकाशक- शशांक शर्मा द्वारा मिशन मीडिया प्रा. लि., प्रेस कॉम्प्लेक्स, रजबंधा मैदान, रायपुर (छ.ग.) 492001 से मुद्रित एवं 29/1110, सेवती स्मृति, आजाद चौक, रायपुर (छ.ग.) 492001 से प्रकाशित। संपादक-शशांक शर्मा, मो. 94255-20531.